हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक मंगलवार, दिनांक 14 मार्च, 2017 को माननीय उपाध्यक्ष, श्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाहन आरम्भ हुई।

प्रश्नकाल आरम्भ

तारांकित प्रश्न

14/03/2017/1100/RKS/DC/1

स्थगित प्रश्न संख्याः3627

श्री रिखी राम कौंडलः उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रश्न की सूचना माननीय मुख्य मंत्री जी ने सभा पटल पर रखी है, उसमें केवल 852 किसानों के ऋण की ब्याज माफ की गई है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो आपका 'चुनाव घोषणा पत्र' था उसमें यह सीधा लिखा था कि किसानों के ऋण माफ किए जाएंगे। उसमें यह क्लासिफिकेशन नहीं थी कि किसानों के ब्याज को माफ किया जाएगा। क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे?

Chief Minister: Mr. Deputy Speaker Sir, no loan has been waived by the Cooperatives Banks. However, interest has been waived under One Time Settlement scheme of the bank. The H.P. State Cooperative Agriculture and Rural Development Bank has waived interest on interest in 598 cases amounting to Rs. 1,4393629 crores. The Kanga Primary Cooperative Agriculture and Rural Development Bank has waived Rs. 20,51,999 in 231 cases. The Jogindra Central Cooperative Bank has waived Rs. 9559 in one case. The HP State Cooperative Bank has waived Rs. 6,67,691 in 22 cases. Thus, these four banks have waived interest amounting to Rs. 1,71,22,878 in 852 cases.

श्री महेन्द्र सिंहः आदरणीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने ज़िला ऊना में एक बहुत बड़ी स्टेटमैंट दी थी कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जितने भी ट्रैक्टर्ज़ किसानों ने लिए हैं, उनके जितने भी कर्ज़े हैं, वे सारे-के-सारे माफ कर दिए जाएंगे। यह ट्रैक्टर कृषि विभाग से संबंधित हैं और किसान इन ट्रैक्टरों का इस्तेमाल केवल मात्र अपनी खेतीबाड़ी के लिए करते हैं। इन ट्रैक्टरों से खेतों को जोता जाता है और फसल की बिजाई की जाती है। जैसा आपने कहा था और यह बात अखबारों में भी छपी है कि हम इन सभी ट्रैक्टरों के जितने भी ऋण बाकी बचे हैं, उन सबको माफ कर देंगे।

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

14.03.2017/1105/SLS-DC-1

प्रश्न संख्याः 3627 ...क्रमागत

श्री महेन्द्र सिंह...जारी

दूसरे, मैं माननीय मुख्य मंत्री से यह भी जानना चाहता हूं कि जो सूचना सभा पटल पर रखी है, इस सूचना में बहुत से ऐसे किसान रह गए हैं जिनकी ब्याज माफ़ी की सूचना आपने नहीं दी है। इसलिए जो शेष किसान हैं, जिनकी ब्याज माफ़ी अभी तक बैंकों ने नहीं की है, क्या आप उनके ब्याज को भी माफ़ करेंगे या नहीं करेंगे?

मुख्य मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने कहा है, ऐसे मैंने कोई घोषणा नहीं की है। ट्रैक्टर वालों की यह मांग रजिस्ट्रेशन को लेकर थी कि जो ट्रैक्टर्ज़ एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है वह वन टाइम की जाए। यह उनकी मांग थी। यह नहीं कि जो बैंक से कर्ज़ा लिया है उसको वेव ऑफ किया जाए। और उनकी जो यह मांग है, it is under consideration of the Government.

श्री रिखी राम कौंडल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, विभिन्न बैंकों की जो ब्याज दर थी, उसके बारे में 852 किसानों का उत्तर तो आ गया है। मैंने तो बैंकों की डिटेल मांगी ही नहीं थी। मैंने तो केवल मात्र यह कहा था कि जब आपने चुनाव लड़ा, आपने घोषणा-पत्र में सीधा लिखा था कि हम किसानों के ऋण माफ़ करेंगे। उन किसानों ने इसी वजह से ही आपको समर्थन दिया थ। आप कह रहे हैं कि हमारे घोषणा-पत्र की सारी बातें पूरी हो चुकी हैं। मेरा प्रश्न यह था क्या आप उन किसानों के ऋण भी माफ़ करेंगे?

मुख्य मंत्री : हमारे चुनावी घोषणा-पत्र में ऐसा कोई ज़िक्र नहीं था।

प्रश्न समाप्त

14.03.2017/1105/SLS-DC-2

प्रश्न संख्याः 3451

श्री नरेन्द्र ठाकुरः उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है उसके मुताबिक doubtful integrity के कुल 63 ऑफिसर्ज़ हैं। उनमें से 27 ऑफिसर्ज़ अभी भी सैंसटिव पदों पर नियुक्त किए गए हैं। As per the decision of the High Court in case Sher Singh Vs State of H.P., सरकार को क्लीयर कट डायरैक्टशन है कि "those Officials who are having doubtful integrity, उनको सेंसटिव पदों पर न रखा जाए"। इन्होंने डिटेल में सूची दी है लेकिन जो रीज़न इन्होंने बताया है कि इन 27 अधिकारियों को क्यों सैंसटिव पदों पर रखा गया है, वह तथ्यों पर आधारित नहीं है। सूचना के सीरियल नंबर 9 पर जो इलैक्ट्रिसिटी एंड पॉवर बोर्ड है, इसमें जितने भी अधिकारियों की लिस्ट इन्होंने दी है, वह एक से लेकर 14 तक सारे-के-सारे सैंसटिव पदों पर रखे गए हैं। इन्होंने रीज़न दिया है कि "non availability of non sensitive post".

उपाध्यक्ष जी, मेरा कहना यह है कि यह रीज़न तथ्यों पर आधारित नहीं है। हैड ऑफिस में यहां पर बहुत से ऐसे पद हैं जो नॉन सैंसटिव पद हैं। फिर जहां चीफ इंजीनियर का पद होता हैं वहां पर साथ में एस.ई. वर्क्स का पद भी होता है। जो एस.ई. ऑप्रेशन में अप्वायंट होता है, वहां एक्स.ई.एन. वर्क्स का पद भी होता है। यह सारे पद नॉन-सैंसटिव हैं। लिस्ट में इन्होंने जो पद सीरियल वाइज बताए हैं, उन लोगों को इन पदों पर आसानी से अप्वायंट किया जा सकता है।

जारी ..श्री गर्ग जी

14/03/2017/1110/RG/AG/1

प्रश्न सं. 3451---क्रमागत

श्री नरेन्द्र ठाकुर---क्रमागत

लेकिन even as per the direction of the High Court जो ऑफिशियल्ज financial irregularity में शामिल हैं उनके खिलाफ चार्जशीट हुई है, इसके बावजूद भी हाई कोर्ट के ऑर्डर की वॉयोलेशन हो रही है और इनको अभी तक भी सेन्सटिव पोस्ट्ज पर रखा गया है!

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि as per the decision of the High Court इनको, जो पद नॉन-सैन्सटिव हैं जैसा मैंने बताया है, ये तथ्यों पर आधारित है, इनको जल्दी-से-जल्दी उन जगहों पर लगाया जाए जो नॉन-सैन्सटिव पोस्ट्ज हैं। तो क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह आश्वासन आज यहां देंगे?

Chief Minister: Sir, as per the list provided by the Government, 63 officers, in all, who have been placed on the list of officers are not considered to be corrupt, but against whom some charges have been levelled. So far Government is concerned the department has kept only some of them in sensitive posts because of their utility and seniority and whom department thinks is essential for the work assigned to him. **But I would like to say that the Government will again look into it.**

Concluded

14/03/2017/1110/RG/AG/2

प्रश्न सं. 3793

श्री खूब राम : उपाध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी है उसके मुताबिक पशु औषधियोजक के 33 स्वीकृत पदों में से 26 भरे हुए हैं और 7 पद रिक्त हैं, ग्राम पंचायत पशु सहायक के 24 स्वीकृत पदों में से 20 पद भरे हुए हैं और 4 रिक्त हैं और पशु पालन परिचारक के 33 स्वीकृत पदों में से 30 पद भरे हुए हैं और 3 पद रिक्त हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, ऑऊटर सिराज आनी चुनाव क्षेत्र में है, सबसे ज्यादा 35% दूध का यहां उत्पादन होता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ये रिक्त कब तक भरे जाएंगे? दूसरा, प्रश्न के 'ग' भाग के उत्तर में कहा गया है कि 'वर्तमान में 25 नियमित पशु औषधालय निजी भवनों में चल रहे हैं।' तो ये जो औषधालय निजी भवनों में चल रहे हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी इन निजी भवनों के लिए धन उपलब्ध करवाएंगे?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि इनके चुनाव क्षेत्र में पशु औषधियोजक के 7 पद रिक्त हैं, तो मैं इनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है। क्योंकि इनके चुनाव क्षेत्र में 7 पद रिक्त हैं और जिला कुल्लू में पशु औषधियोजक के 19 पद रिक्त हैं तथा पूरे प्रदेश में 219 पद रिक्त हैं। इसी प्रकार ग्राम पंचायत पशु सहायक के 4 पद इनके चुनाव क्षेत्र में और 4 पद ही जिला कुल्लू में खाली हैं और लगभग 255 पद पूरे प्रदेश में रिक्त हैं। इसी प्रकार पशु पालन परिचारक के 3 पद इनके चुनाव क्षेत्र में रिक्त हैं और जिला कुल्लू में लगभग 24 पद रिक्त हैं तथा पूरे प्रदेश में 585 पद रिक्त पड़े हुए हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि प्रदेश में पदों को भरने की प्रक्रिया निरन्तर चल रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमने रिक्त पदों को भरने के लिए जो प्रक्रिया शुरू की है

एम.एस. द्वारा प्रश्न जारी

14/03/2017/1115/MS/AG/1

प्रश्न संख्याः 3793 क्रमागत----ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जारी---

उसमें से 132 वैटरीनरी फार्मासिस्ट्स के पदों को भरने के हमने आदेश कर दिए हैं और उनको जल्दी से भरा जाएगा। 95 पदों को कमीशन के थ्रू भरने के लिए प्रक्रिया जारी है। इसी तरह से 200 और पदों का मुख्य मंत्री जी ने बजट के अंदर प्रावधान कर दिया है। जो ग्राम पंचायत पशु सहायक हैं इनके भी 255 पद हमारे खाली हैं उसमें 150 पद हमारे इसी 215 और 217 के बैच के अंदर हम भरने जा रहे हैं इसलिए इनको भरने की प्रक्रिया हम जल्दी-से-जल्दी करेंगे और आपके चुनाव क्षेत्र का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा, जो वर्तमान में 25 नियमित पशु औषधालय निजी भवनों में होने की बात कही है उसमें 23 ऐसे पशु औषधालय आपके चुनाव क्षेत्र के अंदर हैं जहां जमीन उपलब्ध नहीं है। मात्र दो ही पशु औषधालय हैं जिनमें फण्ड्ज देने की प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है, उनको हम फण्ड्ज देंगे। बाकी 23 में आप हमें वहां जमीन दिलवाएं तो उनके लिए भी धन उपलब्ध करवाएंगे।

श्री गोविन्द सिंह ठाकुरः उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि जहां पर भूमि उपलब्ध होगी वहां पर हम भवन बनाने के लिए धनराशि देंगे। मनाली विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत शिरड़ और पशु पालन डिस्पेंसरी जो मुख्य मंत्री आरोग्य धन के अंतर्गत बड़ी शिल्लह में है वहां पर फतेह चन्द नाम के एक व्यक्ति ने चार साल पहले भूमि दान दी है और भूमि पशु पालन विभाग के नाम पर है। क्या वहां पर मंत्री जी भवन निर्माण के लिए धनराशि जारी करेंगे क्योंकि वहां पर विभाग के नाम पर भूमि भी है?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः उपाध्यक्ष जी, जैसे कि माननीय सदस्य ने कहा है कि जमीन उपलब्ध करवा दी गई है तो इसका जरूर ध्यान रखेंगे।

14/03/2017/1115/MS/AG/2

श्री महेश्वर सिंहः उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या आपके संज्ञान में यह बात है कि जब विभाग धन का आबंटन करता है तो आमतौर पर देखा गया है कि विभाग यह नहीं देखता है कि भूमि उपलब्ध है या नहीं। फलस्वरूप जहां भूमि नहीं है वहां कुल्लू जिला में कई जगह पैसा उपलब्ध है और जहां भूमि है वहां पैसा उपलब्ध नहीं है। तो क्या मंत्री महोदय ऐसे निर्देश देंगे कि भविष्य में यह पैसा उसी जगह के लिए दिया जाए जहां भूमि उपलब्ध है? नहीं तो व्यर्थ में वह पैसा पड़ा रहता है। इसलिए जहां

ऐसी स्थिति है क्या उस पैसे को डाइवर्ट करके उसी जिला में जहां भूमि है, वहां उसी काम के लिए राशि दी जाएगी?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः उपाध्यक्ष जी, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, विभाग की कोशिश तो यही रहती है कि जहां भूमि उपलब्ध हो वहीं पर पैसा दिया जाए। यदि माननीय सदस्य के ध्यान में कोई ऐसा मामला है जहां जमीन उपलब्ध नहीं है और पैसा दिया गया है तो उसकी सूचना यदि ये हमें देंगे तो जरूर उस पैसे को बदलकर उसी क्षेत्र में अन्य कहीं देने का प्रयास करेंगे।

श्री रविन्द्र सिंहः उपाध्यक्ष जी, महेश्वर सिंह जी ने जो प्रश्न पूछा है इसी को मैं भी पूछना चाहता था। दूसरा, आप प्लानिंग की मीटिंग में जो विधायकों से प्राथमिकताएं लेते हैं उसमें विभिन्न विधायकों ने स्वास्थ्य एवं अन्य भवनों को छोड़कर जो इस बार भी पूछा है और लगातार दो-तीन सालों से पूछ रहे हैं कि अन्य विभागों के भवन यदि कोई बनाना चाहते हैं, तो जिन विधायकों ने आपके इस विभाग से संबंधित प्राथमिकताएं उसमें डाली हैं क्या उनको प्राथमिकता के तौर पर जहां भूमि भी उपलब्ध है यानी वहां की पंचायत और स्थानीय लोगों ने उसकी रजिस्ट्री तक करवा दी है, उन पर प्राथमिकता से आप वहां भवन बनाने का आदेश करेंगे?

14/03/2017/1115/MS/AG/3

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः उपाध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है यह धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है। -(व्यवधान)-मैं प्राथमिकता ही कह रहा हूं। जितने फण्ड्ज हमारे पास उपलब्ध होंगे उसमें जो प्राथमिकता के ऊपर दिए होंगे, उन पर खास ध्यान दिया जाएगा।

प्रश्न समाप्त/

अगला प्रश्न श्री जे0एस0 द्वारा----

14.3.2017/1120/जेके/एएस/1

प्रश्न संख्याः 3794

श्री पवन काजलः माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि हमारा जो कांगड़ा पी0डब्ल्यू0डी0 का डिविजन है इसमें पहले से ही शाहपुर चुनाव क्षेत्र, कांगड़ा चुनाव क्षेत्र और 5 परसेंट धर्मशाला चुनाव क्षेत्र और 10 परसेंट नगरोटा चुनाव क्षेत्र है। तो अब ये जो डिविजन है, यह वैसे चार चुनाव क्षेत्रों को फीड करता है। एक अभी-अभी जो पी0डब्ल्यू0डी0 डिविजन टांडा में बना। उसके लिए जो बड़ोह में सब डिविजन बना, जो 10 परसेंट नगरोटा चुनाव क्षेत्र का था उसकी जब ये जस्टिफिकेशन बनी तो यह 10 परसेंट बाग पी0डब्ल्यू0डी0 सब डिविजन बड़ोह में आता था। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह कहना चाह रहा हूं कि पी0डब्ल्यू0डी0 के कांगड़ा डिविजन पर पहले ही काफी भार है। डिविजन भी आपने बना दिया है, सब डिविजन भी बना दिया तो जो 10 परसेंट एरिया नगरोटा विधान सभा क्षेत्र का है, इसको क्या आप डिविजन टांडा और सब डिविजन बड़ोह में करेंगे? जब यह खोला था तो इसकी जस्टिफिकेशन इसी के आधार पर बनी थी।

Chief Minister: Hon'ble Deputy Speaker, Sir, the P.W.D. division at Dr. Rajinder Prasad Medical College, Tanda, Distt. Kangra has been established by the Government under Nagrota-Bagwan Vidhan Sabha Constituency. I may say that this division has primarily been opened to look after the Dr. Rajinder Prasad Medical College, Tanda. A Lot of construction work is going on there and Government thought it fit, just like in IGMC, Shimla, at initial stages, when construction work is coming up; residential quarters are coming up; hostels are coming up; other buildings are coming up, It is should be under the direct supervision of an Executive Engineer. This is the main purpose. May be I am not aware if any other part of the Nagrota Bagwan has been also attached to

this Division. Therefore, there is no justification, at present, to exceed to the demand of the Hon'ble Member.

14.3.2017/1120/जेके/एएस/2

श्री पवन काजलः उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जो प्रश्न था इसमें डिविजन का नहीं था। मेरा प्रश्न यह था कि जो सब डिविजन हमारा कांगड़ा है इसमें 10 परसेंट जो बाग है वहां बड़ोह में आपने सब डिविजन खोला उसमें टांडा मेडिकल कॉलेज का कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन ये जो फीडिंग एरिया है इसका विभाग के द्वारा लैटर भी गया था कि इसको टेक ऑफ करिए परन्तु उसके बाद भी टेक ऑफ नहीं हुआ था। इसलिए मैं यह चाहता था कि जब यह सब डिविजन खुला था तो इसकी जस्टिफिकेशन भी थी तो उसमें कोई हर्ज़ नहीं है कि अगर 10 परसेंट का बाग नगरोटा में चला जाए और वैसे भी कांगड़ा चुनाव क्षेत्र डिविजन पी0डब्ल्यू0डी0 का जो पड़ता है, वह चार विधान सभा चुनाव क्षेत्रों को पहले ही फीड करता था तो ये जो 5 परसेंट एरिया था वह धर्मशाला वाला था लेकिन धर्मशाला वालों ने अपना ले लिया तो ऐसे ही उसी आधार पर 10 परसेंट दे दें।

Chief Minister: Hon'ble Deputy Speaker, Sir, the Government will look into the matter.

Deputy Speaker: Is your Question pertains to Distt. Kangra? जय राम ठाकुर जी आप कांगड़ा के बारे में बोलेंगे?

श्री जय राम ठाकुरः उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बारे में कुछ नीतिगत बात करनी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या डिविज़न खोलने के लिए कोई मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं? मैं देख रहा हूं पिछले कुछ समय से बड़े स्तर पर संस्थान खोलने की प्रक्रिया चल रही है और चुनाव के दिनों में यह प्रक्रिया ज्यादा तेज गति से चलती है। एक तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इसके लिए कोई नियम है? अगर कोई नियम है तो उनका क्या कोई पालन हो रहा है? और उसके बाद जो इस

तरह के पी0डब्ल्यू0डी0 के डिविजन है या दूसरे विभागों के डिविजन है, एक डिविजन के अन्तर्गत 2-2, 3-3 चुनाव क्षेत्र भी आते हैं, पाट्र्स आते हैं। क्या मुख्य मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि हर विधान सभा क्षेत्र में रेशनलाईज करके हरेक विधान सभा क्षेत्र के लिए अपना एक डिविजन हो, पी0डब्ल्यू0डी0 का अपना हो, आई0पी0एच0 का अपना हो,

14.3.2017/1120/जेके/एएस/3

इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड का अपना हो ताकि जो चुने हुए विधायक होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं उनको मॉनिटर करने के लिए उस दृष्टि से सुविधा हो?

Chief Minister: Hon'ble Deputy Speaker, Sir, It is not feasible that we will open a separate division of PWD, a separate division of IPH, a separate division of Electricity in each and every constituency of the State. That is not feasible. But wherever it is required, because of distance, area, etc. the Government will consider it.

श्री एस0एस0 द्वारा जारी---

14.03.2017/1125/SS-AS/1

प्रश्न संख्याः 3795

श्री बिक्रम सिंह जरयालः उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि विधान सभा क्षेत्र में एकमात्र आई0टी0आई0 गरनोटा है जो वर्ष 2000 में बनी थी जब धूमल साहब मुख्य मंत्री थे और उसी टाइम से तीन ट्रेड चले हुए हैं जो अब तक पूरे नहीं हैं। एक साल वहां ट्रेनिंग लेते हैं और एक साल उनको दूसरी आई0टी0आई0 में ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। वहां पर 24 बीघे जमीन आई0टी0आई0 के नाम पर है। काफी खुला क्षेत्र है। गरीबों के बच्चे ही आई0टी0आई0 में पढ़ते हैं। अमीरों के बच्चे तो बड़े-बड़े संस्थान में जायेंगे या

फॉरेन में पढ़ेंगे। तो मैं माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि क्या आने वाले वर्ष में यहां पर आप नये ट्रेड बढ़ायेंगे और भवन के लिए बजट देंगे?

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः माननीय उपाध्यक्ष जी, the Government ITI, Garnota was identified on 6.8.2007, with 3 trades i.e. Electrician, Plumber and Dress Making. All these 3 trades are affiliated with NCVT with a total intake capacity of 89 और इनकी अपनी बिल्डिंग है। वहां पर बिल्डिंग है और जमीन ज्यादा है तो स्टेट ऑफ आर्ट आई0टी0आई जो माननीय मुख्य मंत्री जी की 2016-17 के बजट में घोषणा है उसमें इसको लिया गया है और उसकी क्लासिज़ चम्बा में चल रही हैं। तो हम फाइनैंस डिपार्टमैंट के साथ मैटर टेक अप कर रहे हैं जैसे हमारे पास पैसे उपलब्ध होंगे बिल्डिंग बनाकर उसको आपके वहां शिफ्ट करेंगे। स्टेट ऑफ आर्ट का एक और आपको ट्रेड साथ में मिलेगा।

14.03.2017/1125/SS-AS/2

प्रश्न संख्याः 3796

श्री राम कुमारः उपाध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न तीन सड़कों के बारे में था। इसमें ये सड़कें पटटा-जोहडजी-ढकरियाणा का काम लगभग 15 वर्षों से चला हुआ है। यह हमारी तीसरी बार सरकार बन गई है लेकिन यह काम पूरा नहीं हुआ। इसको विभाग ने तीन भागों में बांट कर बताया है कि दो भागों में उन्होंने बस पास कर दी है। मेरा सप्लीमैंटरी माननीय मुख्य मंत्री जी से यह है कि जिन एरियाज़ में पांच-पांच किलोमीटर के पोरशन्ज हैं और विभाग ने बस पास कर दी है क्या उन्हें इसी मंथ चलाने के निर्देश देंगे?

दूसरा, जो केवल 10 मीटर जगह बची हुई है उसको मुकम्मल करने के लिए मैं चाहता हूं कि टाइम बाऊंड करके कम्प्लीट करवाया जाए। इसमें इन्होंने कहा है कि गिफ्ट डीड लेने के प्रयास किये जा रहे हैं। मुख्य मंत्री महोदय, सड़क लगभग तैयार है, रोड थ्रू है। सिर्फ

एक-दो जगह पत्थर तोड़कर पोरशन को कवर करना है, कोई 10-15 मीटर जगह है जिसको बनाना बाकी है। मैं चाहूंगा कि जो पोरशन पास हुए हैं उनमें बस सुविधा शीघ्र उपलब्ध करवाई जाए। जो कम्प्लीट नहीं हैं उन्हें टाइम बाऊंड मैनर में पूरा करके सड़क को थ्रू करने के निर्देश विभाग को देने की कृपा करें।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो यह प्रश्न है यह सात सड़कों के बारे में है और सभी सड़कों की जो वस्तुस्थिति है, वह हमने विस्तार से प्रश्न के उत्तर में दी है तथा ये सड़कें जो हैं सब पर काम हुआ है

जारी श्रीमती के0एस0

14.03.2017/ 1130/केएस/डीसी/1

प्रश्न संख्याः3796 जारी----

माननीय मुख्य मंत्री जारी----

कहीं एक किलोमीटर , कहीं दो किलोमीटर, कहीं कुछ मीटर की वजह से ये सड़कें रुकी हुई हैं। ये इसलिए रूकी हैं क्योंकि उस भूमि के लिए लोगों ने अपनी स्वीकृति नहीं दी है। जो एफिडेविट दिया जाता है, वह नहीं दिया है। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करुंगा कि जो सड़कें भूमि न मिलने के कारण, किसानों ने जिस भूमि के लिए अपनी स्वीकृति नहीं दी है उसके कारण काम रुका है। अगर ये उसमें हस्तक्षेप करेंगें तो वह भूमि लोक निर्माण विभाग के नाम हस्तांतरित होगी और तुरन्त इन सड़कों को पूरा किया जाएगा।

दूसरा इनका यह सुझाव है कि जो सड़कें जितनी बनी हैं, कम से कम उस हिस्से के अंदर बसें चलाई जाएं। उसके बारे में मैं परिवहन विभाग को कहूंगा कि वे उसका निरीक्षण करें और जहां तक बस जा सकती है, वहां तक बसों को चलाया जाए।

श्री राम कुमारः उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बड़े विस्तार से उत्तर दिया है लेकिन मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि ये सड़कें, जो विभाग ने भूमि मालिकों से

गिफ्ट डीड लेने की बात की है, मैं कहना चाहूंगा कि ये सड़कें थ्रू हो गई हैं। जो एक 900 मीटर सड़क बननी थी, वह भी विभाग ने कम्पलीट कर दी है। इसके टैंडर्ज़ लगे हुए हैं। पी.एम.जी.एस.वाई. में ये सड़कें हैं। जब तक उनकी तरफ से सड़क की क्लीयरैंस नहीं होगी, वह टैंडर नहीं होंगें। ये सड़कें थ्रू हैं, वहां किसी किस्म की दिक्कत नहीं है। मैं चाहूंगा कि इसको टाईम बाऊंड करने की कृपा करें।

मुख्य मंत्रीः उपाध्यक्ष महोदय, जैसे मैं पहले कह चुका हूं, लोक निर्माण विभाग की सुस्ती या गफ़लत की वजह से यह कार्य नहीं रुका है बल्कि इन सड़कों के कुछ हिस्से में लोगों ने विभाग को अपने पट्टे दिए हैं, सहमति दी है कि वे अपनी भूमि को लोक निर्माण विभाग को देंगें, उसके नाम हस्तांतरित करेंगें । वहीं भाग रुके हैं । अगर ये अपनी गुडविल का वहां पर इस्तेमाल करें, लोगों से बातचीत करें और

14.03.2017/ 1130/केएस/डीसी/2

जहां-जहां किसानों ने सड़क बनाने के लिए भूमि नहीं दी है, उनसे उस भूमि को दिलवाएं तो वहां पर तुरन्त काम होगा। वह बहुत बड़ा काम नहीं है। कहीं एक किलोमीटर का फर्क है, कहीं दो किलोमीटर का फर्क है और कहीं कुछ मीटर का ही फर्क है। बाकी सड़कें बनी हुई हैं।

श्री राम कुमारः सर, सड़क थ्रू हो चुकी है। सिर्फ पास करना बाकी है।

मुख्य मंत्रीः अगर वह सड़क बन चुकी है तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट उसको पास करें और वहां पर बसों को चलाया जाए।

14.03.2017/ 1130/केएस/डीसी/3

प्रश्न संख्या 3797

श्री राकेश कालियाः उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस आई.टी.आई. में कितने विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और यहां पर कौन-कौन से ट्रेड चल रहे हैं?

खाद्य आपूर्ति, एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः उपाध्यक्ष महोदय, मैकेनिक मोटर व्हीकल व इलैक्ट्रिशियन के दो ट्रेड वहां पर चल रहे हैं। इसकी इनटेक 84 बच्चों को लेने की है।

श्री राकेश कालियाः उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस आई.टी.आई. के बारे में आपके विभाग का फ्यूचर प्लान क्या है?

खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः माननीय उपाध्यक्ष जी, फ्यूचर प्लान इसका यह है कि इसमें 11 के.वी. की एच.टी. लाईन की शिफ्टिंग का कार्य जो था उसके लिए हमने 3 लाख 31 हजार रुपये इलैक्ट्रिकल डिपार्टमैंट को दे दिए हैं।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी.....

14.3.2017/1135/av/dc/1

प्रश्न संख्या : 3797 --------- क्रमागत

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री : ---जारी

और चीफ आर्किटैक्ट को इसका नक्शा जल्दी-से-जल्दी बनाने को कहा है। इस बारे में कई बार कम्युनिकेशन हो चुकी है लेकिन अब मैं इसको पर्सनल लैवल पर बात करके पुश करूंगा ताकि उनका नक्शा समय पर आ जाए। आपकी जो मन्शा है कि इसका भवन समय पर बन जाए तो इसके भवन को भी जल्दी-से-जल्दी तैयार करने की कोशिश करेंगे। वहां पर 84 में से 84 बच्चे ही ऐनरोल है।

14.3.2017/1135/av/dc/2

प्रश्न संख्या : 3798

Chief Minister : Sir, I would like to state, in addition to the information supplied by me in answer to this question I would like to add to make the things more clear that in addition to 61 number " In principle " declared State Roads as the National Highways, following 4 number State Roads have been approved for " In principle "deceleration. Three of these roads are being taken up by National Highways and Infrastructure Development Corporation Government of India (NHIDC) under Bharat Mala programme.

1. Hathithana (NH-21)- Manikaran- Pilga.

2. Taklech-Sarahan-Jeori

3. Chandigarh-Karoran-Thana-Prempura-Garian-Paploha-Bar-Shilukurd-Jangesh-Kasauli-Dharampur on NH-5

4. Naina Devi - Swarghat.

Further, in addition to four laning of Parwanoo - Shimla and Kiratpur Manali, following 3 roads have also been notified for four laning by Ministry of Road Transport and Highways Government of India. These roads have been entrusted to National Highway Authority of India for execution.

1. Chakki to Mandi (NH-20) having length of 196 kms.
2. Shimla to Mataur (NH- 88) having length of 224 kms.
3. Baddi to Nalagarh (NH-21-A) having length of 18 kms.

The land Acquisition process for Baddi to Nalagarh has already been started by State Government. I thought I will give this additional information also along with the reply.

14.3.2017/1135/av/dc/3

श्री रविन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो सूचना इस प्रश्न के उत्तर में यहां पर उपलब्ध करवाई है इसमें एक तो 6 महीने का समय बीत गया है क्योंकि दिनांक 14.9.2016 को भारत सरकार से 61 सड़कों की सैद्धान्तिक मंजूरी प्राप्त हो गई थी।

श्री वर्मा द्वारा जारी

14/03/2017/1140/टी0सी0वी0/ए0जी0/1
प्रश्न संख्याः 3798..... क्रमागत

श्री रविन्द्र सिंह ....जारी...

लेकिन छः महीने गुजरने के पश्चात् भी अभी तक यह सारे-का -सारा काम अधर में लटका हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि सलाहकार नियुक्त करने की प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाएगी?

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, यहां मुख्य मंत्री महोदय ने प्रश्न के 'ग' भाग के जवाब में कहा है कि केन्द्र सरकार से डी0पी0आर0 बनाने के लिए इन-प्रिसिंपल tentative approval for Rs. 229.69 crores स्वीकृति आई है। इसमें सही कौन-सी हैं, जो अब जवाब दिया है, वह सही है या फिर माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो बजट भाषण दिया है, वह सही है? इसमें पृष्ठ न0 40, पैरा न0 98 में इन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से निजी आवंटन का मामला उठाया है और लगभग 300 करोड़ रूपये व्यय इसके लिए चिन्हित कर दिए हैं। इसमें सही कौन-सा है?

तीसरा, उपाध्यक्ष महोदय, जो नेशनल हाईवेज़ इन्फ्रास्ट्रैक्चर डेवैल्पमेंट कारपोरेशन लि0 के गठन करने का प्रस्ताव है, क्या इसका गठन हो चुका है, जो भारत सरकार ने बनाना है, क्योंकि इसके अंतर्गत आपने 4 छोटी-छोटी सड़कें डाल दी हैं। क्या यह कारपोरेशन छोटी-छोटी सड़कों का ही निर्माण करेगा या बड़ी सड़कों के निर्माण का कार्य भी करेंगा? इसमें आपने 4 छोटी सड़कों को दर्शाया है और आपने कहा कि इनकी नई सूचना हमारे पास आई हैं। ये एक 43, 77, 50 और एक 30 किलोमीटर की हैं। बाकी 250-300 किलोमीटर वाली जो सड़कें हैं, इसमें उनको जाना चाहिए था, लेकिन इसमें आपने ये छोटी-छोटी सड़कें डाली हैं। कृपया इन तीनों अनुपूरक प्रश्नों पर प्रकाश डालने की कृपा करें।

मुख्य मंत्रीः उपाध्यक्ष महोदय, ये सारा मामला बड़ा कोम्प्लीकेटिड है। इसको कई स्टे्जिज़ से गुज़रना पड़ता है यानि इन-प्रिंसिपल सैंक्शन के बाद इसको कई स्टे्जिज़ से गुजरना पड़ता है, तब जाकर ही फाईनल अप्रूवल/पैसा आता है और

14/03/2017/1140/टी0सी0वी0/ए0जी0/2

टेंडरिंग प्रोसैस होता है। मैंने बज़ट स्पीच में जो कहा है, वह सही कहा है, वही वस्तुस्थिति है। आज कितने महीने बाद इन-प्रिंसिपल अप्रूव्ल आया है, उसके बाद डिटेल्ड नक्शे बने हैं। उसके बाद फ्रर्स्ट स्टे्ज़ पर अप्रूवल होती हैं और अभी तक इन- प्रिंसिपल अप्रूव्ल हुई हैं, अभी तक वह स्टे्ज नहीं पहुंची हैं, जब नेशनल रोड अथोरिटी, ये कह दें कि हां, ये काम चालू करो और ये पैसा आपको भेजा जाता है। अभी वह स्टेज़ नहीं आई है, लेकिन बहुत प्रोसैस हो चुका है। I am sure now that the final stage where it will be finally sanctioned and money will be allotted is yet to come. We are trying to expedite the entire process.

श्री वीरेन्द्र कंवरः उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये जो उच्च मार्ग स्वीकृत हुए हैं, उनमें से एक भोटा से ऊना जो वाया बसोली हैं और लठैणी-

मंदली पुल भी इसका हिस्सा हैं, जिसकी नोटिफिकेशन भी हो गई है। मुझे जानकारी मिली है कि उसकी डी0पी0आर0 बनाने का टेंडर भी हो चुका है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उसका स्टेट्स क्या है और उस डी0पी0आर0 को पूरा होने के लिए कितना समय लगेगा?

मुख्य मंत्रीः उपाध्यक्ष महोदय, ये सड़क भी अंडर प्रोसैस है। अभी तक इसकी फाईनल अप्रूव्ल नहीं हुई हैं, जिसके आधार पर टेंडर करके आगे काम चलाएं। It has progressed. Next stage would be the final approval then only the work on this road will be allotted and then work will start.

श्रीमती एन0एस0 .....द्वारा जारी।

14/03/2017/1145/ एन0एस0/ ए0जी0/1

प्रश्न संख्याः 3798 -- क्रमागत

श्री महेन्द्र सिंह : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने इस प्रश्न के 'ख' भाग में उत्तर दिया है कि डी0पी0आर0 बनाने के लिए सलाहकार को नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। क्या सलाहकार को नियुक्त करने की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है? उपाध्यक्ष महोदय, अगर सलाहकार नियुक्त कर दिया गया है तो उसका नाम बता दें? दूसरा, इस प्रश्न के 'ख' भाग के उत्तर में ही आपने कहा है कि हमने डी0पी0आर0 बनाने की टैंडर प्रोसैस शुरू की है। उस टैंडर प्रोसैस में 42 रोडज़ ऐसे हैं जिनके आपने तीन बार टैंडर किए हैं और तीन बार टैंडर करने के बाद भी आप उनको फाईनलाईज़ नहीं कर सकें हैं। इसके अलावा आपने कहा है कि 12 सड़कों के टैंडर कर दिए गए हैं और उनकी टैक्निकल बिडज़ खोल दी गई हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये टैक्निकल बिडज़ कब खुली हैं और इनकी फाईनैंशियल बिडज़ आप कब खोलने जा रहे हैं? आपने इसी के उत्तर में कहा है कि हमने पांच की फाईनैंशियल

बिडज़ खोल दी हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वे पांच कौन-कौन सी सड़कें हैं जिनकी आपने फाईनैंशियल बिडज़ खोल दी हैं और पांच कौन सी कंपनियां हैं जिनको आपने डी0पी0आर्ज़0 बनाने का कार्य दिया है?

मुख्य मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, जो इससे पूर्व मैंने कहा था कि यह एक बड़ा लम्बा और कम्पलसरी प्रोसीज़र है और फाईनल अप्रूवल के बाद ही टैंडरिंग होती है तथा उसमें काम शुरू होता है। जिन सड़कों का आपने ज़िक्र किया है - I am sorry I am not able to decipher the handwriting - और टैक्निकल बिड खोलने की बात है, **they will be expedited.**

श्री सुरेश कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी जानना चाहूंगा कि नाहन-कुम्हारहट्टी को भी नैशनल हाईवे किया गया है? क्योंकि पिछले दिनों ऐसी

14/03/2017/1145/ एन0एस0/ए0जी0 /2

सूचना थी कि नाहन-कुम्हारहट्टी जो सड़क है उसकी भूमि स्टेट हाईवे से नेशनल हाईवे को ट्रांसफर कर दी गई है।

मुख्य मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, नाहन-कुम्हारहट्टी जो सड़क है वह पहले ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बनकर तैयार हुई है। इस सड़क का अवार्ड भाजपा की सरकार के समय में हुआ था और तभी बनकर तैयार हो गई थी। यह वर्ल्ड बैंक में शामिल नहीं है। इसके ऊपर कोई और कार्य करने की अभी कोई योजना नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस सड़क के निर्माण में बहुत पैसा वेस्ट हुआ है क्योंकि जो पुराना अलाईनमैंट था उसी को चौड़ा करके यह सड़क बनाई गई है और जितने मोड़ इस सड़क के अंदर हैं उससे इस सड़क की उपयोगित कम हो गई है। यह सड़क जितनी बन गई है वह ठीक है। इस सड़क में कोई परिवर्तन करने या रिअलाईन करने की अभी कोई योजना नहीं है।

श्री सुरेश कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बताया कि यह सड़क प्रधानमंत्री सड़क योजना में बनी है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी के अनुसार यह सड़क स्टेट रोड प्रोजैक्ट में बनी है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बनी है या फिर स्टेट रोड प्रोजैक्ट में बनी है?

मुख्य मंत्री : यह सड़क वर्ल्ड बैंक से बनी है।

श्री रणधीर शर्मा: उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ये जो 65 नेशनल हाईवे अधिसूचित हुए हैं इसमें श्री नैना देवी जी विधान सभा क्षेत्र से दाड़ला मोड़-नवगांव, बैरी सड़क इसमें है और कैंची मोड़ से स्वारघाट टू नैना देवी भाखड़ा तक की सड़क भी इसमें है। उनकी वर्तमान स्थिति क्या है? ये जो 12 सड़कों के टैंडर पूरे हुए हैं क्या उनमें ये भी शामिल हैं? अगर माननीय मुख्य मंत्री जी इन 12 सड़कों के नाम ही बता देंगे तो सबको जानकारी मिल जाएगी कि उन 12 में कौन-कौन सी सड़कें हैं जिनकी टैंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है?

मुख्य मंत्री, श्री आर0के0एस0---- द्वारा जारी

14/03/2017/1150/RKS/AS/1

प्रश्न संख्याः 3798...जारी

Chief Minister: Hon'ble Deputy Speaker, Sir, I want to correct my earlier answer. कुमारहट्टी-नाहन सड़क वर्ल्ड बैंक के पैसे से बनी है और इसका निर्माण पूर्व भाजपा सरकार के समय में हुआ है। जो आपने कहा उसके बारे में मैंने प्रश्न के उत्तर में विस्तृत जानकारी दी है।

श्री राकेश कालिया: उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र बार-बार बता रहे हैं कि 61 रोड्स नेशनल हाईवे डिक्लेयर किए गए हैं। उन रोड्स को बनाने और उनके प्राक्कल के लिए केंद्र

सरकार क्रेडिट तो ले रही है परन्तु कितना पैसा केंद्र सरकार द्वारा दिया गया है? क्योंकि हमारे कहावत है कि 'बिना छोलया बबरुंआं ते गीत नहीं हुंदे।' अगर पैसा आया हो तो आप(विपक्ष की ओर इशारा करते हुए) क्रेडिट भी लें। यह मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं?

मुख्य मंत्रीः उपाध्यक्ष महोदय, जो पुराने नेशनल हाईवे पहले से चल रहे हैं उनको छोड़कर अभी किसी भी सड़क के लिए पैसा नहीं आया है। जो नई घोषित सड़कें हैं उनके लिए प्रोसैस जारी है। कई सड़कों का प्रोसैस बहुत आगे पहुंच चुका है और इसमें जल्द आगे बढ़ने की उम्मीद है। कुछ सड़कें ऐसी हैं जो अभी प्रारम्भिक स्टेज़ पर हैं।

श्री रणधीर शर्माः उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि किसी सड़क के लिए पैसा नहीं आया है। जब डी.पी. आर. ही नहीं भेजी गई है तो पैसा कहां से आएगा? इसलिए यह प्रश्न पूछना भी ठीक नहीं था और यह जवाब भी शायद गुमराह करने वाला है। दूसरा, जो मैंने 12 सड़कों के बारे में पूछा था जिनकी टेंडर प्रकिया पूरी है, उन 12 सड़कों की सूची यहां पर नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि विस्तृत जवाब दिया गया है परन्तु इस सूची में ये सड़कें नहीं दर्शाई गई हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी इन 12 सड़कों के बारे में कृपया बतलाने की कृपा करें? इसके अतिरिक्त मेरे विधान सभा क्षेत्र की जो 2 सड़कें दाड़लामोड़ से बैरी वाया नगांव और स्वारघाट से भाखड़ा वाया कैंची मोड़ हैं, इन दोनों सड़कों की वर्तमान स्थिति क्या है?

14/03/2017/1150/RKS/AS/2

मुख्य मंत्रीः उपाध्यक्ष महोदय, यह जो 229 करोड़ रुपये हैं This is earmarked to be given to the Himachal Pradesh. We have not received even one single paisa out of it, so far.

श्री रणधीर शर्माः उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी तक 12 सड़कों के बारे में नहीं बताया है।

मुख्य मंत्रीः उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य चाह रहे हैं उसकी सूचना अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है। मैं आपको आज ही पत्र देकर सूचित करूंगा।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी बार-बार कह रहे हैं कि एक भी पैसा केंद्र सरकार से नहीं आया है। आप अपने बजट अभिभाषण और इस प्रश्न के उत्तर में दो अलग-अलग आंकड़े देख रहे होंगे। एक में कहा कि 299 करोड़ रुपये इनप्रिंसिपल एग्री हो गए हैं और दूसरे में 229 करोड़ रुपये कह रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत बड़ा लम्बा अनुभव है। क्या यह सत्य नहीं है कि पहले डी.पी.आर. बनाई जाएगी, फिर बिल रेज होंगे और उस बिल के अंगेस्ट पेमेंट आएगी। आपको एडवांस पेमैंट कैसे आएगी, जब डी.पी.आर. आपने अभी टेंडर की है? How can you expect payment against that?

Chief Minister: Hon'ble Deputy Speaker, Sir, Hon'ble Prof. Prem Kumar Dhumal had been the Chief Minister but not the PWD Minister. I happened to be Chief Minister and PWD Minister. I know better than you. मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी इनप्रिंसिपल अप्रूवल आया है, फाइनल अप्रूवल नहीं आया है और उसके बाद ही पैसा आता है। यह बात आपको मालूम होनी चाहिए।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं प्रश्न पूछता हूं तो माननीय मुख्य मंत्री जी को तकलीफ हो जाती है और आप अपना ज्ञान भी खो बैठते हैं। मैं भी पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर रहा हूं परन्तु आपकी तरह गलत ब्लेम नहीं करता था। आपने वही बात कही जो मैंने प्रश्न में कही थी कि जब डी.पी.आर्ज. बनेगी, बिल रेज होगा that will be reimbursed by the Govt. of India.

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

14.03.2017/1155/SLS-AS-1

प्रश्न संख्याः 3798...क्रमागत

प्रोफ़ेसर प्रेम कुमार धूमल...जारी

तो यह दुष्प्रचार है कि सैंट्रल गवर्नमैंट पहले नहीं दे रही है।

मुख्य मंत्री : दुष्प्रचार नहीं है।। I am saying the true story and the fact, as it is. They have accepted to them in principle. जो यह नई सड़कें हैं, अभी तक इनमें से किसी भी सड़क के लिए फाइनल अप्रूवल नहीं आई है। जो पुराने नेशनल हाईवेज हैं, उनके लिए पैसा आया है, मगर जो यह नई सड़कें हैं, अभी तक इनके लिए पैसा नहीं आया है। जब इनकी फाइनल अप्रूवल आएगी, उसी के साथ वह पैसा भी रिलीज करेंगे। उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया चलेगी।

श्री रविन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री से जानना चाहता हूं, आपने कहा है कि 3 सड़कों को फोर लेन बनाने के लिए नोटिफिकेशन की है। इनमें से एक है पठानकोट-चक्की टू मण्डी रोड, दूसरा है शिमला-हमीरपुर-मटौर रोड। इन दोनों पर आजकल युद्धस्तर पर काम चला है। चक्की-पठानकोट-जसूर से मण्डी की ओर सारी सड़क पर काम लगा है। फिर शिमला से शालाघाट और हमीरपुर तक सारी सड़क पर काम लगा हुआ है जबकि यह दोनों सड़कें फोर लेन में होनी हैं। मुझे लगता है कि जब आप इसकी फोर लेन की प्रक्रिया पूरी करेंगे तो वहां फिर से ख़र्चा होगा। क्या यह काम फोर लेन का लगा है या केवल वाइडनिंग या स्ट्रैंथनिंग का काम है। एक तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूं। आपने जो नोटिफिकेशन की है उसमें हमीरपुर-सुजानपुर-आलमपुर-पालमपुर रोड भी इसमें नेशनल हाईवे के लिए नोटिफाई किया है जबकि यह 35 किलोमीटर है। आपने इसकी रिपेयर के लिए किसी को टैंडर अवार्ड किया है। उस सड़क का आलमपुर से लेकर ठाकुरद्वारा तक बुरा हाल है। अपने इसके लिए 26,11,25,000 रुपये का टैंडर दिया है। तीन सड़कें छोटी-छोटी और हैं जिनको भी साथ में जोड़ दिया है। इतना बड़ी राशि सिंगल टैंडर पर अवार्ड कर दी है।

14.03.2017/1155/SLS-AS-2

इसमें क्या कारण है कि एक ही पार्टी को बुलाया गया? सतीश अग्रवाल एंड कंपनी है जिसे यह काम दिया गया है।

मुख्य मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो बजट में 299 करोड़ something का फिगर है, It is a misprint. Actually the money which is to come i.e. 229 cores, which has not come so far. जिस सड़क का वर्णन माननीय सदस्य ने किया, यह टू लेन की है। They are two lane roads and not four lane roads. That are also approved and budgeted much earlier. ...(व्यवधान)... अरे भाई, इतनी ठेस क्यों मारता है? ठेस मत मारो। सुनो। It is not the boxing bout.

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया आप बैठ जाएं।

मुख्य मंत्री : मैं आपसे यह कह रहा हूं कि जहां तक पठानकोट-चक्की रोड का सवाल है, it is sanctioned much earlier. It is a two lane road and same is the Shimla-Matour Road. जो नया बैच ऑफ रोड है, यह उससे पहले की सैंक्शन हैं।

प्रश्न काल समाप्त

अगली मद..श्री गर्ग जी

14/03/2017/1200/RG/DC/1

<u>साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य</u>

उपाध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री जी माननीय सदन को इस सप्ताह की शासकीय कार्य सूची से अवगत कराएंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय सदन को इस सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से अवगत करवाता हूं जो इस प्रकार से है :-

मंगलवार, 14 मार्च, 2017 - 1. शासकीय/विधायी कार्य,

2. बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2017-18- सामान्य चर्चा।

बुधवार, 15 मार्च, 2017 - 1. शासकीय/विधायी कार्य,
2. बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2917-18 - सामान्य चर्चा।

वीरवार, 16 मार्च, 2017 - 1. शासकीय/विधायी कार्य,
2. बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2917-18 - सामान्य चर्चा।

शुक्रवार, 17 मार्च, 2017- 1. शासकीय/विधायी कार्य,
2. बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2917-18 - सामान्य चर्चा।

14/03/2017/1200/RG/DC/2

कागजात सभा पटल पर

उपाध्यक्ष : अब कागजा़त सभा पटल पर रखे जाएंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी अब कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

मुख्य मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अधिनियम, 1968 की धारा 15(1) और (4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2015-16 (1.4.2015 से 31.3.2016 तक) की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

उपाध्यक्ष : अब माननीय खाद्य, नागरिक आपूति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सड़क परिवहन अधिनियम, 1950 की धारा 33(4) के अन्तर्गत हिमाचल पथ परिवहन निगम के 42वें वार्षिक लेखे एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

14/03/2017/1200/RG/DC/3

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

उपाध्यक्ष : अब सदन की समितियों के प्रतिवेदन होंगे। श्री रविन्द्र सिंह जी, सभापति, लोक लेखा समिति (वर्ष 2016-17) के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर भी रखेंगे।

श्री रविन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं :-

i. समिति का **165वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 145वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग** से सम्बन्धित है; और

ii. समिति का **166वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 146वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग** से सम्बन्धित है।

उपाध्यक्ष : अब श्री संजय रतन, सदस्य, लोक उपक्रम समिति (वर्ष 2016-17) के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर भी रखेंगे।

श्री संजय रतन, सदस्य, लोक उपक्रम समिति : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से समिति का **66वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन आर्थिक क्षेत्र (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) 31 मार्च, 2012

के ऑडिट पैरा संख्या 4.8 की समीक्षा पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित** से सम्बन्धित है, की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

14/03/2017/1200/RG/DC/4

मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

उपाध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री जिला किन्नौर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, निचार परीक्षा केन्द्र संख्या 2,551 से दस जमा दो के प्रश्न-पत्रों की चोरी के सन्दर्भ में सदन को अवगत करने बारे वक्तव्य देंगे।

Chief Minister : Deputy Speaker, Sir, I wish to inform this August House that the Board of School Education Dharamshala has informed that the question papers of Physic and Computer Science of 10+2 class Board Examination were stolen on the night intervening 12-03-2017 and 13-03-2017 from Examination Centre No. 2551 Government Senior Secondary School Nichar, Distt. Kinnaur.

According to Principal of the School, these were stolen from the double lock almirah of the school which was found broken in the morning on 13th March ,2017. On verification, it was found that the two packets containing 60 question papers each of Physics and Computer Science were missing apart from 52 answer sheets of Physics and 44 answer sheets of Mathematics of Class 10 examination. Principal has also informed that chowkidar has been deployed around the clock at the School but despite that , this unfortunate incident has happened about which the local police has been informed and FIR has been registered and investigation is underway. Detailed inquiry is also being held by the Deputy Secretary of School Education Board and SDO(Civil) Nichar. It is

further informed that the examination of Physics was originally scheduled for 14th March, 2017 and has been postponed. The fresh date will be notified by the Board of School of Education shortly.

एम.एस. द्वारा जारी

14/03/2017/1205/MS/DC/1

वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए बजट अनुमान

उपाध्यक्षः अब वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा होगी।

डॉ0 राजीव बिन्दलः उपाध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, मुझे उसके बारे में कुछ कहना है।

उपाध्यक्षः इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होती है। आप कृपया नियम के तहत नोटिस दीजिए। I am not allowing you .

डॉ0 राजीव बिन्दलः उपाध्यक्ष जी, महत्वपूर्ण विषय है।

उपाध्यक्षः कोई बात नहीं। Please be seated. I am not allowing you.---(interruption)---. I have not allowed you to speak. Nothing will go on record. माननीय सदस्य आप नियमों के खिलाफ बोल रहे हैं। Please, be seated.

मुख्य मंत्रीः आप बैठिए। पहले आप नोटिस दीजिए।---(interruption)--- Don't try to throw mud on the Himachal Pradesh State Education Board.

डॉ0 राजीव बिन्दलः आपने कहा है कि पेपर चोरी हुए हैं।

मुख्य मंत्रीः क्या पेपर पहले चोरी नहीं हुए हैं? -(व्यवधान)- आप खामोश रहिए। Please sit down, I am not yielding, please sit down, I have yet to say. जब मैं बैठूंगा, तब आपने बोलना। Sir, it is not unusual, in the past also papers have leaked. Even

University papers have leaked, Education Board papers have leaked some way or the other, where there is big change of examination halls. Therefore, Board has taken timely action and we have cancelled these papers and fresh dates will be issued for examinations in these subjects. (---(interruption)---)

14/03/2017/1205/MS/DC/2

Deputy Speaker: Please, be quite. आज से वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट अनुमानों वार्षिक वित्तीय विवरण पर सामान्य चर्चा आरम्भ होगी। चर्चा का समापन 17 मार्च को माननीय मुख्य मंत्री महोदय के उत्तर के साथ होगा। समय की उपलब्धतता तथा पूर्व परम्पराओं के अनुरूप विपक्ष के नेता को 45 मिनट का समय तथा प्रत्येक अन्य माननीय सदस्य को 15-15 मिनट का समय बोलने के लिए उपलब्ध होगा। मेरा सभी माननीय सदस्यों से यह निवेदन रहेगा कि वे अपने-अपने भाषण बजट तक ही सीमित रखें तथा निर्धारित अवधि के भीतर समाप्त करें। साथ में मेरा यह भी अनुरोध रहेगा कि उन बिन्दुओं को दुबारा न दोहराएं जिन पर पहले चर्चा हो चुकी हो।

अब मैं सर्वप्रथम विपक्ष के नेता, प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी को चर्चा आरंभ करने के लिए आमंत्रित करता हूं।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः उपाध्यक्ष जी, वर्ष 2017-18 का बजट माननीय मुख्य मंत्री जी ने 10 मार्च को प्रस्तुत किया है। यह उनके द्वारा इस प्रदेश का 20वां बजट था।

जारी श्री जे0एस0 द्वारा----

14.3.2017/1210/जेके/एजी/1

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः-----**जारी**-

लगभग साढ़े चार घण्टे तक मुख्य मंत्री जी ने इस बजट को पढ़ा है वह भी विश्व रिकॉर्ड बन गया है, उसके लिए भी उनको बधाई देता हूं। सभी माननीय सदस्यों ने यह सारा कुछ साढ़े चार घण्टे सहा, उनको धन्यवाद देता हूं क्योंकि कुछ ने सुना और कुछ सुजान सिंह पठानिया जी जैसे थे जो सो गए इसलिए उन्होंने सहा। अच्छी बात यह थी कि जो मुख्य मंत्री सदा सोए रहते थे ,उस दिन ये जाग रहे थे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बार-बार इस बजट स्पीच को पढ़ा कि आखिर क्या था कि इतने लम्बे समय तक बोलना पड़ा? मैं आखिरी पैराग्राफ से शुरू करूंगा। पैराग्राफ नम्बर 160 है। इसमें बजट अनुमानों के अनुसार यदि बजट 100 रूपया हो तो कैसे खर्च होगा और कहां से आएगा? इसका विवरण दिया जाता है। यह बजट का सारा निचोड़ होता है। इन्होंने कहा कि कुल प्राप्तियां 77 रूपए 45 पैसे होगी और 22 रूपये 55 पैसे ऋण द्वारा लेकर उस अन्तर को पूरा कर दिया जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, जो प्राप्तियां उसमें केन्द्रीय सरकार के करों में 17.39 रूपए का हिस्सा है। केन्द्र के अनुदान का 48.16 रूपए का हिस्सा है, अर्थात् लगभग 65 रूपए कुछ पैसे बन जाता है। 22 रूपए 55 पैसे ऋण लेंगे। लगभग 88 प्रतिशत से ज्यादा केन्द्र की मदद और ऋण से होगा। माननीय मुख्य मंत्री जी जितना विवरण बाकी बोल रहे थे वह 12 प्रतिशत के बारे में चर्चा थी। Much ado about nothing. स्टेट का कंट्रिब्यूशन क्या है? What have you done to mobilize the resources for the State? उपाध्यक्ष महोदय, मैंने वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 और 2016-17 चार बजट इनके पुराने और यह पांचवा बजट देखा। कुल मिला करके ढूंढने की कोशिश की है कि हर बार इन्होंने क्या-क्या घोषणा की, अगली बार उसका कोई जिक्र नहीं। केवल यह घोषणाओं की सरकार है। प्रैक्टिकली कुछ नहीं होता और विकास कार्य ठप्प पड़े हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जो 22.55 प्रतिशत ये ऋण लेने की बात कर रहे हैं, कोई भी राज्य वही ऋण ले सकता है जो आर्टिकल 293 सब-सेक्शन 3 संविधान के मुताबिक अनुमति केन्द्र से मिले। इनको बार-बार केन्द्र ने कहा है कि आप लिमिट क्रॉस कर रहे हैं और

14.3.2017/1210/जेके/एजी/2

यह सरकार उसी रास्ते पर आगे चल रही है और आने वाले समय में ऋण लेने का जो ऑल्टरनेटिव होता है, वह भी खत्म होने वाला है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आंकड़ों से ही अपनी बात कहना चाहूंगा कि वर्ष 2016-17 के इनके बजट में इन्होंने कहा कि रेवन्यू डैफिसिट 476 करोड़ रूपये है और फांनैशियल डैफिसिट 4,076 करोड़ रूपए था। मुख्य मंत्री महोदय, आप हमेशा प्रूडैंट फाईनैंशियल मैनेजमैंट की बात करते हैं बड़ा दक्ष प्रबन्धन और आपका प्रबन्धन यह है कि 476 करोड़ रूपए का रेवन्यू डैफिसिट था।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी------

14.03.2017/1215/SS-AG/1

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल क्रमागतः

वह इस साल के बजट में आपके अनुसार 1041 करोड़ हो गया। 600 करोड़ के लगभग वह बढ़ गया। जो फाइनैंशियल डैफिशिट 4076 करोड़ था, वह 4946 करोड़ हो गया। लगभग 900 करोड़ यह बढ़ गया और आप वर्तमान किसी तरह निकल जाए इसको पूरा करने के लिए सारा जोर ऋण लेने पर लगा रहे हैं। यद्यपि केन्द्र से बहुत ज्यादा धन भी उपलब्ध हो रहा है। आप में एक नयी बात देखने को मिली, कवि हृदय भी ज्यादा है। आपने बहुत सारी पंक्तियां हर चार-पांच मिनट बाद बोली हैं। मैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता से पंक्ति कहना चाहूंगा। जो आप वर्तमान का समय निकालने के लिए ऋण लेते जा रहे हैं उससे भविष्य अंधकारमय होगा।

"वर्तमान के मोहजाल में आने वाला कल न भूलाएं"

ऐसी नीतियां न अपनाएं कि आज का टाइम तो निकल जाए लेकिन कल को दिक्कत हो जाए।

"वर्तमान के मोहजाल में आने वाला कल न भूलाएं,
आओ फिर से दीया जलाएं"

कुछ रिसोर्स मोबेलाइजेशन करें। उपाध्यक्ष महोदय, 2013-14 में केन्द्र सरकार ने इनको 2448 करोड़ का ऋण लेने का अधिकार दिया था लेकिन एक्चुअली इन्होंने 4011 करोड़ ऋण लिया। लिमिट से ऑवर 1563 करोड़ ले लिया। 2014-15 में फिर आर्टिकल 293 (3) के अंडर 2786 करोड़ का अधिकार था लेकिन इन्होंने 4200 करोड़ ऋण लिया। 1414 करोड़ एक्सट्रा लिया। 2015-16 में 3156 करोड़ का अधिकार था लेकिन इन्होंने 3284 करोड़ ले लिया। यानी 128 करोड़ सरप्लस है। मैं हैरान था कि पहले 1400-1500 करोड़ फालतू ले रहे थे लेकिन अब 128 करोड़ पर आ गए। आपकी प्रूडैंट फाइनैंशियल मैनेजमैंट यह है कि हर साल 12 महीने की तनख्वाह मिलती है लेकिन आपने 2015-16 में 11 महीने की ही तनख्वाह शो की।

14.03.2017/1215/SS-AG/2

लगभग 1200 करोड़ रुपया तनख्वाह कम शो करके आपने ऋण कम शो कर दिया। तो अगले साल बर्डन पड़ेगा। 2016-17 में 3540 करोड़ का अधिकार था लेकिन आपने 4075 करोड़ ऋण ले लिया। उपाध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर 5000 करोड़ रुपया ये फालतू ले चुके हैं। केन्द्र से इतनी मदद मिलने के बावजूद जो 13वें वित्तायोग के कारण 20 हजार करोड़ लगभग पांच वर्षों में मिला था, जब केन्द्र में यू0पी0ए0 सरकार थी और यहां हमारी सरकार थी और आपकी भी थोड़े टाइम के लिए थी। अब आपको 40625 करोड़ मिल रहा है और कुल मिलाकर लगभग 72 हजार करोड़ रुपया पांच वर्ष में स्पैशल कैटेगिरी स्टेट के स्टेट्स के कारण और अन्य कारणों से फालतू प्रदेश को मिलेगा। लेकिन उस केन्द्र सरकार पर आलोचना होती है कि दे कुछ नहीं रहे, भेदभाव हो रहा है। तो उसी शेरो-शायरी में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा किः-

"जवानी में चाहे आदमी की जोश न हो

जवानी में चाहे आदमी की जोश न हो,
बात करने की चाहे होश न हो,
लेकिन लाख नुक्स हों इंसान में
लेकिन इंसान अहसान फरामोश न हो। "

जारी श्रीमती के0एस0

14.03.2017/ 1220/केएस/एएस/1

पो0 प्रेम कुमार धूमल जारी----

केन्द्र से इतना कुछ मिलने के बावजूद आप कर्जे पर कर्जा उठाए जा रहे हैं। प्रदेश की आर्थिक स्थिति को खराब करते जा रहे हैं। केन्द्र सरकार के पत्र दिनांकः 28.06.2016 के अनुसार 31 मार्च, 2017 तक हिमाचल प्रदेश का ऋण लगभग 45 हजार 213 करोड़ 30 लाख हो जाएगा और डायरैक्टर एक्सपैंडिचर ने आपको 29 मार्च, 2016 को चेताया था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उनका लैटर कोट करना चाहूंगा। 14वें वित्तायोग के कारण फिस्कल डैफिसिट का टारगेट 3 परसेंट है । कन्क्लूडिंग पैराग्राफ में वे लिख रहे हैंः Since the primary responsibility of remaining within the overall debt GSDP norms recommended by the 14th Finance Commission and the borrowing ceiling shall remain with the State. Primary responsibility will be of the State to remain within 3% of the fiscal deficit. आपका 3.5 आप इस बार कह रहे हैं और पिछली बार 4 परसेंट से ज्यादा था। It is advisable to continually track the liabilities so that the State does not inadvertently breach in net annual borrowings ceiling. State may also calibrate its borrowings with expenditure requirements and approach the market after assessment of its treasury holdings इस पत्र को भी आपने इग्नोर किया। यह केन्द्रीय फाईनैंस मिनिस्ट्री का पत्र है, इसमें भी इन्होंने कहा कि रेवन्यू डैफिसिट ग्रांट 40 हजार 625 करोड़ दी जा रही है इसके बावजूद आपका लोन बढ़ता जा रहा है और debt trap में स्टेट फंस रही है। States maintaining the debt GSDP ratio

within 25% that interest payment revenue receipts ratio within 10% in the previous years. तो अगले साल ऋण आपको तब मिलेगा अगर आप उन शर्तों को मानते हैं जो केन्द्र ने लगाई हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सख्त कंडिशन्ज़ हैं जो ये इग्नोर कर रहे हैं। जो मैंने 72 हजार 47 करोड़ का आंकड़ा दिया था, रेवन्यू डैफिसिट ग्रांट 40 हजार 625 करोड़ total PRI/Panchayati Raj Institutions and Urban Local Development Bodies Rs. 2011 crore, State Disaster Relief Fund Rs. 1304 crore, Share in Central Taxes Rs. 28,107 crore.

हिन्दी श्रीमती अ0व0 की बारी में-

14.3.2017/1225/av/as/1

श्री प्रेम कुमार धूमल ---क्रमागत

यह कुल मिलाकर 72 हजार 47 करोड़ रुपये बनता है। इसके बावजूद भी कर्जा लगातार बढ़े यह उचित नहीं लगता और न ही इसका कोई औचित्य बनता है। मैंने कहा था कि चैप्टर 14 का ऐनक्सचर है जो भारत सरकार ने जारी किया Rawling Target Flexibility: If a state is in a given year borrows over and above the sanctioned borrowings limit by the limit percent amount then in the succeeding year the same amount of the previous year will be deducted from state borrowing limit of that year. मैंने जो लिमिट पढ़ी यानि जो इनको लिमिट्स मिली थीं वह तीन या साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये के बीच में ही थी। लेकिन ये हर बार चार हजार करोड़ क्रोस करते रहे। उसको डिडक्ट कर लेंगे। यहां पर केंद्र ने उदाहरण दिया है। For example, in 2015-2016 GSDP of a state is 1.00 lakh crore with borrowing limit of 3000 i.e. 3% of GSDP. However, the Sate over utilizes the limit by say about 0.5% equivalent to 500 in the succeeding year 2016-2017, if the State has an estimated GSDP of 1 lakh 50 thousand and is allowed to borrow 4500, as per rules and

formulations, the effective borrowing of the State will be 4000 because 500 will be decreased from 4500. अगर किसी की लिमिट तीन हजार करोड़ है और वह साढ़े तीन हजार करोड़ ऋण लेता है तो अगले साल अगर वह चार या साढ़े चार हजार करोड़ बन जाती है तो 500 करोड़ रुपये कम हो जायेंगे। इनस्ट्रक्शन्ज में यह बिल्कुल क्लीयर है। ये 5 हजार करोड़ ऐक्स्ट्रा ले चुके हैं। इस तरह से इन्होंने भविष्य के लिए लोन लेने का भी सारा काम बंद कर रखा है। इस तरह से जो प्रूडैंट फाइनैंशियल मेनेजमैंट का बार-बार दावा किया जाता है उससे इस प्रदेश को बहुत नुकसान हो रहा है और उसी के ऊपर साढ़े चार घंटे का सारा बजट भाषण था। संसाधन जुटाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया। यह वाहवाही तो हो सकती है कि इस बार जो बजट दिया उस पर कोई टैक्स नहीं लगा। मैं मानता हूं कि टैक्स लगाने की सम्भावनाएं अगर कम भी हो---

14.3.2017/1225/av/as/2

माना कि अन्धेरा घना है।
पर दिया जलाना कहां मना है॥

आप फिजूलखर्ची तो रोक सकते हो। 45-50 चेयरमैन / वाइस चेयरमैन की फौज और उनकी गाड़ियां-कोठियां; उनका काम क्या है? 5-7 चेयरमैन तो रोज हमारे खिलाफ स्टेटमैंट देने के लिए ही होते हैं। मुझे लगता है कि वह प्रैस नोट भी उनका शायद पब्लिक रिलेशन डिपार्टमैंट बनाता है और नाम उनके चलता है। कहीं यह स्थिति न आ जाए कि कल को कोई ऋण देने से भी इनकार कर दे, सारे-का-सारा बजट केवल ऋण की अदायगी में लग जाए और फिर कहेंगे :-

कर्ज की पीते हैं शराब।
समझते हैं कि रंग लायेगी इनकी फ़ाकामस्ती एक दिन॥

बेरोजगारी भत्ते की घोषणा की गई। वह 1500 प्रति माह वाला तो छोड़िए यहां पर 12 लाख से ऊपर बेरोजगार हैं। आपका अगर पंजीकृत 8.24 लाख का आंकड़ा ही मानें और उनको आप 1000 रुपये देंगे तो

श्री टी0सी0वी0 द्वारा जारी...

14/03/2017/1230/टी0सी0वी0/डी0सी0/1
प्रो0 प्रेम कुमार धूमल --- जारी

तो एक महीने के लिए 82 करोड़ 40 लाख रूपया तथा 12 महीने के लिए 988 करोड़ 80 लाख रूपया चाहिए। यदि 5 साल के वायदे के अनुसार कैल्कुलेट करोगे तो 12 हजार करोड़ से ज्यादा बनता है। माननीय मुख्य जी ने घोषणा की 2 पोलिटेक्निक और खोलेंगे, हमने 34 आई0टी0आईज खोल दिए हैं। जिस सप्ताह में आपने यहां बजट भाषण पढ़ा उसी सप्ताह का एक उत्तर आपकी सरकार का इस सदन में हैं। उपाध्यक्ष महोदय, 2014-15 में गवर्नमेंट आई0टी0आईज़ में 2105 सीटें खाली रही। इनमें कोई एडमिशन लेने वाला नहीं था। प्राइवेट आई0टी0आईज़ में 4,820 सीटें खाली रही और कुल 6,925 सीटें खाली रही हैं। इनके लिए स्टूडैंट ही नहीं मिलें। पोलिटेक्निकल (गवर्नमेंट) में 170 सीटें खाली रही और ये नये पोलिटेक्निक खोलने की बातें कर रहे हैं। इसी तरह से प्राइवेट पोलिटेक्निक में 7,577 सीटें खाली रही हैं। आप किसके लिए पोलिटेक्निक और आई0टी0आईज खोल रहे हैं। वहां कौन पढ़ रहा है। भारत सरकार से जो पैसा आता है, उससे बिल्डिंग बनाकर उद्घाटन के पत्थर लगा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय 2014-15 में केवल आई0टी0आईज और पोलिटेक्निक (सरकारी/प्राइवेट) का अगर टोटल कर लें तो 14,662 सीटें खाली थी, जहां पर कोई स्टूडैंट दाखिल नहीं हुआ। वर्ष 2015-16 में सरकारी आई0टी0आईज0 में 3,523 सीटें खाली रही और प्राइवेट आई0टी0आईज में 3,567 अर्थात् 7,090 सीटें खाली रही हैं। सरकारी पोलिटेक्निक में 75 और प्राइवेट पोलिटेक्निक में 7,664 सीटें खाली रही हैं। ये सरकार के आंकड़ें हैं। वर्ष 2016-17 में सरकारी आई0टी0आईज में 4,621 सीटें और प्राइवेट आई0टी0आईज में 9,008 सीटें खाली रही हैं, दोनों में कुल 13,629 सीटें

आई0टी0आई0 लैवल की आपकी खाली रही हैं। आप कह रहे हैं कि हमने 34 आई0टी0आईज नये खोल दिए हैं। सरकारी पोलिटेक्निक में 162 और प्राइवेट में 6,275 सीटें खाली रही हैं। उपाध्यक्ष महोदय, केवल आई0टी0आई0 और पोलिटेक्निक की बात नहीं हैं, जो डिग्री कॉलेजिज़ हैं, जहां बी-टेक है, वहां सरकारी में 23 और प्राइवेट कालेजिज़ में 5004 सीटें खाली रही हैं। इनमें एम-टेक की 207 सीटें खाली रही हैं। कुल 288 में से केवल 81 लोग ही एम-टेक करने के लिए आए। बी-टेक में 5,341 खाली रही और एम-टेक में अगले साल ये 254 हो गईं। वर्ष 2016-17 में 35 बी-टेक (सरकारी) में

14/03/2017/1230/टी0सी0वी0/डी0सी0/1

और 5,574 सीटें प्राइवेट में खाली रही हैं। इसके अलावा पिछले साल 306 सीटें एम-टेक की खाली रही हैं। इनमें कुल 5,915 सीटें खाली रही। इसलिए ये घोषणाओं का बजट है कि हम ये खोलने जा रहे हैं। आप पत्थर तराशने चले हों, लेकिन मुख्य मंत्री महोदय, प्रदेश कहीं आगे गति नहीं पकड़ रहा है, कोई उत्थान आगे नहीं हो रहा है।

श्रीमती एन0एस0 .... द्वारा जारी।

14/03/2017/1235/ एन0एस0/डी0सी0 /1

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल ----- जारी

आपने 19,000 पद भरने की घोषणा की है। अगर सारा कुल मिला करके देखें तो पांच सालों में आपने 40,000 के करीब पोस्टें भरने के लिए कहा था। उनमें से 19,000 तो अभी भरने की बात है। आपने कितनी तहसीलों और सब-तहसीलों की घोषणा कर दी है। 37 पद तहसीलदार, 31 पद नायब-तहसीलदार के खाली हैं और इन 19,000 पदों में कोई तहसीलदार/नायब-तहसीलदार भरने का नाम नहीं है। आप किसको गुमराह कर रहे हैं और कब तक करेंगे? इससे आप खुद गुमराह हो रहे हैं, कोई अन्य गुमराह नहीं हो रहा है

क्योंकि प्रदेश के लोग अब आपकी घोषणाओं को गम्भीरता से नहीं लेते हैं। आप जहां जाएं अगर कोई आपसे मिडल स्कूल की डिमांड करता है तो आप हाई स्कूल की बजाए सीनियर सैंकेडरी (प्लस टू) अनाउंस कर देते हैं। फिर आप कह रहे हैं कि

"कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं।

न जाने किस-किस का हौंसला हूं मैं।"

"कैसे कह दें कि थक गए हैं आप।

न जाने किस-किस की नज़र है तुम्हारी कुर्सी पर।"

Chief Minister:- I don't understand this joke.

Prof. Prem Kumar Dhumal: It is difficult to understand the things. अगर आपने कह दिया कि मैं थक गया हूं। आप ऐसा कह ही नहीं सकते हैं क्योंकि कई इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि अगर यह थक गए हैं तो हम आएं। अब तो आप समझ गए होंगे।

मुख्य मंत्री : आप भी इस कुर्सी पर आईंदा होंगे या नहीं होंगे, क्या इसकी कोई गारंटी है?

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अर्थशास्त्र का ज्ञान प्रकट करते हुए कहा कि डिमोनीटाईजेशन ने सब कुछ तबाह कर दिया है। उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड में कर दिया है तो ठीक है। आपने केंद्र की जी0डी0पी0 कम होने की बात कही है। उसको आपने 7.9 से 7.1 कहा था। अब रिवाईज़ड एस्टिमेट 7.4 आ गया है।

14/03/2017/1235/ एन0एस0/डी0सी0 /2

आपकी तो 8.1 से 6.8 रह गई है। वही बात है, "अपनी सम्भाल तू परायी नबेट छोड़।" आपने कभी देखा कि डिमोनीटाईजेशन का आप पर क्या फर्क पड़ा है? घरेलू सकल उत्पाद में गिरावट के क्या कारण हैं? घरेलू सकल उत्पाद वर्ष 2015-16 में 10.4 था वह वर्ष 2016-17 में 9.4 कैसे रह गया है? आपने क्या कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए हैं? क्या आपने बंजर भूमि को काश्त करने के लिए, गैर-हाज़िर कृषकों की समस्याओं से निपटने के लिए कोई कदम सोचे हैं? इसके अलावा आपने पर्यटन की बात कही है। मैं क्षेत्रवाद की बात नहीं करना चाहता हूं। जहां पर प्रकृति ने अच्छी जलवायु,

अच्छा स्थान दिया है वहां पर पर्यटक अवश्य आएंगे लेकिन कांगड़ा, हमीरपुर और ऊना में भी पर्यटक स्थल बन सकते हैं। आपने जो प्रोजैक्ट 100 करोड़ का सबमिट किया है और जिसे केंद्र के पर्यटन विभाग ने स्वीकृत कर दिया है, उसमें काश ये क्षेत्र भी शामिल होते। जब आप नीति बनाते हैं तो आपका विदेशी दार्शनिकों पर बड़ा जोर रहता है। कभी वाशिंगटन की बात आई और कभी मार्टिन किंग लूथर की बात आई। कभी किसी ओर नेता की आई। मैं भी आपको कहना चाहूंगा कि चीन के दार्शनिक कन्फ्युशियस ने कहा है कि अगर हम एक वर्ष की योजना बनाते हैं तो समझो कि हम चावल या गेंहू उगा रहे हैं।

श्री आर0के0एस0---- द्वारा जारी ।

14/03/2017/1240/RKS/AG/1

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः ....जारी

लॉंग टर्म की सोचो। यदि हम 10 वर्ष की योजना बनाते हैं तो समझो कि हमारी योजना वन लगाने की है। मनुष्य के लिए तो हमारी योजनाएं कम-से-कम 100 वर्ष की होनी चाहिए। इसलिए जो हमारी गतिशील योजना है कि 'ऋण लो और शक्कर घी पीओ' वह प्रदेश की सेहत के लिए ठीक नहीं है। वर्ष 2013-14 में आपने कहा - Public Services Guarantee Act will be implemented strictly by bringing more departments in the ambit of this Act. The State Commissioner for Public Grievances will be appointed. Administrative Boundaries will be re-organized. A Commission will be formed for districts and tehsils. उसके बाद न हमने स्टेट कमीशन ग्रीवैंसिज का नाम सुना और न ही डिस्ट्रिक्ट और तहसील के रिऑर्गेनाइज़ेशन की बात कहीं पर आई। ये घोषणाएं किस के लिए हैं? इसलिए मैं कहता हूं कि आपकी घोषणाओं पर लोग विश्वास नहीं करते हैं। वर्ष 2013-14 के बजट में आपने कहा - State Innovation Fund with budget provision of Rs. 5 crores; Lok Mitra in every panchayat of the State; and Mukhyamantri Adarsh Krishi Gaon Yojna. What is the achievement? वर्ष 2013-14 का बजट आपका पहला बजट था, उसकी इम्प्लिमैंटेशन क्या है? For proper marketing of farm products seven sub-market yards in the State at a cost of Rs. 20 crores were

proposed by you. How many have been constructed? कितने मार्किट याड्र्ज़ बने। वर्ष 2013-14 के भाषण के पैरा संख्या 49, पेज 15 में माननीय मुख्य मंत्री महोदय जी ने कहा और जिन्होंने यह रिप्लाई तैयार की होगी उनके रेफरैंस के लिए भी मैं यह बात कह रहा हूं। 'आवारा पशुओं में नर पशुओं की संख्या अधिक है, इसके लिए पशुपालकों को मादा अधिपत्य शुक्राणु उपलब्ध करवा कर नर पशुओं में कमी लाएंगे'। कितनी कमी आई कि वर्ष 2017-18 का बजट आपने 10 मार्च को पेश किया। उसमें फिर आप पैरा 35, पेज 19 में कह रहे हैं और इसी बात को दोहराया है। आवारा पशु तो बढ़ रहे हैं। आपने बड़े धड़ल्ले से कहा कि मेहनत से उठा हूं, जमीन से उठा हूं, जमीन की हकीकत जानता हूं। ज़मीन की हकीकत जानते तो हर महीने जिलाशः, खंडशः पशु मंडी लगाने की बात नहीं करते। जिन नलवाड़ मेलों का आप उद्घाटन करने जा रहे हैं, उनके बारे में पहले आप पता करें। हर वर्ष 22 मार्च को सुन्दरनगर और 23 मार्च को बिलासपुर में नलवाड़ मेला होता है। जाहू का नलवाड़ मेला तो बंद हो गया है। घसौता-महादेव में बैलों का बड़ा कम्पिटिशन होता था।
14/03/2017/1240/RKS/AG/2

आजकल वहां पर एक ही बैल की जोड़ी है और वही बैल की जोड़ी प्राइस लेकर जाती है। हर महीने, हर खंड में, हर जिले में पशु मंडी। कहां से पशु मंडी लगाओगे, मंडी है कहां? जो मंडियां ट्रैडिशनली साल में एक बार लगती थी, वह मंडियां बंद हो गई हैं। आपको लोग गुमराह कर रहे हैं। यह स्थिति ऐसी नहीं है। पशु है परन्तु वे सब आवारा पशु हैं और लोगों के द्वारा निकाले गए पशु हैं। उपाध्यक्ष महोदय, शायद आपको याद होगा,मैंने इसी सदन में कहा था कि कुछ ऐसे नर पशु जो सांड हैं, जो हिमाचल में होते ही नहीं थे, वे ऐसी ब्रीड है जैसे उनको कोई बाहर से लाकर यहां छोड़ रहा है। मैंने इस माननीय सदन में निवेदन किया था कि बॉर्डर एरिया को सील करो। वहां पर चैकिंग की जाए कि ये पशु कहां से आगे आ रहे हैं। माननीय सदस्य भी इस बात से सहमत होंगे कि अजीब सी शक्ल वाले बड़े-बड़े नर पशु कहां से आ गए? यदि बाहर से कोई यह शरारत कर रहा है तो उसको रोकना भी हमारा कर्त्तव्य बनता है। यह हमारे लिए एक समस्या बन गई है। वे पशु लोगों को मारते हैं, फसल का नुकसान करते हैं।

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

14.03.2017/1245/SLS-AG-1

प्रोफ़ेसर प्रेम कुमार धूमल...जारी

आपने 4 साल पहले कहा था कि एन.जी.ओज. और ट्रस्टों को हम गौसदन बनाने के लिए पैसा देंगे। जब आप जवाब दें तो उसमें यह आना चाहिए कि 4 सालों में कितना-कितना पैसा किस-किस एन.जी.ओ. को और किस-किस ट्रस्ट को दिया गया, कितने गौसदन बनें और बाहर आवारा घूम रहे कितने पशु उन गौसदनों में गए। इसमें तो हर पंचायत को हाई कोर्ट की डायरैक्शन आ गई थी। हाई कोर्ट का डिसीज़न कहीं इंपलीमैंट नहीं हुआ। कितनी पंचायतों में गौसदन बने हैं? वहां पर चारे और पानी का प्रबंध हुआ या नहीं हुआ?

आपके 2013-14 के बजट के पेज-12 पैरा 37 में सेव के पुराने पौधों को उखाड़कर अच्छी नसल के नए पौधे लगाने की बात कही गई थी । वर्ष 2015-16 में आपने कहा कि इसी प्रोजैक्ट के अंतर्गत 1000 हैक्टेयर क्षेत्र कवर किया जाएगा। उसके लिए 10 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया। सेव के पुराने पौधों को उखाड़कर नई नसल के नए पौधे लगाने की बात कही गई। आप इटली से नई नसल के पौधे लाए। मुख्य मंत्री महोदय, इटली का रूट स्टॉक वायरस वाला हो गया है। आप वायरस फ्री लाइए। इस तरह तो आप बागवानों को तबाह कर देंगे।

2013-14 के बजट में पेज-12, पैरा 39 में आपने हमारी पिछली सरकार के निर्णय के बारे में कहा कि एंटी हेलगन की परिकल्पना गलत थी। मुख्य मंत्री महोदय, यह सत्य नहीं है। हमने तो 3 एंटी हेलगन बड़ैलघाट कोटखाई में, दयोरीघाट और बड़ालगणु जुब्बल में लगाई थी। जादू वह है जो सिर चढ़कर बोले। हमने तो 3 लगाई थी लेकिन आज हमें इस बात की खुशी है कि हमारी सरकार ने जो निर्णय लिया था, वही सही था। आपने उसे रोका लेकिन हिमाचल के बागवानों ने उसको स्वीकार किया है। आज पांच पंचायतों ने अपने पैसे पर वो एंटी हेलगन लगानी प्रारंभ कर दी है और आपके ही जिला में बागी पंचायत

(कोटखाई) में, रतनाड़ी पंचायत में, कलवोग पंचायत में, महासु बखोल पंचायत में, प्रेमनगर पंचायत में और मड़ौग क्षेत्र (चौपाल) में यह स्थापित भी कर दीं हैं। । लोगों को एंटी हेलगन 1.20 करोड़ रुपये में

14.03.2017/1245/SLS-AG-2

पड़ रही है, लेकिन लोग उसकी उपयोगिता देखकर बाहर से लाकर अपनी एंटी हेलगन लगा रहे हैं। आप भी जहां जाते हैं, अब लोग डिमांड कर रहे हैं कि एंटी हेलगन लगाओ।

एंटी हेलनैट का आपने क्या आलटरनेटिव दिया? वर्ष 2013-14 में आपके द्वारा एंटी हेलनैट पर 80 प्रतिशत् उपदान देने हेतु 165 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान, वर्ष 2014-15 में 15 लाख वर्गमीटर क्षेत्र को कवर करने की बात, वर्ष 2015-16 में अतिरिक्त 100 हैक्टेयर क्षेत्र की बात और वर्ष 2016-17 में 9 लाख वर्गमीटर क्षेत्र को एंटी हेलनैट के अंतर्गत लाया जाना प्रस्तावित। सरकार बताए कि कुल कितना क्षेत्र एंटी हेलनैट के अंतर्गत आया है? जो प्रश्न का उत्तर सदन में दिया गया, उसके अनुसार लगभग 735 बागवानों को ही इसका लाभ दिया गया जबकि इसमें आप क्लेम कुछ और करते हैं। जो 80 प्रतिशत् उपदान आप दे रहे हैं उसमें से 50 प्रतिशत् भारत सरकार देती है। 2017-18 के बजट में आप कह रहे हैं कि 25 लाख वर्गमीटर क्षेत्र और कवर किया जाएगा। फिर प्रदेश में बागवानी का कुल क्षेत्र कितना है? अगर इसका जोड़ देखें तो लगभग 70 लाख वर्गमीटर क्षेत्र को आपने अलग-अलग बजट स्पीचिज में कवर कर दिया है।

फोरैस्ट के बारे में कहते हुए आपने कहा था कि मंकीज को नियंत्रित करेंगे। बंदर और आवारा पशु ही चुनाव में आपका मुद्दा भी था। अब अगली बार वही आपको निपटेंगे भी।

जारी ..श्री गर्ग जी

14/03/2017/1250/RG/AS/1

प्रो. प्रेम कुमार धूमल---जारी

आपने कहा था कि 6 मंकी स्टरलाईजेशन सेन्टर्ज सिरमौर, चम्बा, कांगड़ा, मण्डी, सोलन और बिलासपुर में खोलेंगे। क्या वे खुल गए हैं? मंत्री जी तो माननीय उद्योग मंत्री जी की ओर इशारा कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, एक और बात Setting of Transport Nagars के बारे में कही गई थी। मैं ये चीजें इसलिए यहां कह रहा हूं कि ये आपकी घोषणाएं हैं। इन पर कौन विश्वास करेगा? वर्ष 2013-14 में दो, वर्ष 2016-17 में चार और वर्ष 2017-18 में आपने दो और ट्रांसपोर्ट नगर बनाने की बात की। तो ये ट्रांसपोर्ट नगर कितने और कहां बने? जो वर्ष 2013-14 से शुरू होकर वर्ष 2017-18 तक आ गए।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार लैपटॉप की बात कही गई। वर्ष 2013-14 के बजट में 5,000, वर्ष 2014-15 के बजट में 7,500, वर्ष 2015-16 के बजट में 10,000 और वर्ष 2016-17 के बजट में 10,000 की बात की गई, लेकिन इससे क्या लक्ष्य प्राप्त हुआ? यह बताइए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो बात फंक्शनल पोस्ट्ज को भरने की कह रहा था। तो वर्ष 2013-14 में आपने 4,050 पद भरे, वर्ष 2015-16 में 5,000 पद भरे, वर्ष 2016-17 में कहा कि 13,000 पद भर रहे हैं और अब 19,000 पदों को भरने की बात की है। अगर इन सबको मिला लें, तो प्रदेश के 12,00,000 बेरोजगार नौजवानों से आपने वायदा किया था, लेकिन उनमें से सिर्फ 41,000 को दे पाए हैं और इस पीरियड में कितने कर्मचारी सेवा निवृत्त हुए और अभी ये नौकरियां मिली नहीं हैं, सिर्फ पद भरने की प्रक्रिया ही चल रही है। कुछ पदों की तो घोषणा ही 10 तारीख को हुई है। 19,000 वे पद निकल गए और आप कह रहे हैं 13,000 पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने वर्ष 2014-15 के बजट में पेज-14, पैरा-44 में कन्ट्रोल्ड ऐटमॉस्फीयर स्टोर्ज स्थापित करने की बात कही। तो ये कितने स्टोर्ज स्थापित हुए? जो कन्सेशन इनके लिए ऑफर की थी इसके लिए पूंजी निवेश करने वाले कितने लोग आगे आए? इसी प्रकार वर्ष 2014-15 के बजट में इन्होंने वैजीटेबल पैक हॉऊस घुमारवी और नौदान में बनाने की बात कही। क्या वे बन गए? न घुमारवीं में बना और न ही नौदान में

बना। ये कहीं श्री सुक्खू जी और श्री धर्माणी जी के साथ तो मजाक नहीं किया गया? इन वैजीटेबल पैक हॉऊसेज की घोषणा हुई, लेकिन एक भी नहीं बना।

14/03/2017/1250/RG/AS/2

उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2014-15 के बजट में इन्होंने 'Apple Juice Concentrate Unit in District Shimla by HPMC at a cost of Rs. 15 Crore से लगाने की बात कही। 'उपाध्यक्ष महोदय, मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि यह सिर्फ घोषणाओं की सरकार है और घोषणा पर मैं अन्त में बात सुनाऊंगा। दूसरी बात इन्होंने वर्ष 2014-15 के बजट में Compressed Fodder Plant at Lalsinghi में लगाने की बात की। यह हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के चुनाव क्षेत्र का मामला है। लालसिंघी वहां है, मैं भी जानता हूं और वहां से सांसद रहा हूं। तो यह कम्प्रेस्ड फॉडर प्लांट न तो कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव क्षेत्र में और न ही हमारे अध्यक्ष के चुनाव क्षेत्र में यह बना। इसके अतिरिक्त वर्ष 2014-15 के बजट में Mobile Fish Market Scheme in major Towns की बात भी कही गई। मेरे ख्याल से सारी फिश भरमौरी जी मोबाईल कर गए। यानि हमें तो मोबाईल फिश मार्केट स्कीम कहीं नजर नहीं आई। ऐसी कोई भी मार्केट कहीं बनी नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, इनके ही विभाग से जुड़ी हुई एक और बात है कि वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2014-15 के बजट में कहा गया कि 45,00,000 हर्बल प्लांट्स 91 किस्म की जड़ी-बूटी proposed to be planted. तो वन मंत्री जी ये कितने और कहां लगे, आपने मुख्य मंत्री महोदय को बता देना। वर्ष 2014-15 के बजट के पेज-17 और पैरा-52 में Satellite Based Fire Alert System to protect forest from fire के बारे में कहा गया। तो वह सैटेलाईट सिस्टम कहां है और उसने कितनी आग बुझाई और वे कहां गए?

एम.एस. द्वारा जारी

14/03/2017/1255/MS/AS/1

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जारी-----

ये घोषणाएं करने के लिए बात है? वर्ष 2014-15 में पेज-17 पैरा-53 - मंकी स्टरलाइजेशन 75000 monkeys were sterilized आपने कहा 75000 लेकिन उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। नर बढ़ रहे हैं क्योंकि आप मादा की शायद ज्यादा नसबन्दी कर रहे हैं। Thereafter, how many sterilization done till date. यह फिगर भी जाए। वर्ष 2014-15 तक इनकी संख्या 75000 थी तो अब कितनी स्टरलाइजेशन कर दी है? बी0पी0एल0 परिवारों के लिए वर्ष 2014-15 में 10,700, वर्ष 2015-16 में 10,000 और वर्ष 2016-17 में 12000 मकानों की बात है। कुल कितने बन गए और टोटल एचीवमैंट क्या है?

उपाध्यक्ष जी, आपके क्षेत्र की भी समस्या है। Two biswas of land in urban areas and 3 biswas in rural areas was committed to be allotted to a landless. फ्लड में जिनका सबकुछ बह गया। उनको घोषणा कर दी कि 2 बिस्वा शहरी क्षेत्र में और 3 बिस्वा ग्रामीण क्षेत्र में देंगे। कितने लोगों को भूमि दी गई, वह आंकड़ा भी सामने आए। वे लैंडलैस लोग तो वैसे ही मकान के लिए घूम रहे हैं। वर्ष 2014-15 में मैडम के विभाग ने कहा, पेज-23 पैरा-67, 70 liters water per capita per day will be provided, water ATMs will be installed at important tourist destinations, शिमला में जो आपने जाँडिस वाला पानी पिलाया उसको कौन भूल सकता है। तीसरे दिन वी0आई0पी0 एरियाज में भी नियमित पानी नहीं मिल रहा है। ये वॉटर ए0टी0एम0 किस-किस टूरिस्ट डेस्टिनेशन में कहां-कहां पर स्थापित हुए, इसकी भी जानकारी दी जाए। इसी तरह से एम0पी0पी0 एण्ड पावर्ज में वर्ष 2014-15 में 2000 मेगावाट का टारगेट था और वर्ष 2015-16 में 1050 मेगावाट का टारगेट था। कुल कितनी बिजली जनरेट हुई? आपने चुनाव घोषणा पत्र में 5,000 मेगावाट बिजली जनरेट करने की बात कही थी लेकिन 500 मेगावाट भी नहीं हुई।

उपाध्यक्ष जी, एक प्रश्न मेरे चुनाव क्षेत्र तथा अन्य भी बहुत सारे विधायकों के चुनाव क्षेत्रों से संबंधित है। बस स्टैंड कन्स्ट्रक्शन की बात वर्ष 2014-15 में पेज-30 पैरा-86 पर की गई थी। मुझे खुशी है कि उसमें सबसे पहले मेरे हमीरपुर का नाम था लेकिन एक ईंट नहीं लगी। जो टैण्डर हमारे समय में अलॉट हो गए थे उनको कैंसल कर दिया। हमीरपुर, परवाणु, ऊना, मनाली, बद्दी, ढली और लक्कड़ बाजार शिमला में इनके निर्माण की बात थी और अब इस बजट में शिफ्ट करने की बात आ गई है। इसी तरह से सुन्नी, कुल्लू,

14/03/2017/1255/MS/AS/2

नुरपूर, नालागढ़, चम्बा और मणिकर्ण इत्यादि में कितने बने हैं ज़रा बता दें? -- (व्यवधान)--हां, एक-आधा नज़रबट्टू होता ही है। -- (व्यवधान)--मुख्य मंत्री जी भी हंस रहे हैं।

Chief Minister: I will give reply to your every question. I am listening to you.

Prof. Prem Dhumal: Thank you very much, Sir, but you can reply at the end. वर्ष 2013-14 में पेज-24 पैरा-80, Construction of tunnels. सुरंगें बनाकर हिमाचल को जोड़ देंगे। वर्ष 2014-15 में पेज़ का नम्बर 24 से 31 बदल गया और पैरा 80 का 88 हो गया लेकिन सुरंग कोई नहीं बनी। बंगाणा-धनेटा, भूभूजोत-कुल्लू, होली-उतराला, अब होली-चामुण्डा बन गया है। नाम बदलकर नया नाम हो गया है। तीसा-किलाड़ अण्डर चेणीपास, बैठे हैं तीसा-किलाड़ वाले भी(वी0वी0आई0पी0 गैलरी में बैठे श्री कुलदीप सिंह पठानिया की ओर इशारा करते हुए) There is no mention in the Budget Speech of 2017-2018. इतनी सुरंगें बननी थी। वर्ष 2013-14 से मैंशन शुरू हुई और 5वें साल में आकर उनका मैंशन ही नहीं है। क्या वे सारी सुरंगें बन गई हैं? इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा,

जारी श्री जे0एस0 द्वारा----

14.3.2017/1300/जेके/डीसी/1

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः-----जारी-----

उपाध्यक्षः धूमल जी, एक मिनट। आप और कितना समय लेंगे?

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः उपाध्यक्ष महोदय, 10-15 मिनट का समय लूंगा।

उपाध्यक्षः अब इस माननीय सदन की बैठक का समय 15 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं मुख्य मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि

"लोग गुब्बारे नहीं कि जो चंद फूंकों से फूल जाएं1

कुछ पल हवा में रह के अपने मकसद को भूल जाएं11"

लोग भूलते नहीं , लोग याद रखेंगे एक-एक घोषणा। चुनाव में जब जाओगे तो वे पढ़ेंगे कि इसका क्या बना?

मुख्य मंत्रीः हम लोग आमने-सामने होंगे और देखेंगे जनता किसको जिताती है। दूसरों की कामयाबी पर मत फूलो। हिमाचल को याद रखो। आमने-सामने आंएगे और आप लोग इलैक्शन के बाद नज़र नहीं आएंगे।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2014-15 में रोप-वेज़ की बड़ी लम्बी लिस्ट थी। कितने बन गए? City Museum and Entertainment Park in Shimla City and Children Park in every city, कहां-कहां बने हैं? वर्ष 2015-16 में "construction of godowns and warehouses to increase storage capacity of food grains, Rs. 4 crores provided" कहां गए और कहां बनाएं? गोडाऊन और वेयर हाऊसिज कहां बनें? लिफ्ट इरिगेशन यह मैं अपने साथियों पर छोड़ता हूं। डिजास्टर रिलीफ की आप बार-बार बात करते हैं कि इतने करोड़ दे दिया। वर्ष 2015-16 में 236 करोड़, वर्ष 2016-17 में 248 करोड़। धर्मपुर में भंयकर नुकसान हुआ था। घोषणा हुई कि खड्ड में बस स्टैंड बना दिया था

14.3.2017/1300/जेके/डीसी/2

इसलिए अब हम नया बनाएंगे। कहां बना, उसका क्या बना? वहां के लोगों के मकान गिरे उनको कुछ राहत नहीं मिली। मुख्य मंत्री महोदय आपने कहा कि रास्ते कहां खत्म होते हैं।

"मेले में भटके होते तो घर पहुंचा भी आता कोई,

जो घर में भटके हैं कैसे ठौर-ठिकाने आएगा "

मुख्य मंत्री जी मैं समझा देता हूं कि यदि कोई लवी मेले में गुम हो जाएंगे तो कोई ढूंढ के वहां पहुंचा देगा, लेकिन घर में ही भटके हो तो किसी ने क्या पहुंचना है, क्योंकि है तो वह घर में ही। हम इस तरफ सोचते थे कि आप और किसी को चाहे कुछ कहे या न कहे, ये करें न करें लेकिन सुधीर शर्मा के चुनाव क्षेत्र में आपकी बहुत कृपा बरसती है। लेकिन वर्ष 2015-16 में आपने कहा कि "establishment of Football Academy at Dharamshala" क्या वह स्थापित हो गई? हम बहुत खुश हुए थे और हमने बहुत एप्रिशिएट किया था जब आपने कहा कि आवारा पशुओं से, बन्दरों से, जंगली जानवरों से किसानों को राहत मिलेगी। मुख्य मंत्री खेत संरक्षण योजना में 25 करोड़ रूपए का बजट भी उपलब्ध है। अभी प्रश्न इसी सदन में हुआ था, शायद कालिया जी का था, मंत्री जी ने कहा कि स्कीम तो है लेकिन किसी लाभार्थी ने अप्लाई ही नहीं किया। जिस समस्या से सबसे ज्यादा लोग पीड़ित हैं, किसान पीड़ित हैं, उस समस्या के समाधान के लिए आपने कुछ नहीं किया।

मुख्य मंत्रीः माननीय सदस्य, आपने क्या किया?

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः हमने किया होता तो हम उधर होते। अब आपने कुछ नहीं किया तो आप लोग इधर आओगे।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी-----

14.03.2017/1305/SS-DC/1

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल क्रमागतः

उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो कहता हूं कि किसी से तो वफा की होती, न किसान से और न किसी और से, आपने तो शिमला वालों को भी ठग लिया। उपाध्यक्ष महोदय, संजौली हैलीपैड। वहां कितने हैलीकॉप्टर उतर गए? हैलीपैड बनने के लिए वर्षों नहीं लगते, महीनों में तैयार हो जाता है। कहते हैं कि टूरिज्म बढ़ाने के लिए प्राइवेट हैलीकॉप्टर के लिए

एलाऊ करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, पूरी तरह से लोगों को ठगा गया। बुरा मत मानना, कहा गया है किः-

"निन्दक नियरे राखिये, आंगन कुटी छवाय,
बिन पानी, बिन साबुन, निर्मल करे सुभाय।"

आलोचना को गुस्से में नहीं लेना चाहिए। मैं आपका धन्यवादी हूं कि आपने एक्सटर्नली ऐडिड प्रोजैक्टस के लिए, 90:10 के लिए केन्द्र का धन्यवाद किया है। परन्तु स्पैशल कैटेगिरी स्टेट का स्टेट्स भी तो रिस्टोर हुआ। 17 सैंट्रली स्पोंसर्ड स्कीम्ज़ में भी 90:10 रेशो से ग्रांट मिलती है। उसके लिए खुले मन से धन्यवाद करिये, यह भी क्या हुआ किः-

"सालों-साल की आदत छोड़ी नहीं जाती,
सालों-साल की आदत छोड़ी नहीं जाती,
इबादत भी करेंगे तो गुनाहों की तरह।"

आपने 'Ease of Doing Business' अपने अड्रैस में एक सब-टाइटल दिया है। पेज़-34, पैरा-78 है। 15 दिसम्बर, 2012 को हिमाचल प्रदेश को 'Best Destination for Investment' का गौरव प्राप्त हुआ था। आपने कई मेले लगाए, कई रोड शो किये। लेकिन जब 'Ease of Doing Business' का असैसमैंट आया है तो हिमाचल फर्स्ट पॉजिशन से गिरकर 17th पॉजिशन पर आया है। डी0पी0आरज़0 की मैं चर्चा करना नहीं चाहता। आपने खुद ही मान लिया है कि जब डी0पी0आरज़0 बनेंगी, बिल रेज़ करेंगे तो पेमैंट आयेगी और बजट की प्रिंटिंग में भी मिस-प्रिंट हो जाए तो यह ज़रा

14.03.2017/1305/SS-DC/2

चिन्ता का विषय है। इस तरफ थोड़ा ध्यान होना चाहिए। लगता है कि आपने लास्ट मिनट चेंजिज़ बड़ी करवाईं। इस करके प्रिंटर्ज़ और ऑफिसर्ज़ भी कंफ्यूज़ हो गए। पेज़-49, पैरा-125 में आप कहते हैं कि हर चुनाव क्षेत्र में 10-10 लाख रुपया देकर खेल के मैदान बनायेंगे।

चार वर्षों में कितने बने? कटासनी वाले क्रिकेट स्टेडियम का क्या हुआ, जिसका शिलान्यास 2006 में आपने किया था? एक टी0वी के ऊपर मुख्य मंत्री क्षय रोग योजना के बारे में आ रहा था। इस प्रोग्राम में आप और हम इकट्ठे गए थे और कौल सिंह जी भी साथ थे। यह तो भारत सरकार का कार्यक्रम है। इसके साथ में मुख्य मंत्री का नाम अटैच कर दिया। आपने यह भी कहा कि *"लहू बहाने का, नहीं बार-बार वक्त आता"।* बजट पेशी में कहां लहू बहाने की बात थी? यह बस खोखली घोषणाओं का बजट था। अधिवक्ता कक्ष के लिए एक करोड़ रुपये की घोषणा की। वे कहां गए अधिवक्ता गृह? सारे प्रदेश में अधिवक्ता हैं, वह कक्ष कहां बनेगा, जिस पर एक करोड़ रुपया लगेगा? बिना स्टाफ के आप घोषणाएं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह की हालत है, इसमें एफ0आर0बी0एम0 मैंटेन नहीं होगा और इसका प्रदेश को बहुत नुकसान होगा। यह कोई दलगत राजनीति की बात नहीं है। आर्थिक संकट की बात सारे प्रदेश के लिए गम्भीर समस्या है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने मुझसे पूछा कि तुमने क्या किया?

जारी श्रीमती के0एस0

14.03.2017/1310/केएस/एजी/1

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जारी----

उपाध्यक्ष महोदय, अपनी बात खत्म करते हुए एक छोटी सी बात सुनाना चाहूंगा। एक बार एक बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था। वह बहत पूजा-पाठ करता था। घर में रोज़ झगड़ा होता था कि रोटी भी खाने को नहीं मिलती। जिस भगवान की पूजा करता है वह तुझे कुछ नहीं देता। अगर भिक्षा मांगे तो खाने को कुछ मिल जाए लेकिन वह सच्चा भक्त था। वह एक दिन पूजा करके नदी में अर्ग दे रहा था तो भगवाने ने उसे एक छोटा सा शंख दे दिया कि इसको घर ले जा, इसकी पूजा किया करना, तू जो मांगेगा, वह तुझे मिल जाएगा। घर आया, उसने अगरबत्ती जलाई और कहा कि शंख महाराज हम दोनों पति-पत्नी दो दिनों से भूखे हैं। कुछ खाने को मिल जाए तो उसको दो थाली खाना मिल गया। पत्नी ने कहा कि

हमारी चारपाई भी टूटी हुई है, बिस्तर भी नहीं है, शंख से वह भी मांग लो तो वह भी मिल गया। पड़ौसी ने जब यह देखा तो हैरान हुआ कि यह क्या है, यह कैसे इतना अच्छा खाने-पीने लग गया? उसने कहा कि मेरे लिए भी एक शंख ले आना। वह बेचारा शरीफ आदमी था, उसने भगवान से एक और शंख मांग लिया। उसको शंख मिल गया और वह भी बड़ा शंख मिला। पड़ौसी क्योंकि सम्पन्न था तो उसने पूरी अगरबत्तियों का बंडल जला दिया। उसने कहा कि शंख महाराज मेरे पास एक ही कार है, दो हो जाए। शंख ने कहा बच्चा दो क्या मांगते हो तुझे चार मिल जाएगी। आदमी ने कहा कि मेरे पास एक ही कोठी है, दो हो जाए। शंख ने कहा कि दो क्या मांगते हो चार मिल जाएगी। जो मांगा डबल अनाऊंसमैंट।

मुख्य मंत्रीः उपाध्यक्ष महोदय, वह गपोड़शंख ये खुद हैं। हमने इनको बहुत अच्छा पहचाना है।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः मुख्य मंत्री जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हमने तो सुना था कि चोर की दाड़ी में तिनका लेकिन बिना दाड़ी के यह तिनका कैसे आ गया?

Chief Minister: I am clean-shaven. दाड़ी का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि गपोड़शंख आपकी सरकार रही है और आप हैं और ये बाकी (विपक्ष के माननीय सदस्य) नारदमुनि हैं।

14.03.2017/1310/केएस/एजी/2

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः उपाध्यक्ष महोदय, जिनको मैंने समझाना था, समझ गए इसलिए मैं इस कहानी को यहीं छोड़ता हूं।

मुख्य मंत्रीः धन्यवाद, गपोड़शंख जी, धन्यवाद नारदमुनि जी।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि मुख्य मंत्री जी ने आईना देख लिया है।

Chief Minister: I have heard you with all attention which you deserve.

Prof. Prem Kumar Dhumal: So nice of you. I am grateful to you that you were very patient -patient in the real sense - today.

Chief Minister: Yes. You don't realize I love you more than these people. They are all after your seat. दायें, बायें सभी ऐसे हैं जो आपके पीछे ही पड़े हुए हैं and they are worshipping some other Gods. धूमल साहब, हम आपके शुभ चिन्तक हैं।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः धन्यवाद मुख्य मंत्री महोदय, आप जैसे शुभचिन्तक हो तो बाकियों की तो जरूरत ही नहीं है और मौका आएगा जब आप मेरा ही समर्थन करेंगें।

मुख्य मंत्रीः हां, मैं ज्यादा आपके काम आऊंगा।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में जो कुछ कहा गया है, मुझे लगता है कि वह न बनाने वालों की समझ आया है, न सुनने वालों की समझ आया है और जिन्होंने पढ़ा, उन्होंने बहुत रिकॉर्ड कायम कर दिया लेकिन छोटी-छोटी घोषणाएं, अनेकों योजनाओं का आरम्भ करने की बात, ये भी जानते हैं न शुरू होंगी, न खत्म होंगी, न कोई काम होगा। यह बजट सिर्फ एक प्रयास है जो कि आखिरी बजट के तौर पर किया गया है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

14.3.2017/1315/av/ag/1

-श्री प्रेम कुमार धूमल क्रमागत

उसमें एक रिकार्ड के सिवाय जैसे मैंने शुरू में कहा कि बोलने वाले ने बहुत लम्बा बोला और सुनने वालों का बहुत धन्यवाद; जिन्होंने सुन लिया। मुख्य मंत्री महोदय, आप इस बजट को गौर से पढ़ना क्योंकि आपको स्टडी करने की बहुत आदत है। मैं जानता हूं कि आप रात के दो-दो बजे तक पढ़ते हैं। आप इस बजट को पढ़िएगा और पिछले चारों बजट

मंगवा करके फिर पांचों को कम्पेयर करना। आपको लगेगा कि आपकी हजारों ऐसी घोषणाएं हैं जो एक बार एक बजट में हुई और जब बजट स्पीच / डिसकशन खत्म हुई तो उसके बाद उनको न तो आपने पूछा तथा न किसी और ने पूछा। आपने रिसोर्स मोबलाईजेशन के लिए मंत्रियों की एक कमेटी बनाई थी जिसकी चेयरपर्सन शायद मैडम थी। अपने कार्यकाल के आखिरी साल के बजट में तो यह बता देते कि इन्होंने क्या कहा था। किसी ने कुछ नहीं किया। आपकी छत्रछाया में जो 5 साल बिताने की बात थी; आनन्दपूर्वक बिता रहे हैं। लेकिन इसमें प्रदेश का बेड़ा गर्क हो रहा है। यह बजट प्रदेश हित में नहीं है। इसमें न सोच है, न कोई कल्पना है और ही इसमें प्रदेश को आगे बढ़ाने के बारे में कुछ कहा गया है। मैं इसका विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष जी, आपका धन्यवाद।

उपाध्यक्ष : अब इस मान्य सदन की बैठक दोपहर के भोजनावकाश के लिए 2.15 बजे (अपराह्न) तक स्थगित की जाती है

14/03/2017/1420/टी0सी0वी0/ए0एस/1

सदन की बैठक दोपहर के भोजनोपरान्त 2.20 बजे अपराह्न पुनः आरम्भ हुई।

उपाध्यक्षः अब माननीय मंत्री, श्री जी0एस0 बाली जी चर्चा में भाग लेंगे।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट अनुमान वर्ष 2017-18 के ऊपर आज चर्चा शुरू हुई है, उस चर्चा में आपने मुझे भाग लेने का समय दिया, मैं इसके लिए आपका धन्यवादी हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वहीं से शुरू करूंगा, जहां से हमारे मित्र/बड़े भाई/ प्रतिपक्ष के नेता प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी ने शुरू किया कि रूपये में 12 पैसे हम स्वयं रिसोर्सिज़ से करेंगे और 88 पैसे लोन या सेंटर की स्कीम्ज़ के मार्फ़त आएंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लगा कि हम लोकतंत्र के नये सिस्टम में आ गये हैं। ये फैडरल सिस्टम है, फैडरल सिस्टम में रहते हुए केन्द्र का

टैक्सेशन में जो ढ़ांचा है, उसमें उसका कुछ हिस्सा स्वाभाविक तौर पर स्टेट्स को आता है और उसी हिस्से की हमें प्राप्ति हो रही हैं। लोन लेने की प्रथा, कोई नई नहीं हैं, लगातार प्रदेश में चाहे कोई भी सरकार रही हो, उसने ऋण लिए हैं और उससे अपना काम चलाया है। आज इस सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया है, जिससे ऐसा लगे कि हम ऐसी स्थिति की ओर चले गये हैं, जहां से वापिस लौटना नहीं होगा। ऐसी कोई बात नहीं हैं। हम लोग विद-इन-लिमिट्स जो रिजर्व बैंक की गाइडलाईन्ज हैं, जितना उसमें ऋण ले सकते हैं, उतना ऋण लिया है और बज़ट में उसको एक-एक स्कीम के लिए पूरा दर्शाया गया है

श्रीमती एन0एस0 .....द्वारा जारी।

14/03/2017/1425/ एन0एस0/ए0एस0 /1

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री ----- **जारी**

माननीय धूमल जी ने वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए जो ऋण लेना था उससे ज्यादा लिया और उसके लिए तकरीबन 5,000 करोड़ रूपये के ऐसे आंकड़े निकाले कि ऋण एक्सैस हो गया। मगर यह एक्सैस का रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीयर होना चाहिए। यह एक्सैस विद-इन लिमिट्स है। कई बार जब हम उस तरफ बैठे होते थे, चाहे वर्ष 1998 से 2002, 2007 से 2012 हो, हम भी ये आंकड़े इनको गिनाते थे कि आपके समय में लोन 25,000 या 28,000 करोड़ पहुंच गया है। यह बात बिल्कुल ठीक है कि हम इस दिशा में रिसोर्सिज़ मोबलाईजेशन कैसे करें? अब कदम उठाने का समय आ गया है। मगर उसके लिए मेरा सुझाव यह रहेगा कि माननीय प्रतिपक्ष के नेता जिनके पास वित्त विभाग बहुत लम्बे समय तक रहा है, उनको पूरा ज्ञान है कि प्रदेश के रिसोर्सिज़ कहां पर हैं और कहां से बढ़ाये जा सकते हैं? इसके ऊपर एक कन्सैस बनाएं और वह रेजोल्यूशन इस असैंबली में आए तथा उस रेजोल्यूशन के ऊपर मिलकर दोनों पार्टियां/यह सदन फैसला ले कि यहां इसको टैक्सट करना चाहिए, इस स्कीम को टैक्सट करना चाहिए और यहां से पैसे आने चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सारी हमारी रिसोर्सिज अंडर-टैप हैं। मैं

इस बात को मानता हूं। अगर हम अपने रिसोर्सिज को अच्छी तरह मोबलाईज करेंगे तो मैं समझता हूं कि डेवैलप्मेंट के कामों को करने के लिए धन की कोई ऐसी कमी नहीं है जो आड़े आएगी। यह सरकार दृढ़ संकल्प है। माननीय मुख्य मंत्री, श्री वीरभद्र सिंह जी का मानना है कि अब हम अपने रिसोर्सिज़ को भी बढ़ायेंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट साढ़े चार घंटे का पढ़ा है, इसमें हमारे कुछ मित्रों और माननीय धूमल साहब जी कह रहे थे कि सहा गया, बड़ी मुश्किल से सहा गया। यह सहा नहीं गया बल्कि हम सबने इस बजट को सराहा है कि इतनी उम्र में भी साढ़े चार घंटे तक इन्होंने खड़े होकर इसको पढ़ा है। यह बात आपको माननी पड़ेगी। इन्होंने साढ़े चार घंटे तक खड़े हो करके इसको पढ़ा है और प्रदेश को बिना टैक्स लगाये इतना बढ़िया बजट दिया है। इसमें अब इंस्टीच्यूशन्ज़ खुल

14/03/2017/1425/ एन0एस0/ए0एस0 /2

रहे हैं तो उसका भी आप विरोध कर रहे हैं कि आई.टी.आई. क्यों खुल गए हैं? अगर कहीं पर कोई चीज़ नहीं हो रही है तो उसका भी विरोध कर रहे हैं। हमने सदा यह कहा है कि अगर हम सब लोग मिल करके काम नहीं करेंगे तो कभी हम उधर हैं कभी आप इधर हैं, उसमें फिर ऐसी स्थिति बनेगी और हम सब देखेंगे। माननीय धूमल साहब यहां पर एक शेयर पढ़ रहे थे कि 'हम आज के मोह में कल को न भूल जाएं।' लेकिन यह सब हम तभी पढ़ते हैं जब हम उधर (विपक्ष) जाते हैं और जब इधर (सत्ता) होते हैं तो हमें मोह आज का ही लगता है कि किसी भी तरीके से हम सत्ता में वापिस आ जाएं। उपाध्यक्ष महोदय, कई महत्वपूर्ण ईश्यूज़ हैं जिनके ऊपर कनसैस बनाने की आवश्यकता है। अभी इस सरकार ने लगातार आम नागरिक को चाहे कितनी ही मंहगाई क्यों न हो गई हो, दालें 250 रूपये किलो हो गई हों मगर हम प्रदेश की जनता को 40, 45 और 50 रूपये किलो के हिसाब से तीन दालें देते रहे हैं। इसके साथ नमक और चीनी भी देते रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इसका अर्थ विपरीत नहीं लेना चाहिए। आपके यहां (विपक्ष) से सवाल आता है कि आटा क्यों बंद हो गया?

श्री आर0के0एस0---- द्वारा जारी ।

14/03/2017/1430/RKS/DC/1

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः ...जारी

मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहता हूं। मगर आटा इसलिए बंद हुआ क्योंकि दिल्ली से माल आना बंद हो गया। जो दिल्ली से आता है उसके लिए हम उनके धन्यवादी हैं। मैं खुले मन से जोर-जोर से चिलाकर कह रहा हूं कि जो गडकरी जी ने हमें सड़कें दीं, उसके लिए हम उनके धन्यवादी हैं। जो अच्छा काम करेगा उनके हम धन्यवादी हैं। जो धरातल के ऊपर काम हो उसकी तारीफ करनी चाहिए। हम भी उस वक्त यही कहते थे कि जो यू.पी.ए. का माल आ रहा है उसकी तारीफ करो, तो उस वक्त हमारे कई मित्र संकोच कर जाते थे। यह समय की बात है। समय की बात के साथ-साथ हम लोग स्कीमों के नाम भी बदल देते थे। उस वक्त जो प्रधान मंत्री की स्कीम आती थी उसके आगे मुख्य मंत्री जोड़ दिया जाता था। (व्यवधान)... मैं आपको हैल्थ की स्कीम के बारे में अलग से बता दूंगा। (व्यवधान)... मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता हूं। (व्यवधान)... मैं बताता हूं, हैल्थ में (व्यवधान)... बिन्दल जी शब्द वापिस लेने की आवश्यकता नहीं है। हैल्थ में स्कीमें आई, जिसमें पैसा केंद्र सरकार का था और थोड़े से पैसे आपने उसमें डाले(व्यवधान)...। प्रधान मंत्री जी का, अटल जी का नाम लिखकर कोई दिक्कत नहीं है। (व्यवधान)... आज के दिन में इसका महत्व नहीं रहा कि किसका नाम लिखते हो क्योंकि लोग बड़े तेज़ हो गए हैं। उनको हर चीज़ का पता है कि कौन सी चीज़ कहां से आ रही है। (व्यवधान)... उसको जो राइट दिया, वह राइट किसने दिया। राइट टू इनफोर्मेशन यू.पी.ए. ने दिया, कांग्रेस पार्टी ने दिया, श्रीमती सोनिया गांधी जी की सोच ने दिया, ताकि आप आर टी आई लो और अपने आप सारा पता लगा लो कि कौन सा फंड कहां से आया।(व्यवधान)... जो अटल जी ने दिया उसका धन्यवाद करने के लिए हम कुल्लू, प्रीणी गए और माननीय धूमल जी भी

वहां साथ थे। अटल जी का हृदय बहुत बड़ा है परन्तु आपकी सोच क्यों छोटी होती जा रही है।

14/03/2017/1430/RKS/DC/2

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः सोच आपकी छोटी हो रही है। आप अटल जी के नाम पर आपत्ति कर रहे हो। एक ही योजना थी 'अटल स्वास्थ्य सेवा योजना' जिसके बारे में आप बोलना चाहते थे। 'अटल वर्दी योजना' के लिए तो सारा पैसा हमने दिया है, केन्द्र ने हमें कुछ नहीं दिया था। 'अटल स्वास्थ्य सेवा योजना' 'एम्बूलैंस वाली' के बारे में आपको आपत्ति थी, जिसका नाम आपने बदल दिया। दिल तो आपने छोटा किया।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः उपाध्यक्ष महोदय, मैं तथ्यों पर आधारित बात करुंगा, जोकि मेरे विभाग से संबंधित है। जो वर्दी योजना थी, उसमें जो उस समय के मंत्री थे, वे इस समय माननीय सदन में उपस्थित नहीं हैं। वर्दी योजना में 100 करोड़ रुपये की पेमैंट हमारी सरकार के समय में हुई परन्तु मैंने इस बात का जिक्र आज तक नहीं किया। मैंने इसके बारे में एक बार भी नहीं कहा कि यह अटल वर्दी योजना का पैसा है(व्यवधान)... ।

Deputy Speaker: Please, let him speak.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः उपाध्यक्ष जी, सच्चाई कड़वी होती है। मैं बजट के ऊपर बोल रहा हूं, Budget is very important.

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

14.03.2017/1435/SLS-DC-1

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री...ज़ारी

अगर ऐसी ही चर्चा चलती रही तो कनसैनसस कैसे बनेगा? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि यह डैफिसिट का बजट है। यह भी ठीक है कि यहां पर माननीय धूमल जी ने कई आपत्तियां जताई हैं। मगर उसके साथ जो अच्छी बातें हुई हैं, उनका कहीं नाम नहीं लिया गया है। जो काम हुए हैं उनको उलटा दर्शाने का प्रयास किया गया है।

हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहे हैं। आपने कहा कि इन कॉलेजों में बच्चे नहीं हैं; एम.टैक. में बच्चे नहीं हैं। ...(व्यवधान)...मैंने आंकड़े दिए हैं। लेकिन वह कौन-सा एम.टैक. है? मैंने उस दिन भी कहा था कि कृपा करके इसके ऊपर राजनीति न करें। धूमल साहब, आप तो प्रोफ़ेसर हैं। मैंने कहा कि एम.टैक. की वही सीटें खाली हैं जो प्राइवेट कॉलेजिज में हैं। अब आप स्वयं पता लगा लो कि प्राइवेट कॉलेज कब दिए गए। अगर हम क्वैलिटी के ऊपर काम नहीं करेंगे तो सारी सीटें खाली रह जाएंगी। सीटें किसकी खाली हैं? प्राइवेट इंस्टिच्यूशन्ज की। मैंने अपने समय में कोई प्राइवेट इंस्टिच्यूशन नहीं दिया। यह पहले के ही खुले हुए हैं। हम इनको भी स्ट्रैंथन करना चाहते हैं। They are part and parcel of the system. मगर कृपा करके इनका राजनीतिकरण न करें। जहां-जहां सरकारी संस्थान खुले हैं, वहां पर जितने भी ITIs हैं, उनमें तकरीबन 75 प्रतिशत् से ऊपर सीटें भरी हुई हैं। जो कुछ ट्रेड हैं, जैसे कि एंबराइड्री, उसमें ज्यादा बच्चे ज्वॉयन नहीं कर रहे हैं। हम उसको फेज़ आऊट कर रहे हैं और नए कोर्सिज लेकर आ रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने 2 नए इंजीनियरिंग कॉलेज खोले हैं जो शुरू हो गए हैं। एक ज्यूरी में और दूसरा नगरोटा में है। इसके अलावा एक गवर्नमैंट फार्मेसी कॉलेज, 5 गवर्नमैंट पोलिटैक्निक, 34 गवर्नमैंट आई. टी.आईज., इंडियन इंस्टिच्यूट ऑफ मैनेजमैंट, IIIT, CIPT,RBTI; यह सारे संस्थान जो खोले हैं, यह चल रहे हैं। इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो नहीं चलेगा। किसी भी संस्था को बड़ा

14.03.2017/1435/SLS-DC-2

होने में और उसमें परफैक्शन आने में समय लगता है। लेकिन यह संस्थान शुरू हो चुके हैं। IIM सिरमौर में बना है, IIIT ऊना में बना है, CIPT बद्दी में बना है, RBIT शिमला में बना है, राजीव गान्धी इंजीनियरिंग कॉलेज कांगड़ा में बना है और महात्मा गान्धी इंजीनियरिंग कॉलेत ज्यूरी में बना है। इस तरह से हम लोगों ने काम किया है। अगर कोई काम हुआ है तो उसको राजनीतिक तौर पर यह न बताएं कि यह सही नहीं है। हम उसमें क्वैलिटी लाने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नमैंट इंजीनियरिंग कॉलेज की 720 में से 685 सीटें भरी हुई हैं। फार्मा कॉलेज की 100 की 100 सीटें भरी हुई हैं। गवर्नमैंट पोलिटैक्निक की 2108 में 1946 सीटें भरी हुई हैं। ।T। की 17911 में से 13290 सीटें भरी हुई हैं। यह कहना कि सीटें खाली हैं, सही नहीं है। आपको पता है कि नए संस्थान की क्या समस्याएं रहती हैं। हम लोग जहां भी जाते हैं, लोग वहां संस्थान डिमांड करते हैं और वहां संस्थान खोले जाते हैं। मगर मेरा यह भी मानना है कि आज सीनियर सेकैंडरी स्कूल या कॉलेज के बजाये ।T। का बेहतर हैं। ।T। के बच्चे को डायरैक्ट नौकरी मिल रही है, उसको इसमें कोई परेशानी नहीं हो रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्राइवेट संस्थानों में कमी आई है।

जारी ...श्री गर्ग जी

14/03/2017/1440/RG/AG/1

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री----जारी

क्योंकि प्राइवेट में बच्चों की संख्या में गिरावट इसलिए हुई है कि उनकी कैपेसिटी ज्यादा है और इन्फ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है। उनके पास इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है। पहले बच्चे सरकारी में आते हैं, उसके बाद प्राईवेट इन्स्टीटियूट में जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त माननीय प्रोफेसर साहब ने कहा कि मेरे समय में कोई बस अड्डा नहीं बना। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे हिसाब से जो बस अड्डे हमने बनाए हैं मण्डी फेज-II को पूरा किया, मण्डी फेज-I को कम्पलीट किया।---(व्यवधान)----

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : वह हमने किया।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री : अब आपने किया, उसके बारे में अब क्या बोलना, ठीक है वह आपको भी पता है। मैं मण्डी फेज-II के बारे में कह रहा हूं। हमने फेज-I के साथ फेज-II कम्पलीट किया और फेज-I की तीन करोड़ रुपये की पेमेन्ट की। इन बातों को छोड़िए। तो फेज-II कम्पलीट किया और इसकी टोटल कॉस्ट 16,22,00,000/-रुपये है। सांगला का प्रोजैक्ट पूरा किया और बस अड्डा चालू किया। Work of the following bus stands, चंबा का बस अड्डा रिकॉर्ड समय में पूरा किया और वह उद्गाटन के लिए तैयार है। निरमण्ड पर काम चला हुआ है। निरमण्ड में दो करोड़ रुपये की लागत से, ठियोग में आठ करोड़ रुपये की लागत से, सुन्नी में तीन करोड़ रुपये की लागत से, कोटली में 3,16,00,000/-रुपये की लागत से, रोहडू में लगभग साढ़े छः करोड़ रुपये की लागत से, चिढ़गांव में 70,00,000/-रुपये की लागत से, सरकाघाट में 1,37,00,000/-रुपये की लागत से, डुलैहण में 2,50,00,000/-रुपये की लागत से, अम्ब में 1,49,00,000/-रुपये की लागत से, नूरपुर में 1,38,00,000/-रुपये की लागत से, कोटखाई में अढ़ाई करोड़ रुपये की लागत से, मैड़े में 2,40,00,000/-रुपये की लागत से और करसोग में दो करोड़ रुपये की लागत से और जहां इस बार मैंने पैसे दिए हैं वह भी मैं पढ़ना चाह रहा हूं।

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : हमीरपुर के बारे में भी तो बताइए।

14/03/2017/1440/RG/AG/2

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री : सर, मैं बता रहा हूं, उसी पर आ रहा हूं। आपने विशेषकर हमीरपुर बस अड्डे के बारे में पूछा, तो हमीरपुर बस अड्डु में मैंने एक करोड़ रुपये इसी बजट में दिया है।--(व्यवधान)---जो मेरे पास उपलब्ध हैं जो मेरे पास आ चुके हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। एक करोड़ रुपये मैंने पुराने पैसों में से दिया है। Money is already sanctioned and given. मुझे इस बात का पता है कि वहां बड़ा बस

अड्डा चाहिए। मगर आपको भी पता है कि आप लोगों ने बस अड्डा दिया, लेकिन पांच साल में आप एक भी ईंट नहीं लगा सके और वही ठेकेदार थे, हमने उनको बार-बार कहा कि आओ जहां प्रोफेसर साहब कह गए हैं वहां ईंट लगाओ, लेकिन वे वहां पर एक भी ईंट लगाने को तैयार नहीं हुए और वे भाग गए। -----(व्यवधान)----री-टैण्डर कर दिया। सरकाघाट में पैसे दिए हैं और काम चला हुआ है। महाराज कर्नल साहब वहां जाकर आप देखो। वहां काम चला हुआ है।---(व्यवधान)---अच्छा पुराने वाले नोट की बात कर रहे हैं। वे नोट कुछ वापस कर दें, प्रिमीयम पर जा रहे हैं। मैं यह कह रहा हूं कि आपका बस अड्डा बहुत महत्वपूर्ण है। 15 बस अड्डे आपने गिनाए, हम उनको पी.पी.पी. मोड पर तीन बार लेकर आए। 3-4 बार टैण्डर कर दिया, कोई आकर इनवेस्टमेंट नहीं करता क्योंकि हमने ऐटमॉस्फीयर ऐसा क्रियेट किया। मकलोडगंज का बस अड्डा बढ़िया बन रहा था, लेकिन वहां उसको रोकने का प्रयास किया। अब वह रुका हुआ है और डिस्प्यूट में है। इसलिए ठेकेदार आते नहीं हैं। अभी मैंने चिन्तपुरनी का दिया, तो आज भी मैंने बस स्टैण्ड का श्री नरेन्द्र जी को उत्तर दिया है। जब हम लोग आपस में तनातनी करेंगे, तो कोई भी इनवेस्टर नहीं आएगा और चिन्तपुरनी का जिसको दिया है उसने दो महीने में उसका 20% काम कर दिया। अगर काई इनवेस्टर आएगा, अगर उसको लगेगा कि इनवेस्टमेंट में मुझे कुछ रिटर्न मिल रही है,

एम.एस. द्वारा जारी

14/03/2017/1445/MS/AG/1

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री मंत्री जारी--------

तभी वह आएगा अदरवाइज नहीं आएगा। हम कोशिश कर रहे हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं हमीरपुर, ऊना और धर्मशाला के बस स्टैंड्ज को अगले 2-3 महीने में चालू करके जाऊं। -(व्यवधान)-बजराडू के लिए पैसे दे दिए हैं। क्या मैं पढ़कर सुना दूं या मैं सारे ही पढ़ देता हूं? बजराडू के लिए 50 लाख रुपये दिए हैं। नहीं तो आप मुझसे पर्ची ले जाओ। मैं यह बात ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। -(व्यवधान)-मैंने आपको उस दिन भी कहा था, फिर आप बार-बार पूछते हो। हमीरपुर बस स्टैंड के लिए 1 करोड़ रुपया दिया है। चुवाड़ी,

दुलेहड़, पधर और घुमारवीं के लिए पहले ही पैसे चले गए हैं। -(व्यवधान)-नरेन्द्र जी, मैं आपके वहां आऊंगा। आप सुझाव दीजिए कि क्या करना है। मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूं। जहां आप बोलेंगे वहां लगाएंगे। मेरा यह मानना है कि एक अच्छा काम हो जिससे लोगों को सुविधा हो और इसके लिए हम यह प्रयास कर रहे हैं। मगर जो अच्छा काम हो कृपा करके उस पर कटाक्ष करने की बजाए कुछ अच्छा बोल दिया करो। -(व्यवधान)-

उपाध्यक्ष जी, यहां पर ट्रांसपोर्ट नगर की बात की गई। ट्रांसपोर्ट नगर के लिए हमने पैसे रखे हैं। बद्दी-बरोटीवाला के पैसे दे दिए हैं। हमीरपुर में मैं तीन-चार बार गया। वहां जमीन ही उपलब्ध नहीं होती है। अब जमीन नदौन में उपलब्ध हुई है तो मेरे पास परसों पी0सी0सी0 प्रेजिडेंट आए हुए थे कि नदौन में मत बनाओ। अब मैंने हर चीज जमीन के ऊपर ही बनानी है। अगर मैं इसको नगरोटा ले जाऊंगा तो आप बोलोगे कि नगरोटा ले गए। -(व्यवधान)-मैं उधर अग्निहोत्री जी की तरफ देख रहा हूं। मैं इनसे अलग से बात करता हूं। मैं यह रिकॉर्ड पर बोल रहा हूं कि मैं इनसे बात करता हूं। मगर बात यह है कि हम लोग जगह भी नहीं देना चाहते और बनाना भी चाहते हैं। अभी हमने पी0पी0पी0 मोड में काम किए हैं। अगर आपके पास भी कोई कॉन्टैक्ट में हैं तो कृपा करके बोलें कि वे काम करें। हमने चिन्तपूर्णी वाला चार बार ऐडवरटाइज किया फिर चौथी बार एक आदमी आया और हमने यह कैबिनेट में जाकर करवाया है। किसी तरीके से जाकर के दिया। इसलिए आपसे निवेदन है कि ऐसा वातावरण बनने दें कि कम-से-कम

14/03/2017/1445/MS/AG/2

हमारे काम चालू हो सकें। जब इन्वैस्टर्ज बाहर से आएंगे तभी उनका विश्वास बढ़ेगा और यहां पर वे पी0पी0पी0 मोड में काम करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं इस बात में नहीं जाना चाहूंगा कि संस्थान लगातार खुल रहे हैं। इस बजट में दर्जनों पी0एच0सीज0 और सिविल अस्पताल खुले हैं। इसी तरह से टाण्डा मेडिकल कॉलेज का स्तर बढ़ा है और आई0जी0एम0सी0 में भी काम हुआ है। यहां शिमला के पुराने बस अड्डे के पास स्थित दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल का भी काम हुआ है। अच्छी बात है। -(व्यवधान)- Government is in continuity. कोई फाऊंडेशन स्टोन

रखता है। अगर आप मुझे पर्सनली कहें तो मैं इसके हक में नहीं हूं कि फाऊंडेशन स्टोन रखे जाएं। आप उद्घाटन करो ताकि आपको पता चले कि यह काम हमने पूरा कर दिया।

इसके अतिरिक्त जो 80 वर्ष से ऊपर के 70 प्रतिशत से ज्यादा अपंग लोग हैं उनकी पैंशन 1200/-रुपये कर दी है।

जारी श्री जे0एस0 द्वारा----

14.3.2017/1450/जेके/एएस/1

खाद्य, नागरिक एवं आपूर्ति मंत्रीः-----जारी----

आपने स्किल डवैल्पमैंट में सैंकड़ों-करोड़ों रूपए खर्च कर दिए। यहां पर अपने डिपार्टमैंट्स की बात कर रहा हूं। माननीय धूमल साहब ने यहां पर बात की, हमने नेरवा और भरवाड़ में, एक चम्बा में, एक बिलासपुर में गोडाऊन बनाए भी हैं और टैण्डरिंग भी इनकी चालू है। हमने तकरीबन 4400 और 3300 गोडाऊन के टैण्डर लगाए हुए हैं। 3300 के सिद्धपुर और राजगढ़ के लिए लगाए हुए हैं। नेरवा, भरवाड़, चम्बा और बिलासपुर की टैण्डरिंग हो गई है, इनके ठेके दिए जा रहे हैं। एक गोडाऊन में जो capacity building of Civil Supplies Godowns प्रोफैसर साहब ने कई इश्यूज उठाए थे मैं उनकी बात कर रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय प्रोफैसर साहब ने वर्ष 2014-15, 16,17,18,19 और 20 ये सारे के सारे बजट पढ़ दिए, लेकिन वर्ष 2007 से लेकर 2012 तक के नहीं पढ़े। वर्ष 2007,2008, 2009, 2010, 2011 व 12 के नहीं पढ़े। माननीय उपाध्यक्ष जी, यदि अच्छी तरह से प्रोफैसर साहब नज़र उठाएं तो जो यहां बजट में कमिटमैंट पूरी नहीं हुई, वैसे ही उन्हीं बजटों में भी देख लें, उनमें भी कमिटमैंट्स पूरी नहीं हुई । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट के बाद और बात है। मैनिफेस्टो की बात कही। यहां पर जो बार-बार बेरोजगारी भत्ते के ऊपर चर्चा हो रही है। बेरोजगारी भत्ते ने सब को चित्त कर दिया है। आप सारे के सारे उससे मूर्छित हो गए हैं। मुझे इससे राजनीति नहीं करनी है। जब मैं वर्ष 1998 में चुन कर यहां आया था तब भी मैंने यह बात कही थी और इस हाऊस का रिकॉर्ड है। वर्ष 2012 की

मेरी स्पीच निकाल लें। प्राईवेट मेम्बर डे पर मैं रेज्योल्युशन लेकर आया था। धूमल साहब यहां पर बैठे हुए थे कि ये सरकार एक ठोस नीति बनाए जिसमें बेरोजगारों को रोजगार मिल सकें। उस वक्त ध्वनि मत से कहा कि नहीं, इसको फाड़ दो, काट दो तब आप विपक्ष की कुर्सी पर पहुंचे। उसमें मेरी अन्तिम लाईन यह थी और उस समय माननीय अध्यक्ष, श्री तुलसी राम जी यहां पर बैठे हुए थे। मैंने तुलसी

14.3.2017/1450/जेके/एएस/2

राम जी को कहा कि मुझे बोलने दो। ये अन्तिम कील होगी इनके कोफिन में और आपके हुई। आप लोग उधर विपक्ष में पहुंचे। ये मेरी स्पीच का पार्ट है। यदि आपकी नीयत ठीक है तो आपकी नीति भी ठीक होगी। हमने डेढ़ सौ करोड़ रूपए रखा। प्रोफैसर साहब ने कहा 8 लाख 20 हजार लोग होंगे तो 82 करोड़ रूपए देना होगा। हमारा मैनिफेस्टो आपने नहीं पढ़ा। एक दिन लाए जरूर थे। उसमें हमने कहा कि 2 लाख की लिमिट होगी। प्लस टू से ऊपर के बच्चों को दिया जाएगा। 18 से 35 साल के बच्चों को दिया जाएगा, जो कि मैनिफेस्टो का पार्ट है। हम देंगे। हम वचनबद्ध हैं।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी------

14.03.2017/1455/SS-AS/1

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री क्रमागतः

यह बेरोजगारों का अधिकार है और उनको मिलेगा, हरगिज मिलेगा और आपके सामने मिलेगा। आप लोग बाहर रहेंगे, हम लोग फिर सत्ता में आयेंगे और बेरोजगार हमें यहां बिठायेंगे। --(व्यवधान)-- आप मेरी बात सुनिये। आपको बेरोजगारों की इतनी चिन्ता क्यों हो रही है? आपको इतनी चिन्ता क्यों हो रही है कि बजट जो देंगे वह कहां से देंगे। अगर उनको 200 करोड़ रुपया भी देना पड़ेगा, तब भी देंगे। 250 करोड़ रुपया भी देना पड़ेगा,

तब भी देंगे। इसके लिए बजट में 150 करोड़ का प्रावधान किया है। वह उनको देंगे। ऐसा है प्रधान मंत्री जी से पूछना, जिन्होंने कहा था कि मित्रों ढाई करोड़ नौकरियां देंगे। कहां गईं? हम देंगे और वचनबद्ध हैं देने को। आपके सामने देंगे और गांव में जा-जाकर उनसे पर्चे भरवायेंगे। आप क्यों चिन्ता कर रहे हो? गांव-गांव में जायेंगे, उनसे पर्चे भरवायेंगे और बेरोजगारों की सेवा करेंगे। आप भी करो। आपको भी मौका मिला है, आप भी जाना और उनके कागज़ भरवाओ। 2 लाख से कम इन्कम के कितने लोग हैं, उनके पेपर भरवाओ और आप लोग जा कर काम करो। आपको उस काम में हम लगायेंगे। --(व्यवधान)-- ऐसा है, उपाध्यक्ष जी, जो महेश्वर सिंह जी कह रहे हैं, पर्चे मैं नहीं भरवाता हूं। पर्चे भरवाने का काम डिपार्टमैंट करता है। --(व्यवधान)-- ऐसा है, मेरा मुंह बंद रहने दो। मैं ऐसा नहीं करता हूं कि बुकिंग पर रखूं और उसको फिर कंट्रैक्ट पर भी न रखूं और सीधा कंट्रैक्ट पर ले जाऊं । यह मैं नहीं करता हूं। 1600 से 3000 बसें की हैं और आज पूरे देश में हिमाचल का जो फ्लीट है वह यंगैस्ट फ्लीट है। आपको खुशी होनी चाहिए कि माता रानी और देवी-देवताओं की कृपा से कोई बड़ा एक्सीडैंट नहीं हुआ क्योंकि फ्लीट अच्छा हुआ है। आप भी मन से मानते हैं, सब मानते हैं और बहुत ज्यादा बसें बढ़ी हैं, हर जगह सेवा दे रही हैं। मैं अपने को क्रैडिट नहीं लेता हूं। मान लिया महाराज कि 800 कुछ बसें आपकी आई हैं परन्तु जो 1200 बसें मैंने डाली हैं, उनका भी तो नाम लो। आपकी सिर्फ 800 बसें आई हैं और वह भी कांग्रेस के टाइम पर। मनमोहन सिंह जी, कमलनाथ जी ने वह किया। उसके बाद जो लास्ट की किस्त रह गई थी, उसके लिए वैंकेया नायडू जी को मिला। उन्होंने बहुत बड़ा हृदय रखते हुए कहा कि बिल्कुल ले कर जाओ तो मैं उनका भी धन्यवादी हूं। आपको

14.03.2017/1455/SS-AS/2

इससे तकलीफ तो नहीं हुई। जो सड़कें गडकरी जी ने दी हैं मैं उनका भी धन्यवादी हूं। अगर मोदी जी कुछ और देंगे, उसके लिए भी धन्यवादी होंगे। जो अच्छा काम करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे, बड़े दिल से करेंगे। ए0आई0आई0एम0 नड्डा जी को बोले, वे खुलवाएं। मेरा तो कॉलेज भी रूकवा दिया है। मेरा कॉलेज नहीं बन रहा। यह क्या राजनीति

है? धूमल साहब, आप इसमें कुछ करवाओ। आप कृपा करके करवाईये, मैं हाथ जोड़ रहा हूं। हमने एग्रीमैंट कर दिया, सब कुछ कर दिया तो मेरा फाउंडेशन स्टोन क्यों नहीं होने दे रहे? --(व्यवधान)-- लैंड ट्रांसफर होकर टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमैंट के नाम ही होनी है। वह मेरे नाम है। --(व्यवधान)-- जनाब, हो गई, कुछ क्लीयरैंस की ज़रूरत नहीं है। ऑन रिकॉर्ड मिनिस्टर बोल रहा है। मेरे खिलाफ प्रिवीलेज़ ले आना, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, अपनी ज़रा नॉलेज बढ़ा लो। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि हमारे नाम पर है जगह और हम एग्रीमैंट साइन करने को हैं। I am talking about the Hydro-Engineering College. मैं अपनी बात करता हूं। ऐम्ज़ इनके और नड्डा के बीच की बात है। जब तक नड्डा जी सैंटर में मिनिस्टर हैं तब तक ऐम्ज़ का फाउंडेशन स्टोन नहीं होना, मैं क्या करूं। वह आपकी और नड्डा की राजनीति है। मैंने क्या करना उसमें? नड्डा जी उसे लाएं और जल्दी-से-जल्दी करवाएं। देखिये आई0आई0एम0 लग गया, क्लासें चालू हैं। ट्रिपल आई0टी0 लग गया, क्लासें चालू हैं। सी0आई0पी0ई0टी0 लग गया, क्लासें चालू हैं। मेरे डिपार्टमैंट की बात करो। जो मेरे पास डिपार्टमैंट है, वह मैंने चला दिये। हम नड्डा जी से भी रिक्वैस्ट करेंगे कि ऐम्ज़ का फाउंडेशन स्टोन जल्दी-जल्दी कराएं,

जारी श्रीमती के0एस0

14.03.2017/1500/केएस/एएस/1

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री जारी----

ताकि लोगों को सुविधा मिल सकें। आई.आई.एम. में फोरैस्ट एक्ट नहीं लग रहा। तो आई.आई.एम. में वहां पर कभी भी कंस्ट्रक्शन शुरू हो सकती है, हमने गवर्नमैंट ऑफ इंडिया को लिखकर भेज दिया है। मेरे विभागों में, मैं इस बात को मानने को तैयार हूं, मैंने पहले ही कहा कि फैडरल सिस्टम है और एक दूसरे के बिना काम नहीं हो सकता। जो चीज़ आप अच्छी करते हैं, उसके बारे में हमें तारीफ करनी चाहिए परन्तु जो कार्य वीरभद्र

सिंह जी अच्छा करें, कांग्रेस सरकार अच्छे कार्य करें, उनके बारे में दबे मन से ही कह दो कि अच्छा कर रहे हैं। मुझे याद है कि एम.एल.ए. फंड को 20 से 30 लाख तक करने के लिए हम धूमल साहब के पास कई बार गए थे, तब यह नहीं हुआ लेकिन अब यह 1 करोड़ 10 लाख हो गया, इस बात के लिए ताली मारो। लेकिन आप नहीं मारोगे। हां, हमें पता है कि यह भी हमारे खिलाफ़ ही लगना है लेकिन उसके बावजूद भी बड़ा दिल करके आपको दे दिया और यह भी कहा कि महिला मण्डलों में बांट दो।

उपाध्यक्ष जी, इस सरकार ने बहुत बढ़िया बजट दिया है, जिसमें मज़दूर का, किसान का, नौजवान का, पैंशनर का, बागवान का और कर्मचारियों का पूरा ध्यान रखा गया है। ट्रांसपोर्टरों को बेरोज़गारों के लिए नए रूट खोले हैं और रिसोर्सिज़ मोबलाईजेशन की बात की गई है। मुझे लग रहा है कि विपक्ष के साथियों को यह लगना शुरू हो गया है कि हम लोग सत्ता में नहीं आएंगें लेकिन हमें वित्तीय प्रबन्धन अच्छी तरह करना आता है। हमने यह बजट इस हिसाब से बनाया है कि अगले पांच साल भी हम आएंगें और वित्तीय देनदारियां हम ही करेंगें। इसलिए हम उसकी पूरी तैयारी करके आए हैं कि रिसोर्सिज़ कहां से आने हैं। उपाध्यक्ष महोदय, बेरोज़गारों को माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो एक सम्मान राशि दी है, जो बच्ची गांव में पोस्ट ग्रेजुऐशन करके बैठी थी, उसने टैस्ट देने जाना है, इन्टरव्यू देने जाना है, अपने कार्ड में सिम डालनी है, कहीं इंटरनैट पर बैठकर देखना है कि कहां-कहां पर पोस्टें खाली है, इन्टरव्यू के लिए

14.03.2017/1500/केएस/एएस/2

किताब लेनी है, इन सब के लिए उसको एक हजार रुपया काफी होगा क्योंकि गरीब आदमी के लिए एक हजार रुपया काफी है।

हंसराज जी, गांव में जब जाओगे, इस चीज़ का पता लगाना, आपको जब बेरोज़गार मिलेंगें, मुझे पता है कि कैसे-कैसे मैनेजमैंट करने का आप प्रयास कर रहे हैं मगर कृपा

करके बेरोज़गारों पर राजनीति न करें। बेरोज़गारों को अपना काम करने दें और जो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बढ़िया काम किया है, उससे मैं समझता हूं कि एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार 2017 के चुनावों में दोबारा से सत्ता में आएगी और दोबारा से लोगों की हम सेवा करेंगें और बेरोज़गारों को इससे ज्यादा सुविधा देने का प्रयास करेंगें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का पुरजोर समर्थन करते हुए, जैसे मैंने कहा 20 सालों के जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट दिए हैं, उनमें से यह सबसे उम्दा और बढ़िया बजट है। उपाध्यक्ष जी, आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

14.03.2017/1500/केएस/एएस/3

उपाध्यक्षः अब डॉ0 राजीव बिन्दल जी चर्चा में भाग लेंगें।

डॉ0 राजीव बिन्दलः माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो साढ़े चार घण्टे में अपने जीवन का 20वां बजट प्रस्तुत किया, उसके ऊपर बोलने के लिए आपने समय दिया, आपका आभार।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

14.3.2017/1505/av/डीसी/1

डॉ0राजीव बिन्दल---------- जारी

माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया उसकी माननीय बाली जी ने बड़े भारी मन से प्रशंसा की मगर उस बजट की हालत क्या है? ये बोलते हैं कि बहुत अच्छा बजट है और 20 साल का सबसे बढ़िया बजट है तो बाकी बजट्स का क्या हाल होगा? आपकी किताब *ऐक्सप्लेनेटरी मैमोरैंडम* (---व्यवधान---) बाली साहब, सुन लेना। (---व्यवधान---) उस किताब का पृष्ठ 39 यह कहता है कि पूरे बजट का 31.5 प्रतिशत आप सैलरी पर खर्च कर रहे हैं। उस बजट का 13.83 प्रतिशत पेंशन, 9.78 प्रतिशत इन्ट्रस्ट पे करने के लिए, मैंटीनैंस पर 6.46 प्रतिशत, लोन री-पे करने के लिए 9.93 यानि 10 प्रतिशत

और सब्सिडी के लिए 2.903 प्रतिशत खर्च कर रहे हैं। (---व्यवधान---) बजट की ही बात हो रही है। आपने बजट की बात तो की ही नहीं और पूरे बजट का लगभग 75 प्रतिशत आपने केवल इन्हीं चीजों पर खर्च किया है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो आपको किताब सप्लाई की और जो आपने नहीं पढ़ी है, यह उसकी हालत है। (---व्यवधान---) 5-7 साल पहले पढ़ा होगा । उपाध्यक्ष जी, पैसा तो बचा ही नहीं और *ढींगे हांक* रहे हैं कि बहुत बढ़िया बजट है। उसमें पैसा है नहीं, जितना पैसा है वह सारा-का-सारा सैलरी, री-पेमैंट, इन्ट्रस्ट इत्यादि पर खर्च हो रहा है। उसके बाद अभी तो लाखों लोग लाइन में खड़े हैं जिनके मेडिकल बिलों का भुगतान नहीं हुआ है और जिनको पेंशन नहीं मिली है। यह हालत अभी-अभी सरकार की बजट के अंदर प्रस्तुत की है। यह साढ़े चार घंटे के अंदर जो बजट बोला उसकी हालत साढ़े चार मिनट के अंदर बाहर निकल करके आती है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने सस्टेनेबल डवैल्पमैंट के बारे में कहा। मैंने उसी समय इग्जैक्ट शब्द नोट किए हैं। क्या यह सस्टेनेबल डवैल्पमैंट है? हिमाचल प्रदेश के ऊपर 45 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है। इसके अतिरिक्त 10 प्रतिशत हम इन्ट्रस्ट के ऊपर खर्च कर रहे हैं तथा 10 प्रतिशत री-पेमैंट के ऊपर खर्च कर रहे हैं, इसको सस्टेनेबल डवैल्पमैंट कहेंगे। फिर कह रहे हैं कि हम 20वां बजट दे रहे हैं। यहां पर कहा गया कि मार्वैलस प्रोग्रैस हुई है। मैंने उसी समय इग्जैक्ट शब्द नोट किए और वह नोटिंग यहां मेरे पास है। अनपेरेलल्ड प्रोग्रैस अगर बजट का हिसाब देखें

14.3.2017/1505/av/डीसी/2

तो घाटा बढ़ता जा रहा है। तनख्वाहें बढ़ती जा रही है, पेंशन बढ़ती जा रही है, कर्ज बढ़ता जा रहा है और मेडिकल बिलों का भुगतान नहीं हो रहा। पेंशन समय पर नहीं मिल रही। *अनपेरेलल्ड प्रोग्रैस* और उसकी प्रशंसा माननीय बाली जी कर रहे हैं। प्रोग्रैस क्या है? पूरे तीन पेज भरे हैं और बाली जी ने भी कहा है कि संस्थान खोले हैं। स्कूल खोले हैं मगर मास्टर, चपड़ासी, वॉटर करियर, कमरा, मैदान इत्यादि कुछ नहीं है। अस्पताल खोले गए मगर डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्स इत्यादि कोई नहीं है। तहसीलें खोली गईं मगर

तहसीलदार और दूसरा स्टाफ कोई नहीं दिया गया। प्राइमरी स्कूल में फट्टे लगाये और कालेज खोले। हिमाचल प्रदेश में 1.25 लाख कर्मचारियों के पद खाली हैं और आपने कहा कि हैल्थ की बहुत अच्छी स्थिति है। पता नहीं, कौल सिंह जी के साथ दोस्ती में कहां बातचीत हो गई होगी।

श्री वर्मा द्वारा जारी

14/03/2017/1510/टी0सी0वी0/ए0जी0/1

डा0 राजीव बिंदल.... जारी

केवल स्वास्थ्य विभाग में, परसों यहां पर चर्चा लगी थी, 10 हजार 25 पद खाली हैं। आपकी स्थिति नगरोटा में ठीक होगी। आप सिरमौर चलिए। मेरे पास आईये, मैं आपको दिखाता हूं , 70 परसेंट स्कूलों में मास्टर नहीं हैं। 70 परसेंट प्राइमरी हैल्थ सेंटर में डॉक्टर नहीं हैं। आप जरा शिलाई, रेणुका और नाहन वालों से पूछिये कि स्वास्थ्य संस्थानों का क्या हाल हैं। आज ददाहू की हालत यह हो गई है, 8 डॉक्टर होते थे, माननीय सी0पी0एस0 महोदय, आज 2 डॉक्टर वहां पर ढूंढकर नहीं मिलते हैं। हरिपुरधार में डिलिवरियां होती थी, वे बन्द हो गई हैं। मैं आपको बताता हूं, अभी 2 दिन पहले मैंने नोटिस भी दिया है, 12 किलोमीटर बर्फ के ऊपर चारपाई पर डिलीवरी के लिए पेशेंट को लाये, लेकिन हरिपुरधार में डॉक्टर नहीं था और वहां से उसको एंबुलेंस में लेकर नाहन आये, फिर नाहन से चण्डीगढ़ के लिए रैफर किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजगढ़ में 12 डॉक्टर होते थे, आज 2 डॉक्टर हैं और ओ0पी0डी0 सारी सोलन को रैफर की जाती है। आप बोलते हैं, बहुत अच्छा बजट है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय बाली जी कहीं चले न जायें। मैं इनको बताना चाहता हूं, एक हाई-लैवल ड्रामा हिमाचल प्रदेश में हुआ और ऐसा ड्रामा शायद देश के किस अन्य राज्य के अन्दर नहीं हुआ होगा। माननीय मुख्य मंत्री जी बोले बेरोज़गारी भत्ता नहीं मिल सकता, मिलना ही नहीं चाहिए। ये कोई वद्धावस्था/अपंग पेंशन थोड़ी ही हैं, जो मिलनी चाहिए। ये नहीं मिलनी चाहिए। श्री सुखविन्द्र सिंह (सुक्खू) जी बोले- अरे हमारा घोषणा पत्र है, ये भत्ता तो मिलना चाहिए। माननीय मुख्य मंत्री जी बोले-अनाड़ियों ने बनाया है,

घोषणा पत्र, तो दिल्ली से चलकर हमारे एक नेता जी आ गये और बोले नहीं यह घोषणा पत्र तो मैंने बनाया है। ये तो मानना ही पड़ेगा। उसके बाद इनकी गिटमिट हुई। वास्तव में मुख्य मंत्री जी और बाली जी, ये सारे लोग आपस में मिले हुए थे। ये ऐसा माहौल बनाना चाहते थे कि हम कुछ-न-कुछ कर भी दें और किसी-न-किसी तरह इस जंजाल से बाहर भी निकल जाएं। आपने जंजाल से निकलने की एक ऐसी कोशिश की कि मक्कड़जाल में खुद फंस गये। जैसा यू0पी0 में फंसे, वैसे हिमाचल में भी फंसे हैं। साहिब, ये मक्कड़जाल में फंसे और इस मक्कड़जाल में इन्होंने घोषणा करवा दी। मुख्य मंत्री जी बोले-भारी मन से बोल रहा हूं और इसके लिए 1.50 करोड़ रूपये की घोषणा करता हूं। अगस्त तक इसके लिए नियम बनाऊंगा, सितम्बर में देना शुरू करूंगा और अक्तूबर में

14/03/2017/1510/टी0सी0वी0/ए0जी0/2

इलैक्शन आ जाएगा। इस प्रकार से एक महीने के पैसे दे करके, नाखुन कटवा करके शहीद हो जाऊंगा। मेरे ऊपर कोई दोष नहीं आएगा। श्री बाली जी बाहर निकलो और यात्रा करके बताओ। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने घोषणा पत्र बनाया, आपने बेरोज़गारों के घर-घर में जा करके, लिख करके दिया कि हम आपको 1000 रूपये महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे। ये कहीं पर नहीं लिखा कि आप दो लाख बेरोज़गारों को महंगाई भत्ता देंगे। आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। आपको बेरोज़गारी भत्ते की किताब भी पढ़नी नहीं आई। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आज इस सदन में चुनौती देकर के कहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी को भी मैसिज़ चला जाएगा, फाईनेंस सेक्रेटरी भी सुन रहे होंगे, अगर आप ये 8,200 करोड़ रूपया बेराज़गारों को नहीं देते, हम लोगों को घर-घर में जाकर बताएंगे कि आप लोगों (बेरोज़गारों) के साथ इन लोगों ने धोखा किया है। अक्तूबर, 2012 में आपने अपना घोषणा पत्र जारी किया।

श्रीमती एन0एस0.... द्वारा जारी।

14/03/2017/1515/ एन0एस0/ए0जी0 /1

डॉ0 राजीव बिन्दल ----- जारी

अक्तूबर 2012 से अक्तूबर 2017 तक बेरोजगारी भत्ता दीजिए तब जा करके हमारे बेरोजगारों के लिए खर्चा पूर्ति होगी।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री : आप 15-15 लाख रूपये की राशि हमारे खाते में डलवा दीजिए।

डॉ0 राजीव बिन्दल : आप उसकी चिन्ता न करें। भेज देंगे। (व्यवधान) मैं आपको आर0टी0जी0एस0 भेज रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि कभी ऐसी स्टेटमैंट नहीं आती है। उन्होंने इस किताब (बजट बुक)में कहा है। लाखों बेरोज़गारों को रोज़गार नहीं दिया गया है। साढ़े चार साल का समय हो गया है और फिर भी आपके पास अभी देने के लिए आंकड़े नहीं है। लाखों बेरोज़गारों से आपका क्या मतलब है? बताईये आपने कितने बेरोज़गारों को नौकरी दी है? माननीय बाली जी इसकी बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। सब बहुत बढ़िया है। माननीय उपाध्यक्ष जी, यहां पर कहा गया कि डिमोनीटाईजेशन ने हमारे यहां पर प्रोग्रेस रोक दी है। मैं कहना चाहूंगा कि हां, डिमोनीटाईजेशन ने कांग्रेस की प्रोग्रेस तो रोक दी है। 480 सीटों में से 19 सीटें कांग्रेस की आई हैं। टी0वी0 पर एक एडवर्टाईजमैंट आती है कि धाग-दब्बे ढूंढते रह जाओगे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कांग्रेस को ढूंढते रह जाओगे। यह तो डिमोनीटाईजेशन का असर है। यह असर अभी यहां भी आएगा, तब इसका असर आपको दिखाई देगा।

माननीय उपाध्यक्ष जी, केंद्र सरकार का पैसा 32 प्रतिशत से 42 प्रतिशत कर दिया गया है। इसमे 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जब प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी मुख्य मंत्री हुआ करते थे और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी हिमाचल प्रदेश को टैक्स रेवैन्यू शेयर का 32 प्रतिशत मिलता था और वही अब 42 प्रतिशत मिलता है। उसके बाद भी इनकी हालत यह है। नीति आयोग की आलोचना कर रहे हैं। नीति आयोग ने हिमाचल प्रदेश को विशेष दर्ज़ा दे करके 90:10 का शेयर दे दिया है। उसके बारे में नीति आयोग की आलोचना कर रहे हैं। 80-80 लाख रूपये की राशि एक-एक पंचायत को आ रही है। उसमें से कोई खर्च

14/03/2017/1515/ एन0एस0/ए0जी0 /2

नहीं हो रहा है, कोई भी काम नहीं हो रहा है, बी0डी0ओ0 के पास पैसे पड़े हुए हैं। यहां पर इस मान्य सदन में प्रश्न लगा हुआ था कि 465 करोड़ रूपये की राशि बी0डी0ओ0 के पास पड़ी हुई है और वह वहां पर इसको धूप दे रहा है। यह जो हालत है मैं उसकी थोड़ी-सी व्याख्या करना चाहूंगा।

"मर्ज़ बढ़ता गया ज्यूं-ज्यूं दवा की

कर्ज़ बढ़ता गया ज्यूं-ज्यूं कांग्रेस सरकार आगे बढ़ती गई।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट सत्र में एक पुस्तक वित्त विभाग की हमें दी गई है। वर्तमान सरकार दबादब कार्पोरेशन्ज़ बना रही है। उसके चेयरमैन, वाईस-चेयरमैन बनाये जा रहे हैं और उनको लाल बती वाली गाड़ियां दी जा रही हैं। यह किताब लिखती है कि बोर्ड और कार्पोरेशन्ज़ के पास 6359 करोड़ रूपये की राशि बकाया है। बोर्ड और कार्पोरेशन्ज़ का जो घाटा है वह हजारों करोड़ में पहुंच गया है। फिर भी इन हारे हुए लोगों को नीली और लाल बत्तियां दी जा रही हैं। ये लोग सिर पर बैठ करके उद्घाटन और भूमि पूजन कर रहे हैं। जिसका शिलान्यास हो गया उसका भूमि पूजन किया जा रहा है। यह एक नया फॉर्मूला आ गया है। एक नई कार्पोरेशन बनाई गई है और उसमें तो कमाल ही कर दिया है। पहले बोलते हैं कि हम नशा विरोधी हैं। पहले तो वे बड़े-बड़े ठेकेदार थे, पहले शराब बेचते थे लेकिन उसके बाद यही बीमारी सरकार को भी लग गई है और सरकार ने कहा कि अब हम भी शराब के ठेकेदार बनेंगे। सरकार ने एक अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक शराब की कार्पोरेशन बना दी और कहा कि अब हम शराब बेचेंगे।

श्री आर0के0एस0 ---जारी।

14/03/2017/1520/RKS/AS/1

डॉ0 राजीव बिन्दलः .....जारी

शराब बेचने के लिए टेंडर हो गया, सब कुछ हो गया। जिन ठेकेदारों को ठेका चला गया, उनको डिबार कर दिया गया। यह एक कोर्पोरेशन बन गई और सीधा रिटेल वालों को शराब बेचेगी। माननीय उपाध्यक्ष जी, इसके बीच में काफी भ्रष्टाचार हुआ। कहीं से एक पार्टी ढूंढ कर ले आए और सारे-का-सारा काम उस पार्टी को दे दिया गया। इस कोर्पोरेशन को अडिशनल चीफ सैक्रेटरी वगैरह चला रहे हैं और उनका खर्चा, तनख्वाह सरकार दे रही है। जो बिचौलिए हैं, उनकी मालामाल है। जिस शराब से करोड़ों रुपये का रेवन्यू आता था, इस साल उस शराब से सरकार को घाटा हुआ। मैं यह पूछना चाहता हूं कि किसको फायदा देने के लिए यह कोर्पोरेशन खड़ी की गई? किसको कितने करोड़ रुपये का फायदा पहुंचाया और इसमें कितने करोड़ रुपये का घाटा सरकार को हुआ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जमटा की कहानी सुनाई थी। जमटा में किसी डिपार्टमैंट का डिपू हुआ करता था। वहां पर आजकल 150 ट्रक शराब के खड़े रहते हैं। आते-जाते लोग उन ट्रकों को देखते रहते हैं। क्योंकि सरकार के गोदाम में माल उतारने की जगह नहीं है। इसलिए वे ट्रक वहां खड़े रहते हैं। ट्रक वालों की मौज है या सरकार की मौज है, पता नहीं यह क्या है? कोर्पोरेशन बनाने का एक नया धंधा इस सरकार ने खड़ा किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किसान, बागवान, बेरोजगार और कर्मचारी होते हैं। आपने इन सबको लॉलीपॉप पकड़ा दिया। आपने कहा कि बागवानों के लिए हम बहुत अच्छा करेंगे। आपने कहा- कीवी उत्पादन के लिए हम 'मुख्य मंत्री विशेष प्रोत्साहन योजना' शुरू कर रहे हैं। कीवी पैदा करने के लिए 1 मीटर X 1 मीटर का गड्ढा बनाना पड़ेगा। उसके अंदर खाद, पानी और मिट्टी डालनी पड़ेगी। जब एक साल बाद पौधा बड़ा होगा तो उसके ऊपर एंग्लारन लगाकर अंगूर की बेल की तरह उसकी बेल को चलाना पड़ेगा। आपने कहा- हम 'पौधे की खरीद के ऊपर 50 प्रतिशत सब्सिडी देंगे'। हिमाचल प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश

14/03/2017/1520/RKS/AS/2

में 2 करोड़ रुपये की सब्सिडी रखकर किसान को चुना मत लगाओ। यह बजट का प्रावधान है। कीवी के उत्पादन के लिए 4 करोड़ रुपये की सब्सिडी का प्रावधान है। बागवानों को यह कहा गया कि सब्सिडी में प्लास्टिक के क्रेट दिए जाएंगे। जब धूमल जी की सरकार थी तो 90 प्रतिशत सब्सिडी में प्लास्टिक के क्रेट बांटे गए और यह क्रेट हजारों, लाखों के हिसाब से बांटे गए। आज आपने प्लास्टिक के क्रेट पर सब्सिडी के लिए 2 करोड़ रुपये बजट का प्रावधान कर दिया। आप 2करोड़ रुपये में कितने क्रेट बांटोगे? पॉलीथीन की सब्सिडी में 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। आपने कहा- हम सेब उत्पादकों को गुणवत्ता वाली पौध देंगे। आपने वायरस पैदा करने वाले पौधे हिमाचल प्रदेश में बढ़ा दिए। जब आप फील्ड में जाओगे तो पता चलेगा कि सेब की क्या हालत है? आपने कहा- हम 'किसानों की चिंता कर रहे हैं'। दूध उत्पादकों के लिए आपने 1 रुपये की बढ़ौतरी कर दी। किसान का दूध बाजार में 35-40 रुपये प्रति लीटर बिकता है और सरकार 16, 17, 18, 19 व 20 रुपये प्रति लीटर खरीद रही है। क्या यह किसानों की चिंता है? वन विभाग के बारे में माननीय मंत्री जी ने कहा-'वनों का दक्ष प्रबंधन और योजनापूर्वक विकास कर रहे हैं'। मेरा सीधा-सीधा आरोप है कि आप वनों का योजनापूर्वक विनाश कर रहे हैं। इसके लिए मैं यहां पर फोटोग्राफ्स भी ले करने के लिए तैयार हूं। यह फोटोग्राफ्स मेरे मोबाइल के अंदर हैं। चील के पेड़ों को छिल-छिल कर उनसे बेरोज़ा निकाला जा रहा है। लैंटाना उखाड़ने के नाम पर अरबों रुपये जेब में डाला गया है। हिमाचल प्रदेश की 30-40 प्रतिशत भूमि लैंटाना के अंतर्गत चली गई है। लैंटाना के नाम पर योजनापूर्वक धांधली और भ्रष्टाचार हो रहा है। पानी के तालाब बनाए जा रहे हैं। कहां बनाए जा रहे हैं? जंगलों में बनाए जा रहे हैं। एक कहावत है कि कितने तालाब बनाए गए, सौ।

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

डॉ0 राजीव बिन्दल ...जारी

कहां बनाए? वह तो भर गए। जैसे किसी को खाली कागज़ दिखाया कि इसके ऊपर गधे की तसबीर है। बोला कि गधा दिख नहीं रहा। तो कहा कि गधा तुम्हें नहीं दिख रहा क्योंकि वह यहां से होकर चला गया है। इसी तरह से कहा गया कि आज वन विभाग में पानी रोकने के लिए डैम लग रहे हैं। न तो डैम लग रहे हैं और न कुछ और लग रहा है, न लैंटाना उखाड़ा जा रहा है, केवल योजनापूर्वक विनाश का काम हो रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, बंदरों को लेकर आजकल एक नया फार्मूला निकला है। वर्ष 2008 में माननीय प्रेम कुमार धूमल जी मुख्य मंत्री थे। उस समय वानर वाटिका की बात आई और वह बनाई गई। उस समय ये लोग इस ओर थे। माननीय बाली जी कूद-कूद कर बोलते थे कि वानर वाटिका से वानर भाग रहे हैं। ...(व्यवधान)...2008 में वह वानर वाटिक फेल थी लेकिन 2017 में वह वानर वाटिका कामयाब हो गई।

माननीय उपाध्यक्ष जी, एक कहावत है कि अंधा बांटे रेबड़ी, मुड़-मुड़ अपने को दे। जहां भी बजट में पढ़ो - स्मार्ट सिटी धर्मशाला में, केंद्र सरकार का पैसा धर्मशाला में। मैं पढ़ रहा था - टूरिज्म में 680 करोड़ रुपया धर्मशाला में। केंद्र सरकार की योजनाएं भी एक ही जगह के लिए, बाकी जगहों के लिए कुछ नहीं।

माननीय उपाध्यक्ष जी, टूरिज्म को लेकर मेरा सीधा-सीधा माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना है कि जिला सिरमौर टूरिज्म के लिए पोटैंशियल एरिया हो सकता है परंतु जिला सिरमौर में टूरिज्म विकास के लिए एक भी पैसा नहीं रखा गया है। हमारे नाहन के लिए न रखते परंतु चीफ पार्लियामैंट्री सैक्रेटरी के इलाके के लिए तो कुछ पैसा रख देते। वहां के लिए भी नहीं रखा। वह तो बोल नहीं सकते हैं। परंतु वहां के लिए टूरिस्ट जाएगा तो हमारे यहां से होकर जाएगा। हम खुद गुज़ारा कर लेंगे।

14.03.2017/1525/SLS-AS-2

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपदा प्रबंधन की बड़ी प्रशंसा की गई है। आपदा प्रबंधन की शिमला में क्या हालत हुई? थोड़ी-सी बर्फ़ पड़ी और फिर 15 दिनों तक बिजली नहीं था, पीने का पानी नहीं था। सिरमौर जिला के अंदर 25 दिनों तक सड़कें नहीं खुलीं। इस बर्फ़ के बाद गांव में अभी भी 70 परसैंट सड़कें बंद पड़ी हैं।

माननीय उपाध्याक्ष जी, पेयजल योजनाओं की चर्चा करना चाहता हूं। कहां जाएं, किस-किस को रोएं। पिछले एक साल से एक भी पाइप आई.पी.एच. डिपार्टमैंट के पास नहीं है। हम जाते हैं कि पाइप टूटी है, रिपेयर कर दो। लेकिन पाइप लगाने के लिए विभाग के पास नहीं है।

माननीय उपाध्याक्ष जी, इस सरकार में एक और बड़ा ज़ोरदार काम चला हुआ है। एक कामगार कल्याण बोर्ड है जो कांग्रेस कल्याण बोर्ड बना हुआ है। वह जगह-जगह जाते हैं, कांग्रेसियों को इकट्ठा करते हैं। कहीं सिलाई मशीन देते हैं, कहीं कुछ और देते है। कामगार कल्याण बोर्ड वोटों का प्रबंध करने के लिए कांग्रेस कल्याण बोर्ड बना है। उपाध्यक्ष जी, उन्होंने शायद आपको भी फायदा नहीं पहुंचाया होगा। (घंटी) माननीय उपाध्यक्ष जी, क्षमा करना। मैं बाली जी जितना ही समय लूंगा। उससे ज्यादा नहीं लूंगा। उतना ही देना।

माननीय उपाध्यक्ष जी, भाषा, कला एवं संस्कृति नाम से भी एक चैप्टर इस बजट में है। भाषा, कला एवं संस्कृति का पैसा सारे-का-सारा जिला शिमला और जिला किन्नौर के लिए है। सिरमौर जिला में न मंदिर है, न मस्जिद है, न गुरुद्वारा है, न ऐतिहासिक स्थल है, न पुराने टूटे-फुटे जीर्ण-शीर्ण स्थान हैं! इसलिए वहां के लिए कुछ नहीं है। फिर ये कहते हैं कि हम समान विकास कर रहे हैं। अगर हमारे यहां से कैंसर का मरीज आ जाए तो उसको 15000 रुपया नहीं मिलता लेकिन अगर शिमला जिला का कोई जुखाम का मरीज भी आ जाए तो उसको मुख्य मंत्री राहत कोष से 50000 रुपया मिल जाता है। ऐसा समान विकास हो रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह कैसा विकास है? कुछ गिने-चुने वकीलों का इस सरकार ने बहुत विकास किया है। "माले मुफ्त दिल बेरहम"।

जारी ...श्री गर्ग जी

14/03/2017/1530/RG/DC/1

डॉ. राजीव बिन्दल----जारी

उपाध्यक्ष जी, एक प्रश्न लगा हुआ है जिसका उत्तर मेरे पास है। जो कुछ जाने-माने वकील हैं उनको फीस देने के लिए बहुत सारे मामले चले हुए हैं। एक कपिल सिब्बल जी हैं, पी.एस. नरसिम्हा जी, सुनील मुरारका जी, चीमा साहब, अशोक विज जी, अभिषेक मनुसिंघवी जी जो प्रवक्ता हैं। करोड़ रुपये इनको फीस के चले गए। यह बजट कहां जा रहा है? पहले तो है ही नहीं, लेकिन जो बचा है वह कहां जा रहा है?

माननीय उपाध्यक्ष जी, माफिया की चर्चा बहुत लंबी होती है। मैं यहां सिर्फ एक ट्रांसफर माफिया की बात करना चाहूंगा। माननीय मुख्य मंत्री जी को एक सज्जन ने एक मोटा चिट्ठा बाई हैण्ड सौंपा। जब मुख्य मंत्री जी ने नहीं सुना, तो राज्यपाल महोदय को दिया, राज्यपाल महोदय ने नहीं सुना, तो शिमला में प्रैस कॉन्फ्रेस की, जब शिमला में प्रैस कॉन्फ्रेंस को किसी ने नहीं सुना, तो उन्होंने सिरमौर में प्रैस कॉन्फ्रेंस की और अब उन्होंने कोर्ट में पी.आई.एल. दाखिल की है। तो कैसे ट्रांसफर माफिया हिमचल प्रदेश में काम कर रहा है और पैसा इकट्ठा करने का काम चला हुआ है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं चन्द बातें कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। माननीय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री जी ने बहुत सारे बस अड्डों की चर्चा की। नाहन बस अड्डे में यदि चार बूंद पानी की पड़ जाएं, तो नाहन बस अड्डा पानी से भर जाता है और 6 इंच उस पानी में चलकर बस पकड़नी पड़ती है। मैं इनसे चार साल से गुहार लगा रहा हूं, लेकिन हर बार इन्होंने लॉलीपॉप थमा दिया। इन्होंने एक बार कहा कि इसको हम पी.पी.पी. मोड में बनाएंगे। लेकिन वह पी.पी.पी. मोड नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि मैंने पैसे दे दिए हैं, लेकिन वहां कुछ नहीं हुआ। यदि ये वहां की टॉयलैट में एक बार टॉयलैट होकर आ जाएंगे, तो मैं इनको आर.टी.जी.एस. करके इनके अकॉउन्ट में पैसे भेजूंगा। उसकी इतनी बुरी हालत है। मैंने प्रश्न किया जो आज ही लगा है। इन्होंने उत्तर दिया। लेकिन ये वहां जाकर बैठ गए थे कि 12.00 बज जाएं और 12.00 बज गए। परन्तु

हमारी वर्कशॉप की क्या हालत है? मैं चाहूंगा कि ये वर्कशॉप में जाकर देखें कि इतना कीचड़ और दलदल वहां है कि वहां काम करने वाला कैसे काम करते हैं? इन्होंने कहा कि दो लाख रुपये दे दिए। तो आजकल दो लाख रुपये में तो सफेदी भी नहीं होती। वहां बसें कैसे रिपेयर हो रही हैं इसका भगवान ही राखी है।

14/03/2017/1530/RG/DC/2

उपाध्यक्ष : कृपया अब समाप्त करें।

डॉ. राजीव बिन्दल : हां जी। पांच मिनट लगाऊंगा। 'अमृत' योजना के बारे में यहां कहा। हमने पहले भी कहा कि अमृत योजना के लिए नाहन का कहीं पर भी नंबर नहीं है या कहीं पर उसका समावेश नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां नेशनल हाइवेज़ पर बहुत चर्चा हुई। 65 नेशनल हाइवेज़ पूरे हिमाचल प्रदेश का भाग्य बदल सकते हैं। 65 नेशनल हाइवेज़ का पैसा लेने के लिए सरकार तैयार नहीं है और उसमें भी किन्तु-परन्तु कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां ट्युबरकिलोसेज की चर्चा कर रहे थे 'मुख्य मंत्री टी.बी. उन्मूलन कार्यक्रम।' केन्द्र सरकार की योजना है। माननीय बाली जी ने कहा, केन्द्र सरकार की योजना के ऊपर नाम रखा। आदरणीय प्रो. प्रेम कुमार धूमल जी ने केन्द्र सरकार की योजना का मुख्य मंत्री की नाम पर नाम नहीं रखा था और हमें इस बात का फख है। आज भी मेरे पास वह कागज मौजूद है 'अटल स्वास्थ्य सेवा' जिस दिन 25 दिसम्बर, 2010 को शुरू की थी और आज तक 8,76,000 मरीजों को उस सेवा ने उठाया है। मुझे इसके लिए आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी का धन्यवाद करना है जिन्होंने अटल स्वास्थ्य सेवा शुरू की। --(घण्टी)---

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया अब समाप्त करिए।

डॉ. राजीव बिन्दल : आपने कहा कि केन्द्र सरकार का पैसा है, केन्द्र सरकार का 25% और 75% प्रदेश सरकार का, ऐसी योजना है, लेकिन इन्होंने तो कोशिश की कि यह बन्द हो जाए, परन्तु यह बंद नहीं हो सकी। इनकी भरपूर कोशिश थी कि वह आगे से पीछे हो जाए, परन्तु नहीं हो सकी।

एम.एस. द्वारा जारी

14/03/2017/1535/MS/DC/1

डॉ0 राजीव बिन्दल जारी--------

आपने "अटल वर्दी योजना" का नाम बदलकर "अटल अन्न योजना" कर दिया और आप नाम बदलने की बात करते हैं? आपने "नशा मुक्त हिमाचल" की बात कि अरे, नशा मुक्त हिमाचल नहीं बल्कि यह नशा युक्त हिमाचल है। डॉ0 राजीव सहजल जी का प्रश्न संख्याः 2801 लगा था जिसमें आपने कहा कि एक साल में 2014 मामले एन0डी0पी0एस0 के आए हैं। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं दो-तीन बातें अपने विधान सभा क्षेत्र की कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्षः कृपया समाप्त कीजिए। माननीय सदस्य एक मिनट में समाप्त कीजिए।

डॉ0 राजीव बिन्दलः उपाध्यक्ष जी, मेरे यहां सड़कों की बहुत बुरी दुर्दशा है। कालाअम्ब बहुत ही महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है। कालाअम्ब से त्रिलोकपुर की सड़क का बुरा हाल है। अभी नवरात्रों के मेले में 15 लाख यात्री वहां से जाएंगे। सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है पता ही नहीं चलता है, ऐसी दुर्दशा है। कालाअम्ब में एक भी टॉयलेट नहीं है जिसमें हजारों-लाखों यात्री जा सकें यानी वहां टॉयलेट की कोई व्यवस्था नहीं है।

इसी तरह से आपने टाउन प्लानिंग की बात कही। उपाध्यक्ष जी, यह कैसा करिश्मा है कि पौंटा साहिब से नाहन की तरफ चलो तो चार पंचायत सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र की छोड़ दीं और पांचवीं पंचायत नाहन विधान सभा क्षेत्र जहां से बी0जे0पी0 का विधायक है उसमें सबसे पहले मिस्रवाला को टाउन प्लानिंग में, माजरा को टाउन प्लानिंग में, उसके बाद कोलर को टाउन प्लानिंग में और धौलाकुआं को टाउन प्लानिंग में डालकर लोगों की मुसीबतें बढ़ा दीं। मैं चाहूंगा कि जहां अन्य क्षेत्रों को टाउन प्लानिंग से बाहर निकालने की बात की है इनको भी टाउन प्लानिंग से बाहर किया जाए।

Deputy Speaker: Please, wind-up. मैं अगले वक्ता को बोलने के लिए बुला रहा हूं।

डॉ0 राजीव बिन्दलः उपाध्यक्ष जी, मैं दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

Deputy Speaker: No, I have given you 32 minutes. Just windup now. Please wind up now. I am calling next speaker if you are not winding up.

14/03/2017/1535/MS/DC/2

डॉ0 राजीव बिन्दलः उपाध्यक्ष जी, बाढ़ राहत के नाम पर मेरे क्षेत्र में भारी नुकसान किसानों का हुआ। उनको राहत के नाम पर कुछ नहीं मिला। नालका, समालका, त्रिलोकपुर और बरमा पापड़ी में कुछ नहीं मिला।

एक अपनी बात मैं आपके माध्यम से सरकार से शेयर करना चाहूंगा। मैं ट्राइबल एरिया की बात करूंगा। मेरे यहां 9500 ट्राइबल नाहन विधान सभा क्षेत्र में हैं। आपने बजट में कहा कि 9 प्रतिशत ट्राइबल के लिए पैसा देते हैं। मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि साढ़े चार साल में एक भी पैसा इन ट्राइबल्ज के लिए हमारे क्षेत्र में नहीं मिला। ऐसा कैसा भेदभाव हो गया? हमें उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। हमारे यहां ट्राइबल एरिया है। हमारे यहां ट्राइबल गुज्जर हैं उनके डेरों की बिजलियां काट दीं जबकि 20-20 साल से वहां बिजली लगी हुई हैं। फिर आप कहते हैं कि हम गरीब और ट्राइबल का कल्याण करना चाहते हैं?

उपाध्यक्ष जी, मेरी ई0एस0आई0...,

Deputy Speaker: Now I am calling Shri Rajesh Dharmani Ji to speak.

डॉ0 राजीव बिन्दलः चलो, मैं समाप्त तो कर दूं।

Deputy Speaker: No you are not doing it.

डॉ0 राजीव बिन्दलः माननीय उपाध्यक्ष जी, मुझे बोलने के लिए आपने 33 मिनट दिए, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। परन्तु एक बात है। माननीय बाली जी ने आधे दिल से इस बजट का विरोध किया है और समर्थन भी आधे दिल से किया है। मैं जो किसान विरोधी, बेरोज़गार विरोधी, बागवान विरोधी और कर्मचारी विरोधी यह बजट है इसका पूरे

दिल से विरोध करता हूं और यह सरकार बदलने वाली है। थोड़े दिनों के अंदर आप इधर आने वाले हैं और जिस तरह यू0पी0 और उत्तराखण्ड में हुआ है वैसा ही सफाया आपका होने वाला है। उपाध्यक्ष जी, धन्यवाद।

14/03/2017/1535/MS/AS/3

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः उपाध्यक्ष जी, हमारे दोस्त और हमारे विधायक श्री बिन्दल जी ने दो बातें कहीं। माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में नहीं हैं। एक बात इन्होंने यह कही कि एक व्यक्ति को कैंसर हुआ, उसको 15 हजार रुपये सहायता राशि मिली और शिमला जिले का दूसरा व्यक्ति जिसको जुकाम हुआ था उसको 50 हजार रुपये की सहायता राशि मिली। आप कृपया कैंसर के उस पीड़ित का नाम बता दें, हम मुख्य मंत्री जी से उनको पूरी राहत दिलाएंगे। इसके अलावा जिस जुकाम से पीड़ित व्यक्ति को 50 हजार रुपये सहायता राशि मिली है उसका भी नाम बता दें ताकि उससे थोड़ी-बहुत रिकवरी की जा सके। दूसरी बात बिन्दल जी यह है कि जो बात आपने मेरे नोटिस में लाई थी, मैंने 25 लाख रुपया उसकी मैंटीनैंस के लिए रखा हुआ है। क्योंकि पी0पी0पी0 मोड में ये बने हैं। आप 25 लाख रुपये जहां भी उसको लगाना है लगा लें या जिसको भी ठीक करवाना चाहते हैं करवा लें। -(व्यवधान)- उसमें दो बार रिपेयर हो चुकी है। मैं तीन बार विजिट कर चुका हूं। एक बार आपके साथ भी अगले 15 दिनों के अंदर विजिट करूंगा और उसको सुनिश्चित बनाने का प्रयास करेंगे कि वह ठीक ढंग से हो।

अगले वक्ता श्री जे0एस0 द्वारा----

14.3.2017/1540/जेके/एजी/1

उपाध्यक्षः अब श्री राजेश धर्माणी जी चर्चा में भाग लेंगे।

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राजेश धर्माणी): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा यहां इस सदन में प्रस्तुत बजट अनुमान 2017-18 के लिए किए है, मैं उसके

समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूं। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिस जोश के साथ और जिस तरीके से 4 घण्टे 27 मिनट अपने स्टेमिना व एनर्जी लैबल का प्रदर्शन किया उससे हमारे भाजपा के जो सामने मित्र बैठे हैं अपने आपको थोड़ा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आप लोगों को अपना भविष्य डार्क दिख रहा है इसलिए यहां पर जो मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपकी तरफ से बोला उसमें यह स्पष्ट झलक रहा है कि आप लोग अपना भविष्य धूमिल होता देख रहे हैं। यहां पर धूमल साहब द्वारा यह कहा गया कि यह घोषणाओं की सरकार है। बिन्दल साहब ने तो बड़े जोश के साथ अपनी वाकपटुता का परिचय दिया और यह साबित करने की कोशिश की कि सब जगह अंधकार फैला है। हम आपको दीया जला करके रोशनी में जो हकीकत है उसको दिखाने का प्रयास करेंगे। यहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी की जो स्पीच है उसमें पेज नम्बर 79 में सबसे निचली लाईन में लिखा है कि H.P. adjudged as "Best State" in the country in education and inclusive growth. पूरे भारत वर्ष में एजुकेशन और समावेशी विकास में बैस्ट डिक्लेयर हुआ है। यहां पर पर्यटक आते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अच्छी कानून-व्यवस्था है। बाकी राज्यों की तुलना में बेहतर यहां पर इन्फ्रास्ट्रक्चर है। उसी वजह से यहां पर पिछली साल 1 करोड़ 85 लाख पर्यटक हिमाचल प्रदेश में आए। अगर यह व्यवस्थाएं ठीक न हों तो शायद पर्यटक न आते। दूसरे, यदि ये अन्धेंरे में भी देखेंगे तब भी बिन्दल जी को नाहन का मैडिकल कॉलेज दिखेगा। नज़र आपकी इतनी मोटी हो गई है, हालांकि आप स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, ठीक है वह मैडिकल कॉलेज केन्द्र सरकार ने दिया। उसको मैं एग्री करता हूं, लेकिन गुलाम नबी आजाद जी उस समय केन्द्र में स्वास्थ्य मंत्री थे। उन्होंने तीन

14.3.2017/1540/जेके/एजी/2

मैडिकल कॉलेज दिए थे। (Interruption) Rs. 100/- crores for each medical college. कहते हैं कि यहां पर बड़ा कुछ केन्द्र सरकार ने किया। अगर बहुत कुछ किया

क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा प्रदेश है। यहां पर ई0एस0आई0 मैडिकल कॉलेज दिया था, जिसको नेरचौक में खोला। आप हमें यह बताएं कि उसको चलाने में भारत सरकार ने क्यों असमर्थता व्यक्त की? सिर्फ हिमाचल प्रदेश और केरल का ई0एस0आई0 मैडिकल कॉलेज चलाने से मना किया बाकी 13 मैडिकल कॉलेज ई0एस0आई0 कार्पोरेशन देश में चला रही है, जबकि उनकी शुरूआत हिमाचल के बाद हुई थी। यह भेदभाव नहीं तो और क्या है? यह आपकी फेल्योर है। आपका भेदभाव वाला रवैया है। मोदी जी बात तो करते हैं सवा सौ करोड़ देशवासी भाईयो और बहनों की, लेकिन जब बात कुछ करने की आती है तो 21 करोड़ में से 4 करोड़ मुस्लिम भाई व बहनें उत्तर प्रदेश में है एक को भी टिकट देने की हिमाकत आप ने नहीं की है। उससे पता लगता है कि कितनी समावेशी आपकी सोच है। ये आपकी उसी सोच को लेकर आपने कोशिश की है कि धार्मिक आधार के ऊपर समाज को बांटा जाए और धार्मिक उन्माद पैदा करके वोट हासिल किए जाए उसका परिणाम है जो आप यू0पी0 की बात कर रहे थे।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी...

14.03.2017/1545/SS-DC/1

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राजेश धर्माणी) क्रमागतः

यहां पर आपने देखा कि एक तरफ चार करोड़ हैं और एक तरफ 21 करोड़ हैं, इस तरीके से उनको टैरेराइज़ करके यह कोशिश की है। धूमल साहब कह रहे थे कि सिर्फ घोषणाओं की सरकार है। आप यहां पर पेज़ नं0-1 से लेकर पेज़ नं0-5 तक देखें। जो चार साल की उपलब्धियां हैं उनको यहां पर दर्शाया है। या तो आपने इनको सुना नहीं होगा या सुनना नहीं चाहते हैं या उस समय सो गए होंगे या फिर पढ़ना नहीं चाहते। आप इसको पढ़ो। अगर मैं इसको पढूंगा तो इसमें काफी टाइम लगेगा। यहां पर 21 सिविल हॉस्पिटल भी हैं। 34 सी0एच0सीज़0 हैं और 96 पी0एच0सीज़0 खोले हैं। उसी तरीके से 42 नए सरकारी कॉलेज खोले हैं। तीन मेडिकल कॉलेज खोले हैं। दो इंजीनियरिंग कॉलेज खोले हैं। 1328

नए सरकारी विद्यालय खोले या अपग्रेड किये हैं। उसी तरीके से फॉरमेसी कॉलेज खोला है। बाकी इसमें पूरा विवरण दिया है। कोई भी संस्थान खुलेगा तो वह धीरे-धीरे पूरी तरह से स्थापित होता है। ऐम्ज़, दिल्ली हिन्दुस्तान का प्रीमियर इंस्टिट्यूट है। जो वहां सुपर स्पैशलिस्ट की 18 पोस्टें हैं उसमें से 13 पोस्टें खाली हैं, जब से आपकी सरकार आई है। आप वहां पर जाकर रिकॉर्ड चैक करें। तो यह सब जगह थोड़ी दिक्कत है। यहां पर बिंदल साहब बोल रहे थे कि पोस्टें खाली हैं। जब ये स्वास्थ्य मंत्री थे तो एक प्रश्न हमने उठाया था और उस प्रश्न के जवाब में कहा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर 79 प्राईमरी हैल्थ सैंटर्ज़ ऐसे थे, जिसमें एक भी डॉक्टर नहीं था। न डॉक्टर था और न ही फार्मासिस्ट था। 46 मिडल स्कूल ऐसे थे, जिसमें कोई टीचर नहीं था। जिसमें उधार के टीचर से काम चला रहे थे। यहां पर वैसे ही बाकी महकमों की बात थी। लेकिन यह बात ठीक है कि आप इतना जोर-शोर से बोलते हैं, झूठ को भी बार-बार जोर से बोलेंगे और दूसरों को लगता है कि शायद यह सच होगा। लोगों को गुमराह करके इसी बात का आप फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं। यहां पर कहा गया कि बजट में इकोनॉमिक्स का ध्यान नहीं रखा गया और आने वाले इलैक्शन को ध्यान में रखकर बजट पेश किया गया है। बिंदल साहब, यहां पर एक दूसरी किताब दिखा रहे थे। इसको अगर आप पढ़ेंगे, यह ठीक है कि हमारा रेवेन्यू

14.03.2017/1545/SS-DC/2

डैफिशिट स्लाइटली बढ़ा है। लेकिन जो फिस्कल डैफिशिट है, पिछले साल वह -4.23 परसैंट जी0एस0डी0पी0 का था। इसमें इम्प्रूवमैंट हुई है इस समय -3.50 परसैंट है। कुल ऋण जो हिमाचल प्रदेश सरकार के ऊपर है वह पिछले साल तक 33.96 परसैंट जी0एस0डी0पी0 का था, इस बार वह थोड़ा कम हुआ है। 33.92 परसैंट है। उसी तरीके से जो गारंटीज थीं, वह भी जो हमारी रेवेन्यू रिसीट्स हैं, पिछले बार 23.84 परसैंट था। इसमें भी इम्प्रूवमैंट हुई है और इस बार 22.95 परसैंट है। तो यह हमारी इम्प्रूवमैंट हैं। यह बजट सिर्फ इलैक्शन को ध्यान में रखकर नहीं पेश किया गया है और सबसे बड़ी बात है कि रेवेन्यू एक्सपेंडीचर में बढ़ोत्तरी की है। 11,308 करोड़ 29 हजार रुपया आने वाले समय में सामाजिक सेवा क्षेत्र पर खर्च किया जायेगा। दूसरा, यहां पर बात कर रहे थे कि हमने सिर्फ घोषणनाएं की हैं। आपको मैं याद करवाना चाहता हूं कि आपकी सरकार कैसी थी। जो

फ्रंट लाइनर्ज़ हैं वे यहां से चले गए। उससे पता लगता है कि जो आप बिन्दु उठाते हैं उसका उत्तर सुनने के लिए आप लोग कितने गम्भीर हैं। आपकी सरकार के समय में जो बीमार गरीब लोग थे, उनके लिए कांग्रेस सरकार के समय में एच0आर0टी0सी0 की बसों में एक अटैंडैंट के साथ फ्री ट्रैबल करने की फैसिलिटी थी। आपकी सरकार में महेन्द्र सिंह जी उस समय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे और इनको लगा कि यह बड़ा भारी बर्डन ट्रांसपोर्ट के ऊपर पड़ रहा है और उस स्कीम को बंद कर दिया। हमारी सरकार बनते ही पहले ही दिन मुख्य मंत्री जी ने उसको चालू करने की घोषणा की है और आज बाली जी उसको कंफर्म कर रहे हैं कि वह स्कीम अब भी चल रही है और ऐसे गरीब लोगों को उसका फायदा मिल रहा है। हमारी पिछली सरकार के समय में

जारी श्रीमती के0एस0\

14.03.2017/1550/केएस/एएस/1

मुख्य संसदीय सचिव(श्री राजेश धर्माणी) जारी----

गरीब लोगों को मकान की मुरम्मत के लिए पैसे दिए जाते थे आपकी सरकार ने वह भी बन्द कर दिए थे। तो आप अन्दाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की सोच आप ले कर चलते हैं। गरीब को मारकर गरीबी खत्म करने की आपकी सोच है जो सही नहीं है। यहां पर विपक्ष के साथियों की तरफ से यह बात कही गई कि यह केन्द्र सरकार की योजना है। यह ठीक है लेकिन हिमाचल प्रदेश भी केन्द्र सरकार और भारतवर्ष का ही हिस्सा है। यहां पर जो तर्क दिया गया कि जो क्षय रोग उन्मूलन योजना है, बिन्दल जी अभी बैठे नहीं हैं। धूमल साहब ने भी और बिन्दल जी ने भी यह कहा कि यह केन्द्र की योजना है। क्षय रोग उन्मूलन योजना केन्द्र सरकार के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में भी है और हिमाचल प्रदेश में मुख्य मंत्री जी ने प्रोएक्टिव हो कर यह घोषणा की है। केन्द्र सरकार कह रही है कि वर्ष 2025 में हम टी.बी. उन्मूलन करेंगें लेकिन हिमाचल प्रदेश में उसको 2022 में खत्म करने की बात कही गई है। मैं आपका सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए यह बात कह रहा हूं कि

जितना पैसा भारत सरकार दे रही है, उससे कई गुना ज्यादा जो इन्टरनैशनल एजैन्सिज़ हैं, यू.एस.ए. व डब्ल्यू.एच.ओ. से पैसा आ रहा है, यू.एन.ओ. से पैसा आ रहा है। वह तो भारत सरकार से भी ज्यादा है तो आप क्या कहेंगें कि वह भारत सरकार की बजाय यू.एन.ओ. का एजैंडा है तो फिर आप वह बोलो अगर बजट ही डिसाईड करता है। ये इंटरनैशनल एजैंसिज़ हैं जहां से भारत सरकार से ज्यादा बजट आ रहा है। यह सब के लिए है और ग्लोबली 2035 में टी.बी. उन्मूलन के लिए टारगेट रखा गया है। यह अच्छी बात है कि उसको 2022 में खत्म करने की बात मुख्य मंत्री जी ने कही है। आप कहते हैं कि केन्द्र सरकार से पैसा आ रहा है। 90:10 की स्पैशल केटैगरी की स्टेट का दर्जा प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने दिया था। मोदी जी ने इसको छीनने का प्रयास किया लेकिन जब हम सभी ने इसका विरोध किया, उन्होंने बोल दिया था कि वहां पर अब 50:50 चलेगा। 90:10 की रेशो नहीं चलेगी लेकिन जब हमारी सरकार ने यहां से स्ट्राँगली प्रोटैस्ट किया, अपना केस स्ट्राँगली प्लीड किया तो आप लोग भी डर गए कि चुनाव आने हैं इसलिए आप लोगों को फेस नहीं कर पाएगें

14.03.2017/1550/केएस/एएस/2

इसलिए दोबारा से पुराना स्टेटस बहाल किया। (व्यवधान) मैं मोदी जी का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वे प्रधान मंत्री हैं। प्रधानमंत्री नहीं होते तो उनका नाम नहीं लेते।

Deputy Speaker: Please, don't disturb. I am not allowing him to speak. कृपया बैठे-बैठे रनिंग कमेंटरी न कीजिए। I will not allow this.

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राजेश धर्माणी): मोदी जी का नाम इसलिए भी लेना पड़ता है क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी की बजाय भक्तजन पार्टी बन गई है, आप सब मोदी भक्त है। उपाध्यक्ष जी, यहां पर एक बात कही गई कि भारत सरकार से पैसा आता है। हम आपसे यह पूछना चाहते हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी से भी आग्रह करेंगें कि यहां पर वे भी अपना डाटा दें। आपके टैलिफोन के बिल के ऊपर, मोबाईल बिल के ऊपर, बिजली के बिल के ऊपर, जो आप ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेल करते हैं, उसके ऊपर, पैट्रोल पर और

यहां तक कि रैस्टोरैंट में अगर खाना खाने जाते है, हमारी बहनें ज्वैलरी लेती है तो उसके ऊपर सर्विस टैक्स लगता है। वह सर्विस टैक्स कहां जाता है? भारत सरकार का जो रेवन्यू कलैक्ट होता है, वह कहां से आता है? वह स्टेट से जाता है। हमारे यहां पर ए.सी.सी., अम्बुजा और जे.पी. सीमेंट फैक्ट्रियां लगी हैं। उनका सैंट्रल एक्साईज़ कहां जाता है? प्रदूषण हम झेलते हैं। जो यहां पर फैक्ट्रियां लगी हैं, उनका सैंट्रल एक्साईज़ कहां जाता है? जो इन्कम टैक्स लगता है, वह कहां जाता है? वह भारत सरकार की किटी में जाता है फिर वहां से डिस्ट्रिब्यूट होता है कुछ परसेंट वे अपने लिए रखते हैं। तो यह स्टेट से ही जाता है । भारत सरकार का अपना अलग से कोई ऐसा एरिया नहीं है । वह स्टेट से ही रेवन्यू कलैक्ट होता है। उसी में से कुछ परसेंट यहां पर रीएलोकेट होता है। यह बोलना कि कोई नया काम आपकी सरकार कर रही है ऐसा नहीं है। यह सिस्टम हमारे पूर्व के नेताओं ने बनाया है। फैडरल सिस्टम है । आपको उसको मानना पड़ेगा। They are bound to oblige. They are bound to give. अगर वह टैक्स कलैक्शन करने के लिए कम्पैल करते हैं तो उसका हिस्सा लेने का हमें भी पूरा अधिकार है। इसमें कोई खैरात नहीं बांट रहे हैं।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी----

14.3.2017/1555/av/ag/1

श्री राजेश धर्माणी---------- जारी

और जब स्कूल/कालेज खोलते हैं तो आप यहां पर बोलते हैं कि रेवड़ियों की तरह बांट रहे हैं। रेवड़ियां नहीं बांटी जा रही यह भविष्य बांटा जा रहा है। यहां सब कुछ चुनाव के मद्देनजर नहीं किया जा रहा है बल्कि आने वाली जनरेशन के हिसाब से किया जा रहा है। हम अगर आने वाली जनरेशन को अच्छी ऐजुकेशन नहीं देंगे, हम यूथ का ध्यान नहीं रखेंगे। (---व्यवधान---) अभी बेरोजगारी भत्ता दिया गया उससे भी यूथ की इम्पावरमैंट होगी जिसका जिक्र बाली साहब ने भी किया है। यह सब यूथ इम्पावरमैंट के लिए है। हम अगर नैक्स्ट जनरेशन का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम उनसे क्या ऐक्सपैक्ट करेंगे कि वह हमारे से बेहतर करेगी। इसलिए नैक्स्ट जनरेशन को हायर लैवल पर ले जाने के लिए ही

यह सब कुछ किया जा रहा है। हमें इस बात का फक्र है कि पूरे हिन्दुस्तान के अंदर केवल हमारी विधान सभा में यूथ ओरिएंटिड बजट रखा गया है। शिक्षा के ऊपर, तकनीकी शिक्षा के ऊपर, मेडिकल ऐजुकेशन के ऊपर, स्किल डवैल्पमैंट अलाऊंस के ऊपर, अनइम्पलॉयमैंट अलाऊंस इत्यादि इन सारी चीजों को मिलाकर आप देखेंगे कि हमारी स्टेट में सबसे ज्यादा बजट अलोकेशन यूथ डवैल्पमैंट के लिए हुआ है।

(सभापति, श्री कुलदीप कुमार पदासीन हुए।)

इस बात का हमें जहां फक्र है वहीं आपको चिन्ता सता रही है क्योंकि आप लोगों को इससे दिक्कत होने वाली है। आप लोग प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे थे। हम यहां पर आप लोगों से यह भी पूछना चाहते हैं कि ढाई साल के अंदर मोदी साहब ने हमारी प्रदेश सरकार को कितना पैकेज दे दिया? यहां पर धूमल साहब ने एपिडा प्रोजैक्ट की बात की है। एपिडा प्रोजैक्ट जब केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और आनन्द शर्मा जी कॉमर्स मिनिस्टर थे उस समय सैंक्शन हुए थे। वर्तमान केंद्र सरकार को इस बात की शर्म आनी चाहिए कि वह पैसा भी वापिस ले लिया। हमारे प्रोजैक्ट 80-80 प्रतिशत तक कम्पलीट हो गये मगर पैसा वापिस लेने की वजह से वह काम अब अटके पड़े हैं।

14.3.2017/1555/av/ag/2

यहां पर नये सी0ए0 स्टोर सैंक्शन हुए थे उसकी अप्रूवल मिली हुई थी मगर उसको भी कैंसिल कर दिया गया। आप लोगों की सोच इस तरह की है। यहां पर एन0आर0डब्ल्यू0डी0पी0 में करोड़ों रुपये का पैसा आता था मगर अब केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय के मुकाबले उसमें 10 प्रतिशत के करीब पैसा रह गया है। आई0डब्ल्यू एम0पी0 में पैसा सैंक्शन था उस पैसे को वापिस लिया गया और उसको नहीं दिया जा रहा है। ए0आई0एम0पी0 के अंतर्गत करोड़ों-अरबों रुपये की स्कीमें सैंक्शन होती थी मगर जबसे केंद्र में आपकी पार्टी की सरकार बनी है कोई पैसा नहीं दिया जा रहा। आपकी केंद्र

सरकार ने अपने ढाई साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में कुल कितने किलोमीटर रेल लाइन बना दी? आपकी सरकार एक किलोमीटर भी नहीं बना पाई। उस पर केंद्र सरकार एक रुपया भी खर्च नहीं कर पाई। यहां पर घोषणाओं की बात की जा रही थी तो मैं कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार ने घोषणा की थी कि हर घर को पानी देंगे। आज भी हर घर के अंदर नलके नहीं लगे हैं। आपने लोक सभा चुनाव के समय जो वायदे किए थे और उनके बारे में जब पत्रकारों ने आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को पूछा कि उन वायदों का क्या हुआ तो उन्होंने कहा कि ये तो जुमले थे। आपके तो जुमले होते हैं, हमारी तरफ से जो घोषणापत्र में वायदे किए गए थे उनको पूरा करने की कोशिश की गई है। हालांकि प्रदेश सरकार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी न होने के बावजूद भी माननीय मुख्य मंत्री ने उन घोषणाओं को सिरे चढ़ाया है उसके लिए जहां हमारी सरकार बधाई की पात्र है वहीं आपके लिए यह चिन्तनीय विषय बन गया है। मुख्य मंत्री जी ने यहां पर लगभग 19हजार नई नौकरियां देने की बात कही है आपको इससे भी तकलीफ हो रही है। जब 19 हजार लोगों को नौकरियां मिलेगी तो स्वाभाविक है कि आपको राजनैतिक तौर पर मुश्किल होगी। यहां पर बजट भाषण में यह भी कहा गया है कि स्कूलों में जो आई0टी0 टीचर पढ़ा रहे हैं, जो इम्पलाइज आउट सोर्सिज के ऊपर काम कर रहे हैं उनके लिए भी पॉलिसी बनाई जायेगी और आपको उसकी भी चिन्ता हो रही है।

14.3.2017/1555/av/ag/3

सभापति (श्री कुलदीप कुमार) : माननीय सदस्य (श्री हंस राज) बैठे-बैठे कमैंट्स न करें। कृपया उनको बोलने दें।

श्री राजेश धर्माणी : माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट के अंदर सभी वर्गों का ध्यान रखा है और लगभग 30 नये इनिशिएटिव लिए गए हैं। आपको इससे दिक्कत होती है क्योंकि जब नये इनिशिएटिव लेंगे तो स्वाभाविक है कि आपको परेशानी होगी। यहां पर बिन्दल साहब सस्टेनेबल डवैल्पमैंट की बात कह रहे थे। हम अपनी सरकार का धन्यवाद करते हैं कि हमारी सरकार इसके ऊपर प्रो-ऐक्टिव होकर काम कर रही है और वर्ष 2022 तक

सारे एस0डी0जीज0 जो यू0एन0 ने तय किए हैं उन सारे टारगैट्स को पूरा करेंगे। लेकिन मैं आपके समय की भी याद दिलाना चाहता हूं। मैंने यहां पर एक प्रश्न किया था कि यू0एन0 एजैंसी ने जो एम0डी0जीज0 सैट किए थे। लेकिन उस प्रश्न का पांच साल के कार्यकाल में कोई उत्तर नहीं आ पाया क्योंकि आपकी सरकार के पास उस बारे में न तो कोई डाटा था और न ही आपने उसके ऊपर काम किया था।

14/03/2017/1600/टी0सी0वी0/डी0सी0/1
मुख्य संसदीय सचिव (श्री राजेश धर्माणी).... जारी

अब उनकी (MDGs) जगह एस0टी0जीस आये हैं और उसके ऊपर हमारी सरकार प्रो-एक्टिव होकर काम कर रही है। वर्ष 2022 तक उनको अचीव करने की बात भी यहां पर कही गई हैं। इस बजट में जो एक बहुत अच्छा स्टैप लिया गया है, वह सोशल ऑडिट करने का निर्णय लिया है। जो भी डेवैल्पमेंटल काम होगा, उसकी रिपोर्ट संबंधित पंचायत को जाएगी कि एक महीने के अन्दर कितनी प्रोग्रैस हुई और साल के अन्दर कितनी प्रोग्रैस हुई हैं। यह एक बहुत बड़ी फ्यूचरिस्टिक सोच को दर्शाता है। आप लोगों को इसको एप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन आपने तो जो विधायक निधि बढ़ाई है, उसके लिए भी धन्यवाद नहीं किया। माननीय विधायकों के पास एक रूपया भी डिस्क्रेशनेरी ग्रांट के लिए नहीं होता था। आपके माननीय विधायक श्री राजन सुशांत जो इस विधान सभा में कुछ समय के लिए रहे थे, वे डिमाण्ड करते थे कि डिस्क्रेशनेरी ग्रांट दी जाये, लेकिन आपकी सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी। हम माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि आज 5-5 लाख रूपया डिस्क्रेशनेरी ग्रांट के रूप में दिया जा रहा है। -(व्यवधान)- आप लोगों ने एक रूपया नहीं दिया। इसकी वज़ह से गरीब लोगों को जरूर फायदा मिलेगा, लेकिन आप लोगों ने उसका युटेलाइज़ सही तरीके से करना है।

सभापतिः चौहान जी, बैठे-बैठे कॉमेंट्स न करें। Let him speak, don't disturb him.

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राजेश धर्माणी): आवारा पशुओं के लिए भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने "मुख्य मंत्री खेत संरक्षण" योजना की घोषणा की थी। आपके कुछ वक्ता कह रहे थे कि इसका लोगों ने फायदा नहीं उठाया। लोग फायदा नही उठा पाये इसलिए सबसिडी 60

परसेंट से बढ़ाकर 80 परसेंट कर दी गई है और इसके लिए आपको धन्यवाद करना चाहिए। इस तरह से माननीय मुख्य मंत्री जी ने किसानों के दुख-दर्द को समझने की कोशिश की है। ये आवारा पशुओं की समस्या खत्म हो सकती थी, लेकिन आपके संगठन से संबंधित जो गो-रक्षा समितियां बनी हैं, मुझे एक सदस्य मिले जो फण्डस इकट्ठा कर रहे थे। मैने उनसे ज़िक्र किया कि आप कितना काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हम दो करोड़ सदस्य हैं। जब उन्होंने यह

14/03/2017/1600/टी0सी0वी0/डी0सी0/2

बात की तो मैंने उनसे कहा कि पूरे हिन्दुस्तान के अंदर 30 लाख आवारा पशु हैं, अगर 7-7 गऊ रक्षक एक समूह बनाएंगे तो 7 लोगों के हिस्से में एक गाय/बैल आएगा और इस सारी समस्या का हल हो सकता है, लेकिन गऊ रक्षक केवल नोट और वोट के लिए हैं। नोट और वोट इकट्ठे करने हैं तो गऊ रक्षक और अगर उनकी सेवा करने की बात है, तो उनकी सेवा के नाम से आपकी तरफ से कोई कोशिश नहीं होती हैं। हम माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ई-गवर्नेंस को लेकर फोकस किया है, ताकि लोगों को अनावश्यक रूप से अपने समय की बर्बादी न करनी पड़े और उनको घर बैठे ही ऑन-लाईन बहुत-सी सुविधा मिल सकें। उन्होंने नाबार्ड में जो 70 करोड़ की सीमा थी उसको 80 करोड़ किया है। ऐसे 30 नये इनिशिएटिव लिए हैं। जो "मुख्य मंत्री कीवी प्रोत्साहन" योजना है, डॉ0 बिंदल जी उसमें भी खोट निकाल रहे थे। कीवी में खड्ढा ही नहीं खोदना होता है, इसमें बेल चढ़ाने के लिए एंगल से जाला बनाया जाता है, उसके लिए भी सबसिडी की बात इस बजट में की है, लेकिन अगर सब जगह नकारात्मक सोच रखेंगे तो आपको सब जगह अंधेरा ही दिखेगा। यदि आप अच्छी सोच रखेंगे तो स्वाभाविक है कि आप लोग उसमें अच्छी चीजें देंखेंगे। जो बेजान पशु हैं, कई बार उनको इमरजेंसी सर्विस की आवश्यकता पड़ती है। इसके बारे में कल भी मुझे एक फोन आया कि इमरजेंसी में हम किसको फोन करें? माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि इसके लिए टोल-फ्री नम्बर लगाया जाएगा और इमरजेंसी सर्विस भी प्रोवाइड की जाएगी। यहां पर "कृषक बकरी पालक" योजना की भी घोषणा की गई है। बिलासपुर जिला में भी बकरी काफी पाली जाती है। यह पहली बार हुआ है कि बकरी पालन प्रोत्साहन के लिए योजना आई है। इससे पहले

भेड़ पालन के लिए तो योजना आती थी, लेकिन बकरी पालन के लिए कोई योजना नहीं थी। इससे हमारे नीचले क्षेत्रों को भी फ़ायदा होगा। दूसरा, मैं यह भी कहूंगा कि जो 670 करोड़ रूपये का लोन सैंक्शन हुआ है, इसमें एक प्रोजैक्ट हमारे घुमारवीं का भी है जो सोर्स लैवल ऑग्मेनटेशन टैक्निकली अप्रूव्ड हैं। भारत सरकार से भी इसकी अप्रूव्ल हो गई हैं। उसके लिए भी पैसों का प्रावधान किया जाये। उसी तरह से यहां दो स्ट्रेट मिशन, एक फूड प्रोसैसिंग और एक एग्रो फॉरेस्ट्री के ऊपर शुरू किया है। इनसे बेरोजगारी को काफी रोजगार मिलेगा और आने वाले समय के अन्दर हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ेगा।

श्रीमती एन0एस0.... द्वारा जारी।

14/03/2017/1605/ एन0एस0/डी0सी0 /1

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राजेश धर्माणी) ----- जारी

इस बजट में सभी वर्गों की पैन्शन भी बढ़ाई गई है। आंगनबाड़ी वर्कर्ज़ और हैल्परों का मानदेय भी बढ़ाने की बात कही गई है। आशा वर्करों को भी फिक्स 1000 रूपये की राशि मिनीमम दी जा रही है। हमारे मिड-डे-मील वर्कर्ज़ जो कि इग्नोर्ड होते थे, वे भारत सरकार के इम्पलायी हैं उनका मानदेय श्री प्रणब मुखर्जी जी ने 200 रूपये से सीधा 1000 रूपये किया हुआ था लेकिन अढ़ाई सालों के तीन बजट आपकी सरकार (केंद्र सरकार) ने दे दिए फिर भी उनकी अभी तक एक भी रूपये की बढ़ोतरी केंद्र सरकार ने नहीं की है।

सभापतिः माननीय सदस्य, please wind up.

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राजेश धर्माणी) : माननीय सभापति जी, मैं अपना भाषण इसी के साथ समाप्ति की तरफ ले जाता हूं और इसका पूरी तरह से समर्थन करता हूं। जो हमारे विपक्ष के सदस्य हैं, उनसे भी कहूंगा कि आप सब भी सकारात्मक सोच रखें। आप यहां पर जो डिमोनीटाईजेशन की बात कर रहे थे और अगर आपने उसका असली इम्पैक्ट देखना है तो पंजाब में देखो। वहां पर आपकी दो सीटें रह गई हैं। गोवा में भी आपकी सरकार (भाजपा) के खिलाफ हमें बहुमत दिया है।

सभापतिः माननीय सदस्य, please, no running commentary. Please keep quite.

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राजेश धर्माणी): मणिपुर में भी आपकी सरकार (भाजपा) के खिलाफ लोगों ने अपना मत दिया है। हम इनका (विपक्ष) का धन्यवाद करते हैं। (व्यवधान)

Chairman: Please keep quite. No running commentary. आप बैठै-बैठै कमैंट न करें।

14/03/2017/1605/ एन0एस0/डी0सी0 /2

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राजेश धर्माणी): अब आप विधायक बन गए हैं। हम पंजाब के लोगों का खासतौर पर धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने, मोदी जी ने जो बेतुकी सी घोषणा की थी कि हम कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, उस सपने को वहां की जनता ने धराशायी कर दिया है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की पंजाब में सरकार लाई और *** ___(घंटी)

मैं इसी के साथ सभापति महोदय आपका धन्यवाद करता हूं, जय हिन्द।

***अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

14/03/2017/1605/ एन0एस0/डी0सी0 /3

सभापति : अब श्री गोविन्द राम शर्मा जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री गोविन्द राम शर्मा : सभापति महोदय, जो बजट 10 मार्च को माननीय मुख्य मंत्री जी ने पेश किया है। मैं इस मान्य सदन में उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरे से पूर्व बहुत से वरिष्ठ सदस्यों ने अपनी-अपनी बात रखी है। लेकिन इस बजट में जो आम समाज, निम्न वर्ग के लिए खास कुछ नहीं दिया गया है। हम एक छोटे से मज़दूर से शुरू करते हैं क्योंकि

सबसे निम्न स्तर एक मज़दूर का होता है तो उसके लिए दिहाड़ी की बढ़ोतरी नाम मात्र की गई है। होना तो ऐसा चाहिए था कि उस निम्न वर्ग का विशेष ध्यान रखते और उनके दैनिक भत्ते को बढ़ाया जाना चाहिए था। इसके साथ-साथ जो ग्रामीण स्तर पर स्कूलों में रसोइये रखे हैं, उसमें बहुत से गरीब लोग और विधवा बहनें शामिल हैं। उनको आज से 7-8 साल पूर्व रखा गया था। उस समय उनको 1000 रूपये प्रति माह के हिसाब से मिलता था और आज जो उनका वेतन बढ़ाने की घोषणा की है, वह केवल मात्र 200 रूपये बहुत कम है। इसी प्रकार जो अन्य पैन्शन योजनाएं अपंगों के लिए, विधवाओं के लिए या बुजुर्गों के लिए उसमें भी नाम मात्र की बढ़ोतरी की गई है।

श्री आर0के0एस0 ----- जारी।

14/03/2017/1610/RKS/AG/1

श्री गोविन्द राम शर्मा....जारी

जो वाटर गार्ड रखे गए हैं उनकी सैलरी में जो बढ़ोतरी की गई है वह बहुत कम है। मुझे ध्यान है कि कांग्रेस सरकार ने वाटर गार्डों की भर्ती 650 रुपये से शुरू की थी और हमारी सरकार ने इन वाटर गार्डों को 1350 रुपये वेतन में भर्ती किया था। लेकिन आज के समयानुसार कर्मचारियों/अधिकारियों व हमारी सैलरी को देखते हुए उनका वेतन केवल मात्र 1700 रुपये किया गया है, जोकि बहुत कम है। मेरा सरकार से निवेदन है कि जो निम्न स्तर के लोग हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जाए और उनकी सैलरी में बढ़ोतरी की जाए। 2-3 साल पूर्व कांग्रेस सरकार ने आशा वर्कर प्रदेश में रखे। उस वक्त सरकार ने यह कहा था कि इन वर्करों को 850 रुपये या एक हजार रुपये सैलरी देंगे। कैबिनेट की मीटिंग भी हुई और उसमें भी सैलरी के बारे में डिसाइड किया गया होगा। लेकिन आज तक उनको पैसा नहीं दिया गया । पहली बार उनको पैसा दिया गया जोकि हजार रुपये कम है। उनका वेतन कम-से-कम दो-अढाई हजार रुपये होना चाहिए। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा

कि इन वर्करों को जिस डेट से रखा गया है उस डेट से इनको एरियर मिले ताकि जो गरीब लोग नौकरी में लगे हैं उनको कुछ-न-कुछ लाभ मिल सके। इसी प्रकार कर्मचारियों के लिए 2 प्रतिशत डी.ए. दिया गया। उसके बाद डी.ए. को 3 प्रतिशत कर दिया गया। जो केन्द्र सरकार ने 2 प्रतिशत डी.ए. दिया है, वह नये पे-स्केल पर दिया है। यदि यह डी.ए. पुराने पे-स्केल पर दिया गया होता तो यह 7 प्रतिशत बनता है। इसलिए मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि इस पर भी विचार किया जाए और जो कर्मचारियों का सही डी.ए. बनता है, उस तरीके से उन्हें डी.ए. दिया जाए।

मुख्य मंत्रीः माननीय सदस्य आप इस बारे में स्पेसिफाई करो कि आप किन कर्मचारियों के बारे में बात कर रहे हैं?

श्री गोविन्द राम शर्माः सभापति महोदय, प्रदेश का कोई भी कर्मचारी जिनके लिए आपने डी.ए. दिया उसकी बात मैं यहां पर कर रहा हूं।

14/03/2017/1610/RKS/AG/2

श्री गोविन्द राम शर्माः जो डी.ए. पहले दिया था उसको आपने बाद में 3 प्रतिशत कर दिया है। लेकिन यह डी.ए. केन्द्र सरकार ने न्यू-पे स्केल में दिया है और यहां पर अभी तक पुराना पे-स्केल है। पुराने पे-स्केल के हिसाब से यह डी.ए. ज्यादा बनता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप अधिकारियों को निर्देश दें कि जो सही डी.ए. बनता है, उस हिसाब से डी.ए. दिया जाए। इसी प्रकार जो रिटायरी कर्मचारियों और दूसरे कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता दिया गया उसमें भी केवल नाम मात्र की बढ़ोतरी की गई। आपने बजट भाषण में कहा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वाशिंग अलाउंस देंगे। पहले 30 रुपये वाशिंग अलाउंस दिया जाता था और आपने इसमें 30 रुपये और बढ़ा दिये। यदि आप ड्रैस ड्राईक्लीन करने के लिए कहीं चले जाओ तो 300 या 400 रुपये से कम पैसे कोई नहीं लेता है। यह भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के साथ एक मज़ाक है। इसमें भी ध्यान देने की आवश्यकता है। आपने विधायक निधि बढ़ाई इसके लिए आपका धन्यवाद। आपने इसको

1.10 करोड़ रुपये किया और हमारा आपसे निवेदन है कि इसमें भी और बढ़ोतरी की जाए। जो अच्छी बात है उसकी प्रशंसा करने में हमें कोई शर्म नहीं है। लेकिन बहुत सी बातें ऐसी हैं जिसमें पक्षपात किया जाता है। बहुत से कर्मचारियों का उत्पीड़न किया गया। जैसे मेरे निर्वाचन क्षेत्र से श्री विनोद ठाकुर जी थे। माननीय मुख्य मंत्री जी मुझे यह भी पता चला कि आपके ऑफिस के नाम से कई फ्रॉड डी.ओ. डायरेक्टरेट पहुंचे और

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

14.03.2017/1615/SLS-AG-1

श्री गोविन्द राम शर्मा...ज़ारी

उन्होंने कोई मुद्दा उठाया होगा जिसके बाद उनके विरोधी लोगों ने आपको मिसगाइड किया होगा या आपके कार्यालय को मिसगाइड किया होगा जिसके कारण उसके एक नहीं बल्कि 3-3, 4-4 ट्रांसफर आर्डर कर दिए गए। ट्रांसफर के बाद उसके ससपैंशन आर्डर भी कर दिए गए। वह भी यहां से नहीं बल्कि दिल्ली से किए गए। यह बातें ठीक नहीं है। ऐसी ही हमारे एक एन.आर. ठाकुर हैं। वह एन.जी.ओज. के जनरल सैक्रेटरी हैं। उसको भी 3-3 बार ट्रांसफर किया गया। पहले शिलाई किया, फिर दूसरे स्थान पर कर दिया और बाद में कोटखाई कर दिया। ऐसे ही हजारों कर्मचारियों को ट्रांसफर किया गया। शायद सारी बातें आप तक नहीं पहुंचती होंगी। बीच में कहीं कोई ऐसा कौकस है जो आपको मिसगाइड करता होगा। उन कर्मचारी नेताओं की आपस में नहीं बनती होगी; कहीं इलैक्शन में उनकी लड़ाई हुई होगी। उसको लेकर आपके पास बड़ी-बड़ी बातें बनाकर कि यह भाजपा का है या फलां पार्टी का है, उनको विक्टेमाइज करने की कोशिश हुई है। मेरा निवेदन है कि आपको इस ओर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि आप प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं।

मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि केंद्र सरकार ने जो एन.एच. दिए, उनकी डी.पी.आर्ज़. तुरंत बनें। 15 एन.एच. ऐसे हैं जो बहुत पहले स्वीकृत हो गए। प्रश्न के आपके उत्तर में था कि 12 एन.एच. की फौरमैलिटीज पूरी कर ली हैं। उनकी जानकारी मिल जाए कि वह 12

एन.एच. कौन से हैं। 42 एन.एच. ऐसे हैं जिनकी डी.पी.आर्ज़. बनाई जा रही हैं। मेरा निवेदन है कि अगर हम डी.पी.आर्ज़. तुरंत बनाएंगे तो उसका लाभ मिलेगा और केंद्र सरकार से पैसा आएगा जैसा कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में आ रहा है। आपको इसमें 1900 करोड़ रुपये से ज्यादा आया है। फिर आापके अधिकारी जो डी.पी.आर्ज़ बना रहे हैं उनके माध्यम से प्रदेश के लिए करोड़ों रुपया और आएगा। अगर केंद्र से आने वाले पैसे से आप जल्दी काम करेंगे तो उसका लाभ प्रदेश सरकार को और प्रदेश की जनता को मिलेगा। इसमें कोई श्रेय लेने की बात नहीं है कि इसका श्रेय नड्डा जी को, धूमल जी को या गडकरी

14.03.2017/1615/SLS-AG-2

जी को या भाजपा को मिल जाएगा। श्रेय किसी को भी मिले, लेकिन जो काम करने का है, जिससे प्रदेश को लाभ मिले, वह काम करना चाहिए।

अरबों रुपये स्वास्थ्य विभाग में केंद्र सरकार ने दिए हैं और माननीय नड्डा जी ने भेजे हैं। लेकिन आज तक वह पैसा नहीं लग रहा है। करोड़ों रुपया आने के बावजूद भी अगर उस पैसे को न लगाएं तो हानि इस प्रदेश की और प्रदेश की जनता की हो रही है। वह पैसा तुरंत लगे। जहां आवश्यकता है वहां लगेगा तो उसका लाभ भी होगा। यह ठीक बात है कि कई ऐसी जगह स्कूल या कॉलेज खोल दिए गए जहां उनकी आवश्यकता नहीं है। इसी तरह स्वास्थ्य विभाग की CHC या PHC खोल दी गईं। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने भी यह बात कही। कई जगह आवश्यकता भी थी। मैंने भी निवेदन किया था। आपने मेरे कहने पर घड़याच और लद्दाघाट में स्कूल खोले हैं जिसके लिए मैं आपका धन्यवाद भी करना चाहता हूं। लेकिन कहीं-कहीं स्कूलों की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए जहां आवश्यकता हो वहां ज़रूर आप ध्यान दें। लेकिन वहां पर शिक्षकों की भी आवश्यकता है। अध्यापक बहुत कम हैं। कई जगह जो हमारे इंटिरियर के स्कूल हैं, वहां पर जहां 10 अध्यापक होने चाहिए वहां

पर 2 ही अध्यापक काम कर रहे हैं। जहां 15 अध्यापक होने चाहिए वहां 5 ही काम कर रहे हैं। वहां अध्यापक हों, इसका जनता को लाभ होगा।

स्वास्थ्य विभाग में मेरे अर्की में यह स्थिति है कि जहां अर्की प्रॉपर में 9 डॉक्टर होते थे आज वहां 2-3 होते हैं। मैंने प्रश्न किया था जिसमें वहां पर 5 पद खाली बताए गए। मुझे लगता है कि वहां 3 ही डॉक्टर्ज़ हैं। ऐसे ही, चाहे वह दिगल की बात हो या लोहारघाट या बलेरा के पास की बात हो या भुमती की बात हो, वहां पर न कोई डॉक्टर है, न पैरा मैडिकल स्टॉफ है। वहां उनकी आवश्यकता है ताकि वहां की जनता को इसका लाभ मिल सके और उन बेचारे लोगों को दूर न जाना पड़े। इसकी भी चिंता करने की आवश्यकता है।

...श्री गर्ग जी

14/03/2017/1620/RG/AS/1
श्री गोविन्द राम शर्मा----जारी

सभापति महोदय, मेरा इनसे एक और निवेदन है कि ग्रामीण क्षेत्र में जंगली जानवरों ने इतना तंग कर दिया है कि लोग गन्दम, मक्की इत्यादि-इत्यादि का जो बीज बोते थे अब लोगों ने वह भी बीजना छोड़ दिया है। क्योंकि जंगली जानवर कुछ रहने ही नहीं देते। इसके लिए कोई-न-कोई योजना बनाई जाए। चाहे मनरेगा के माध्यम से किसी प्रकार का चौकीदार आदि रखा जाए या इसके लिए कुछ और किया जाए। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि इन जंगली जानवरों से बचाव के लिए यदि कोई योजना बनेगी, तो इसका प्रदेश को लाभ होगा और प्रदेश के बेरोजगार नौजवान को भी इससे बहुत लाभ होगा। क्योंकि यदि वे खेतीबाड़ी या सब्जी लगाने का अपना कोई काम करेंगे, तो इसका लाभ भी इस प्रदेश की जनता एवं बेरोजगारों को होगा।

सभापति महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र में 7-8 साल पहले ट्रांसपोर्ट का एक सब-डिपो खोला गया था। मैंने इसके लिए पहले भी अनुरोध किया था, लेकिन अब तो इसे बंद किए हुए सवा चार साल हो गए। वहां जो सब-डिपो का एरिया मैनेजर था वह भी ट्रांसफर कर दिया और वहां जो स्टाफ एवं मशीनरी थी वह सब वहां से ट्रांसफर कर दिया गया। सोलन जिले में अर्की क्षेत्र एक ऐसा है जो सबसे लंबा-चौड़ा क्षेत्र है, आपको इसकी जानकारी है

क्योंकि आप प्रदेश के 6 बार मुख्य मंत्री रह चुके हैं इसलिए आपको पूरे प्रदेश की जानकारी है। 200 किलोमीटर एक कोने से दूसरे कोने तक मेरा चुनाव क्षेत्र है। वहां अधिकतर सड़कें भी हम लोगों ने बना ली हैं। लेकिन वहां के लिए केवल मात्र तीन बसें अभी तक आई हैं। बाकी सारी-की-सारी कहीं और दे दी हैं। इसलिए सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन है क्योंकि यहां पर परिवहन मंत्री जी तो हैं नहीं और माननीय मुख्य मंत्री यहां हैं। तो वहां के लिए बसों की व्यवस्था की जाए और वहां जो बस अड्डा है उसमें बहुत दिक्कत है। वहां जगह काफी है, लेकिन थोड़े से पैसे की आवश्यकता है। अगर उसके लिए पैसे आ जाएं, तो बहुत अच्छा काम वहां होगा। हमने तो यह भी कहा था कि हमें इस बारे में डायरैक्शन दे दें, तो जो भी किसी से लेना होगा, हम उसमें काम करवा देंगे। बाद में जो दुकानें इत्यादि हैं उनको दे दें। इससे सरकार को किराया भी जा जाएगा और आमदनी होगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस तरफ भी आप ध्यान दें।

14/03/2017/1620/RG/AS/2

सभापति महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र अर्की में बरसातों और सर्दियों में पानी की बहुत दिक्कत है और गर्मियों में तो क्या हाल होगा, यह तो ईश्वर ही जाने। अभी तक बहुत सी जगहों पर पेयजल योजनाओं की बहुत दिक्कत है। कई गांव तो ऐसे हैं जहां अभी तक पानी की पाईपें भी नहीं बिछी हैं और उनके लिए कोई स्कीम ही नहीं बनी। जब विभाग से कहते हैं, तो वे कहते हैं कि पैसा नहीं है। छोटा सा पंप खराब हो जाए, तो पैसा नहीं है या कहीं छोटी सी कोई पाईप लगनी हो, तो कहते हैं पैसा नहीं है। वहां ऐसी स्थिति है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जहां-जहां पेयजल की कोई स्कीम नहीं बनी या जो छोटी-छोटी स्कीमें हैं उनके लिए पैसे की व्यवस्था करें ताकि वहां के लोगों को गर्मियों में पानी मिल सके। आज से पांच साल पहले जिन स्कीमों का शिलान्यास किया गया था उनका काम आज तक पांच सालों में कम्पलीट नहीं हो पाया है। उसका क्या कारण रहा कि उनके लिए कभी पैसे ही नहीं आए या कभी कोई परेशानी हो गई या कभी ठेकेदार काम छोड़कर चला गया। इसके लिए भी आप विभाग को आदेश दें कि पेयजल योजनाओं पर काम करें ताकि गर्मियों में जो पानी की दिक्कत है उसको दूर किया जा सके।

सभापति महोदय, मैं ट्रांसपोर्ट नगर के बारे में कहना चाहूंगा कि प्लानिंग की मीटिंग में दो वर्ष पहले भी कहा माननीय मुख्य मंत्री जी ने था। इस बार भी विभाग को इस बारे में

आदेश दिए, इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करना चाहूंगा, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत हुई है। इसलिए मेरा इनसे निवेदन है कि ये विभाग को दुबारा से कहें कि वहां जगह है और जगह ट्रांसफर करके यदि वहां ट्रांसपोर्ट नगर बन जाएगा, तो उसका लाभ सभी को होगा। चाहे लोग कांगड़ा, मण्डी, कुल्लू, ऊना, बिलासपुर आदि से आएं, तो उन सभी को सुविधा होगी। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि वहां हमेशा ही ट्रैफिक जाम रहता है। इसके बनने से इस जाम से भी छुटकारा मिलेगा। ---(व्यवधान)---

सभापति महोदय, पार्किंग की समस्या शायद सभी चुनाव क्षेत्रों में होगी। लेकिन मेरे चुनाव क्षेत्र में पार्किंग की बहुत समस्या है। अर्की, दाड़लाघाट, भुमती, जयनगर, दिग्गल और कुनिहार में पार्किंग की बहुत दिक्कत है और बहुत सारी गाड़ियां सड़कों पर लगी रहती हैं जिससे ट्रैफिक जाम व दुर्घटना का हमेशा खतरा बना रहता है। इसके लिए भी कुछ-न-कुछ आप अवश्य करें ताकि उसका लाभ हम सभी को हो।

एम.एस. द्वारा जारी

14/03/2017/1625/MS/AS/1

श्री गोविन्द राम शर्मा जारी--------

मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि अर्की के अंदर दो सड़कें आज से 6-7 साल पहले एप्रूव हुई थीं और एप्रूव होने के बावजूद भी उन सड़कों पर काम आज तक नहीं हुआ। उसका एक कारण यह है कि उसमें चाहे अधिकारियों की कमी कह लो कि उसमें थोड़ा सा एरिया फॉरैस्ट का था। सड़क नाबार्ड से एप्रूव हो गई लेकिन बाद में फॉरैस्ट का एरिया नहीं हुआ। उसके टैण्डर हो गए और ठेकेदार ने काम भी शुरू कर दिया लेकिन बाद में काम रुक गया। ऐसे ही जो दो सड़कें हमारी दानोघाट से नेरी-प्लाटा और मज्याट से पपलोटा वाया देओरा, इन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो मेरे क्षेत्र में स्कूलों में अध्यापकों की कमी है, अस्पतालों में डॉक्टर्ज और पैरा-मेडिकल स्टाफ की कमी है, उसको भी सरकार तुरन्त पूरी करे। इसके साथ मैं एक निवेदन जरूर करूंगा कि मैंने विधायक प्राथमिकता की बहुत सी सड़कें नाबार्ड के लिए भेजी हैं और कुछ पैंडिंग पड़ी हैं। आज तक इन चार वर्षों में मेरी एक भी सड़क एप्रूव नहीं हुई है। मेरा मुख्य मंत्री जी से

निवेदन है कि जो सड़कें पैंडिंग पड़ी हैं तो अप्रैल में जब और सड़कों की नाबार्ड के तहत एप्रूवल होगी तो इनको भी तुरन्त एप्रूव करवाने का आप प्रयास करें। अन्त में मैं इतना ही कहूंगा कि यह बजट कर्मचारी विरोधी, किसान विरोधी और बागवान विरोधी है इसलिए मैं इसका समर्थन करने में असमर्थ हूं।

14/03/2017/1625/MS/AS/2

श्री सुरेश भारद्वाजः उपाध्यक्ष जी, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है।

सभापति (श्री कुलदीप कुमार): बोलिए।

श्री सुरेश भारद्वाजः सभापति जी, माननीय राजेश धर्माणी जी इस सदन में बोल रहे थे। वे चीफ पार्लियामेंट्री सैक्रेटरी भी हैं हालांकि इन्होंने रिजाईन कर दिया है। इन्होंने एक शब्द बोला है कि पंजाब के चुनावों ने ***। मेरा नम्र निवेदन है कि इस प्रकार के शब्द कार्यवाही से निकाल दिए जाएं क्योंकि प्रधानमंत्री जैसे उच्च पद पर बैठे व्यक्ति के लिए इस प्रकार की बात करना सदन में किसी भी चुने हुए माननीय सदस्य के लिए शोभनीय नहीं है।

सभापतिः ठीक है, एग्जामिन कर लेंगे, देख लेंगे।

श्री सुरेश भारद्वाजः ठीक है, धन्यवाद।

*** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यावाही से निकाला गया ।

14/03/2017/1625/MS/AS/3

सभापति (श्री कुलदीप कुमार): अब चर्चा में श्री इन्द्र दत्त लखनपाल (मुख्य संसदीय सचिव) भाग लेंगे।

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल (मुख्य संसदीय सचिव): सभापति जी, वर्ष 2017-18 के लिए आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट के प्रावधान इस सदन में प्रस्तुत किए हैं, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

प्रस्तावित बजट की सामान्य चर्चा के ऊपर यहां पर जो आज चर्चा हुई उसमें विपक्ष की तरफ से केवल-मात्र विरोध करने के लिए ही चर्चा की गई और आंकड़ों के हेरफेर में उल्टफेर करने की कोशिश करके इन्होंने यह जताने की कोशिश की है कि हमारा जो प्रदेश है इसमें विकास के सारे काम ठप्प पड़ गए हैं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने साढ़े चार घण्टे तक अपना 20वां बजट पढ़ने में जो विश्व रिकॉर्ड बनाया, वह अपने आप में एक मिसाल थी। विपक्ष के नेता जो इस समय सदन में उपस्थित नहीं हैं उन्होंने मुख्य मंत्री महोदय को इसके लिए बधाई दी और यह भी कहा कि इसे लोगों ने सहा। इसे लोगों ने सहा नहीं बल्कि लोगों ने सराहा और एक-एक बात को इन्होंने जिस सलीके से यहां पर रखा, उसको हम सभी ने सुना। मैं तो यह कहना चाहूंगा कि वर्तमान समय का जो बजट है वह राजनीतिक बजट न होकर एक सामाजिक बजट है और समाज के हर वर्ग के लोगों को इस बजट से लाभ हुआ है।

जारी श्री जे0एस0 द्वारा----

14.3.2017/1630/जेके/डीसी/1

मुख्य संसदीय सचिव (इन्द्र दत्त लखनपाल):------**जारी**-----

हालांकि पिछले चार वर्षों में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इस प्रदेश की विकास की गति को बढ़ाने के साथ-साथ समाज से जुड़े हुए हर वर्ग के उत्थान के लिए जो कार्य किया है उसकी मिसाल नहीं है, लेकिन इस वर्ष जो इन्होंने यहां पर बजट प्रस्तुत किया है इससे राजनीतिक तौर पर विपक्ष के लोगों को चिन्ता होना लाज़मी है। बेराजगारी भत्ते के ऊपर पिछले छः महीने से चर्चा पर चर्चा पूरे प्रदेश के अन्दर चली हुई थी उसके ऊपर विराम लगा। यहां पर आदरणीय धूमल जी और बिन्दल जी ने कहा कि पैसा कहां से आएगा और

कितने बेरोजगारों को रोजगार भत्ता मिलेगा? माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि डेढ़ सौ करोड़ रूपए का बजट में प्रावधान किया है। बेरोजगार युवाओं को जिनको भत्ता दिया जाना है उसकी गाईड लाईन बनाई जाएगी। कौन बेरोजगार लोग इसमें पात्र होंगे और क्या गाईड लाईन बनेगी, आने वाले एक महीने के अन्दर जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कहा, सारी तस्वीर आपको स्पष्ट हो जाएगी। यह अपने आप में बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला इस प्रदेश के अन्दर हुआ है। इसी प्रकार से कौशल विकास भत्ता भी सीधे युवाओं के साथ जुड़ा हुआ है, उससे भी युवाओं को लाभ हुआ है। इस बजट में चाहे कृषि के क्षेत्र की बात हो, चाहे बागवानी क्षेत्र की बात हो और चाहे अन्य क्षेत्र की बात हो, युवाओं को खेत की ओर ले जाने की बात इस बजट में देखने को मिलती है। हमारे विपक्ष के लोग इसके बारे में यहां पर बोलना नहीं चाह रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि विधायक क्षेत्रीय विकास निधि माननीय मुख्य मंत्री जी के समय में 1 करोड़ 10 लाख तक पहुंची है क्या उससे विपक्ष के लोगों ने लाभ नहीं लिया? क्या आप लोगों ने अपने-अपने क्षेत्र में उस पैसे से कोई जंज घर नहीं बनाया, शमशान घाट नहीं बनाया और कोई पेयजल की योजना नहीं बनाई? आपको इनका धन्यवाद करना चाहिए। आपको उसका लाभ हुआ है। यह आपको बोलना चाहिए। केवलमात्र बड़े-बड़े

14.3.2017/1630/जेके/डीसी/2

आंकड़ों की गलत पिक्चर यहां पर आप लोगों द्वारा देने के बावजूद यह विकासोन्मुखी बजट है। जहां तक कृषकों की बात की जाती है, यह सही बात है कि जो हमारे किसान लोग थे, आवारा पशुओं की वजह से वे बहुत ही दुविधा में थे और उनको उन आवारा पशुओं को भगाने में बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। रात-दिन जो हमारे बुजुर्ग है, माताएं हैं, बहनें हैं, वे डंडे ले करके उन गायों व बैलों के पीछे दौड़े रहते हैं, आज इससे उनको निजात दिलाने के लिए पिछले वर्ष जो बजट में 60:40 की रेशो से बाड़बन्दी के लिए प्रावधान किया गया था, यह सही बात है कि लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि

वह बहुत मंहगा पड़ रहा था। किसानों की बात सुनते हुए, प्रतिनिधियों की बात सुनते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी ने आज उसको 80:20 की रेशो में लाया है। मैं समझता हूं कि इसका काफी लाभ हमारे किसानों को होगा, उनकी खेती-बाड़ी बंजर होने से बचेगी। इसी के साथ जो हमारे पॉली हाऊस बनते हैं, जो उसमें 2000 वर्ग मीटर एरिया उपदान के लिए कवर किया जाता था आज उसमें 4000 वर्ग मीटर का प्रावधान रखा है। यह सही बात है कि हमारे प्रदेश में जब से वानिकी के क्षेत्र में पॉली हाऊसिज का निर्माण होना शुरू हुआ है, उसमें नौज़वान साथियों ने अपने रोजगार पैदा किए हैं। फूलों की खेती, सब्जियों की खेती और 12 महीने उसमें उन्होंने अपने उत्पाद तैयारन किए हैं। इससे जब 4000 वर्ग मीटर में उन्हें उपदान मिलेगा उसका उन्हें लाभ होगा। इसी प्रकार से बहुत से ऐसे पॉली हाऊसिज थे जो प्राकृतिक कारणों की वजह से या बन्दरों की वजह से टूट-फूट गए थे, जिनकी रिपेयर की जानी चाहिए थी, उनके लिए भी जो हमारे युवा थे, किसान लोग थे उनकी बहुत लम्बे समय से मांग थी कि हमें इसके बारे में कुछ न कुछ सब्सिडी दी जाए। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने हर पांच वर्ष के बाद जो पॉली हाऊसिज क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, उनकी रिपेयर के लिए इसमें प्रावधान किया है। ये सारी की सारी चीजें युवाओं के साथ जुड़ी हुई हैं। पशु-पालन को लेकर 50 प्रतिशत तक उपदान देने की बात की गई है।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी-----

14.03.2017/1635/SS-AG/1

मुख्य संसदीय सचिव (श्री इंद्र दत्त लखनपाल) क्रमागतः

उससे भी हमारे लोगों को लाभ होगा। जो हमारे पढ़े-लिखे नौजवान साथी हैं उनको इसका लाभ होगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कृषकों के लिए एक वरदान साबित हुई है और मैं अपने हमीरपुर के किसानों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्हें पूरे देश के अंदर मृदा स्वास्थ्य कार्ड के ऊपर प्रथम स्थान मिला है। इसी प्रकार से अभी माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बजट में प्रावधान किया है कि पूरे प्रदेश के अंदर सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य

कार्ड आबंटित कर दिये जायेंगे। इसी प्रकार से आज हमारे लोग जैविक खाद की ओर बढ़े हैं। सरकार ने प्रयास किये, अनुदान दिया, बजट में प्रावधान किये तो उससे प्रदेश में लोग जैविक खाद पैदा करने के लिए अग्रसर हुए हैं।

इसी प्रकार से जो हमारे चुने हुए ब्लॉक समिति के सदस्य थे, जिला परिषद् के सदस्य थे, पिछले एक वर्ष से मांग कर रहे थे कि जो 14वें वित्तायोग ने उनकी आर्थिक शक्तियों का हनन किया है उसको एक बार पुनः धरातल पर लाकर उन्हें कुछ-न-कुछ पैसा दिया जाए। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो हमारे पंचायती राज, जिला परिषद् और ब्लॉक समिति के चुने हुए माननीय सदस्य हैं उनके लिए 42 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह अपने आप में खुशी की बात है और सभी को इसके लिए धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि उसमें जहां सत्तापक्ष के लोग हैं वहीं विपक्ष के लोग भी पंचायती राज में हैं। आपको यह बात भी जोर-शोर से करनी चाहिए थी क्योंकि इसके ऊपर विपक्ष के लोगों ने काफी राजनीति करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कुछ नहीं कर रही है। प्रदेश सरकार कुछ नहीं दे रही है। जबकि यह मदद पंचायती राज विभाग को केन्द्र सरकार की तरफ से दी जानी चाहिए थी लेकिन जब तीन-तीन बार माननीय मुख्य मंत्री महोदय और पंचायती राज मंत्री महोदय ने केन्द्र सरकार को पत्र लिखे और उन्होंने वे रिजैक्ट किये तो इस मांग को हमारे माननीय मुख्य मंत्री, वीरभद्र सिंह जी ने माना और आज हमारे माननीयों को पैसा मिला है। इससे मैं समझता हूं कि जहां उन्हें मान-सम्मान मिलेगा वहीं अपना काम करने में प्रोत्साहन मिलेगा। एक मातृ शक्ति बीमा योजना, जिसमें 10 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक की जो लड़कियां और महिलाएं हैं उनको एक लाख रुपया मृत्यु पर मिला करता था, उसके लिए दो लाख रुपये का प्रावधान किया गया। और जो ऐसी महिलाएं या लड़कियां, जिनके पति की मृत्यु हो जाती थी, उनको पूर्ण रूप से अपंग होने पर एक लाख रुपये का प्रावधान किया है। ये समाज से जुड़ी

14.03.2017/1635/SS-AG/2

हुई चीज़ें हैं। आज बुजुर्ग लोगों की सामाजिक पैंशन 1200 रुपये से 1250 रुपये की गई। अपंगों की पैंशन 1500 रुपये से 1550 रुपये की गई। इस प्रकार समाज से जुड़े हुए हर वर्ग

के लोग, जोकि गांव के अंदर रहते हैं, उनको इस बजट में कितना फायदा हुआ है, यह हमारे विपक्ष के लोगों को नज़र नहीं आ रहा। पिछले चार वर्षों से लगातार इसमें बढ़ोत्तरी होती जा रही है।

शहरी विकास के लिए इस बजट में 403 करोड़ का प्रावधान है। हमारा जो शिमला क्षेत्र है यहां पर एक पर्यटक की दृष्टि से आज देखा जाए तो पूरे शिमला शहर का कायाकल्प हुआ है। उसमें एल0ई0डी0 लाइटस लगाई गईं। उसमें चारों तरफ से नई प्रकार की रेलिंग लगाई गईं। सर्कुलर रोड को चौड़ा किया जा रहा है और भी कई प्रकार के कार्य किये जा रहे हैं। चाहे हमारा आई0जी0एम0सी0 हॉस्पिटल है वहां पर एक नया भवन बनकर तैयार हो रहा है, जिसमें पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा भी है तथा उसमें नये ओ0पी0डी0 सैंटर्ज़ भी बनाए जा रहे हैं। यह अपने आपमें एक विकास की गाथा है और जब-जब भी इस प्रदेश में माननीय मुख्य मंत्री, वीरभद्र सिंह जी की सरकार बनी है आई0जी0एम0सी0 के अंदर सुविधाओं की कमी नहीं रही है। आज हर क्षेत्र में यहां पर कहा गया कि कॉलेज खोले जा रहे हैं, टीचर्ज़ नहीं हैं लेकिन स्कूलों की पदोन्नति की जा रही है, मैं एक बात यहां पर कहना चाहूंगा कि आज अगर ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलेज खुले हैं तो सबसे ज्यादा लाभ लड़कियों को हुआ है। दूर-दराज के क्षेत्रों में अभिभावक डरते थे कि उनकी बच्चियां पढ़ने कहां जायेंगी लेकिन आज उनके घरद्वार पर कॉलेज खुले और उनमें भारी भीड़ छात्राओं की देखने को मिल रही है। तो क्या ये सामाजिक काम नहीं हैं, क्या ये विकास के काम नहीं हैं? जहां तक स्टाफ की बात की जाती है अभी हाल ही में 88 एसोशियेट प्रोफेसर कॉलेज काडर के भर्ती किये गये हैं। यह निरन्तर प्रक्रिया चली हुई है। पिछले चार वर्षों के अंदर 40-45 हजार से अधिक कर्मचारियों की भर्तियां की गईं और इस वर्ष इस बजट में 19 हजार नौकरियां और देने की घोषणा माननीय मुख्य मंत्री जी ने की है,

जारी श्रीमती के0एस0

14.03.2017/1640/केएस/एजी/1

मुख्य संसदीय सचिव (श्री इन्द्र दत्त लखनपाल) जारी....

उससे सभी विभागों में, चाहे पम्प ऑप्रेटर हैं या पुलिस विभाग है, चाहे वन विभाग है, हर विभाग में नई भर्तियां होने जा रही हैं और हुई भी है । यही कारण है कि आज प्रदेश के लोग एक बार फिर से इस प्रदेश के अन्दर माननीय मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए लालायित है। आज विद्युत विभाग के माध्यम से जो नवीनीकरण किया जा रहा है, थ्री फेज़ लाईन की जा रही हैं, ट्रांसफार्मर बदले जा रहे हैं। करोड़ों की लागत से ये काम पूरे गांव के अन्दर किए जा रहे हैं।

इसी प्रकार से सड़कों का जहां तक कार्य हैं, धूमल जी कह रहे थे कि विकास के काम ठप्प पड़े हैं। शिमला से हमीरपुर की तरफ जाएं तो सड़कों को चौड़ा करने का कार्य किया जा रहा है। पुलों को चौड़ा किया जा रहा है, नये पुल बनाए जा रहे हैं। हर क्षेत्र में नाबार्ड के माध्यम से कार्य हो रहा है। हमारे अपने ही विधान सभा क्षेत्र में लगभग 12 पुल बनाए जा रहे हैं। 6 सड़कें बनाई जा रही है। तो ये क्या विकास के कार्य नहीं हैं?

आज करोड़ों रुपये की लागत से पानी की पाइपें बिछाई जा रही है। ऐसा नहीं है कि विभाग में पाइपों की कमी है। सप्लाई की वजह से कई बार कमी पड़ जाती है लेकिन यह कहना कि पाइपें नहीं मिल रही है तो मेरे अपने विधान सभा क्षेत्र के अंदर ही करोड़ों रुपया पाइपों के ऊपर खर्च हुआ है और नई लाइनें बिछाई गई है। पूरे प्रदेश के अन्दर हजारों के हिसाब से हैंडपम्प लगाए गए हैं जिससे लोगों को घर-द्वार में पेयजल की सुविधा मिले। निरन्तर प्रक्रिया के माध्यम से समाज से जुड़े हर वर्ग को लाभ दिया गया है। तो यह कहना कि इस बजट में कुछ नहीं है, यह बेमानी बात है।

आज एक हजार बसों के नए रूट का प्रावधान किया गया है। एक हजार बसें और गाड़ियां जब बेरोज़गार युवकों को मिलेंगी तो मैं समझता हूं कि जहां आम जनता को उन बसों का लाभ होगा, उससे रोज़गार के साधन भी सृजित होंगें।

14.03.2017/1640/केएस/एजी/2

नए-नए उद्योग लगाए जा रहे हैं। इस छोटे से प्रदेश के अन्दर आज हर क्षेत्र में इन चार वर्षों में इतना विकास हुआ है कि विपक्ष के लोगों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है सिवाय विरोध के लिए विरोध करने की बात है।

माननीय सभापति महोदय, यह जो बजट है, यह राजनीतिक न होकर एक सामाजिक बजट है और समाज के हर वर्ग से जुड़ा हुआ और उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं ले कर आया है । आने वाला जो समय है, 6 महीने के बाद इस प्रदेश में जब चुनाव होंगें, माननीय मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में एक बार फिर से हमारी सरकार बनेगी और माननीय मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी सातवीं बार इस प्रदेश के मुख्य मंत्री बनेंगें और हमारा प्रदेश नई ऊंचाइयों को छूएगा, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सम्बोधन को समाप्त करता हूं। आपने बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

14.03.2017/1640/केएस/एजी/3

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राजेश धर्माणी): सभापति महोदय, जो माननीय सुरेश भारद्वाज जी ने प्वाइंट उठाया, नरेन्द्र मोदी जी हमारे प्रधान मंत्री हैं, इस नाते हम उनका आदर करते हैं लेकिन जो उन्होंने एक हेट-केम्पेन पूरे इंडिया में हमारे राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर के नेताओं के विरुद्ध चलाई है। (व्यवधान)

सभापति (श्री कुलदीप कुमार): धर्माणी जी, आप अपनी बात जारी रखिए। इधर देखकर बात कीजिए।

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राजेश धर्माणी): प्रजातंत्र में यह कहना कि हम किसी पार्टी को खत्म करके, कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगें । (व्यवधान) इससे निन्दनीय कोई बात नहीं हो सकती। (व्यवधान) आप पूरी बात तो सुन लो।

14.03.2017/1640/केएस/एजी/4

सभापति (श्री कुलदीप कुमार): धर्माणी जी, आप इधर एड्रैस करिए। Dharmaniji, please address to the Chair. (व्यवधान) बैठ जाइए। धर्माणी जी, एक मिनट आप भी बैठिए।

संसदीय कार्य मंत्री: सभापति महोदय, श्री सुरेश भारद्वाज जी ने एक मसला उठाया है और धर्माणी जी उसका ही स्पष्टीकरण दे रहे हैं। मेरा विपक्ष के माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि पहले इनको बोलने दो। अगर आप लोगों को ठीक नहीं लगेगा तो आप बोल लेना।

सभापति (श्री कुलदीप कुमार): सभी को समय दिया जा रहा है। आप सीट पर बैठे-बैठे रनिंग कमैंट मत करिए। Let him speak. Let him make the point.

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राजेश धर्माणी): सभापति महोदय, यह जो प्रजातंत्र विरोधी मानसिकता है, राष्ट्रीय स्तर की कांग्रेस पार्टी जिसका बहुत सुनहरा इतिहास है, जिसने भारतवर्ष को बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, उसको यह कहना कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगें और हमारे नेताओं के खिलाफ जो इन्होंने घृणा का केम्पेन चलाया है, हमारा यह कहना है कि उस मानसिकता के ऊपर यह तमाचा है। फिज़िकल तमाचा ही नहीं होता। (व्यवधान)

सभापति (श्री कुलदीप कुमार): बैठिए, बैठिए।

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राजेश धर्माणी): मानसिकता के विरुद्ध यह तमाचा है। यह कोई व्यक्तिगत तमाचा नहीं है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

14.3.2017/1645/av/ag/1

श्री सुरेश भारद्वाज : सभापति महोदय, बजट पर चर्चा हो रही है। यह हिमाचल प्रदेश की विधान सभा है। यहां पर जो बजट प्रस्तुत किया गया उस बजट पर माननीय सदस्य श्री राजेश धर्माणी जी ने एक शब्द का प्रयोग किया है। मैंने केवलमात्र उस शब्द को कार्यवाही

से बाहर निकालने की बात की है और आपने व्यवस्था दे दी है। उसके बाद राजेश धर्माणी जी प्रधान मंत्री के बारे में नई-नई शब्दावली यूज़ कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इन्होंने जो कहा उसको रिकार्ड से बाहर निकाला जाए। जो इस सदन का विषय नहीं है, इस हाऊस से बाहर ये जो चाहे बोल सकते हैं हम उसका जवाब वहां देंगे। लेकिन यहां पर इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करने का कोई मतलब नहीं है।

सभापति (श्री कुलदीप कुमार) : मैंने रूलिंग दे दी है और इस बारे में इग्जामिन कर लेंगे। अब श्री हंस राज जी चर्चा में भाग लेंगे।

14.3.2017/1645/av/ag/2

श्री हंस राज : माननीय सभापति महोदय, यहां पर जो बजट पेश हुआ है आपने मुझे उस पर बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

यहां पर कई लोगों ने कहा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने 4 घंटे खड़े होकर बजट को पढ़ा है और बड़ा सामाजिक बजट है। मैं इसमें सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आप जिस तरह से घंटे या आधे घंटे का भाषण चार-चार घंटे में पढ़ रहे हैं तो देश में आपकी रफ्तार कैसी होगी इस पर सोचन की जरुरत है। अब क्योंकि जमाना 4-जी में चला हुआ है। आप अभी भी तार और ई-मेल में फसे हुए हैं। मैं किसी पर व्यक्तिगत कमैंट नहीं करना चाहता। लेकिन प्रदेश का एक सजग नागरिक होने के नाते मैं यहां पर दो-चार चीजें ही बोलूंगा क्योंकि ज्यादा बोलने के लिए इस बजट में कुछ नहीं है।

जब बजट भाषण चल रहा था तो सत्ता पक्ष के कई नेताओं ने कहा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने यहां पर एक अद्वितीय स्टेमने का उदाहरण पेश किया है। मैं भी इस चीज को मानता हूं लेकिन आज की डेट में मैं जैसे बार-बार कह रहा हूं कि हमें इस तरफ सोचना पड़ेगा। जब व्यक्ति ज्यादा ही हो जाता है तो उसको स्वयं छोड़ देना चाहिए। आप 6 बार के मुख्य मंत्री हैं और *** हम चाहते हैं कि आपने इस प्रदेश में जो आयाम स्थापित किए हैं (---व्यवधान---) सर, मैं बोल रहा हूं।

सभापति (श्री कुलदीप कुमार) : माननीय सदस्य, आप बजट पर बोलिए। (--व्यवधान---) आपका समय जा रहा है।

*** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया ।

14.3.2017/1645/av/ag/3

श्री हंस राज : सभापति जी, मैं बोल रहा हूं। सीरियस होकर बोल रहा हूं। सभापति जी, आपने मेरे फ्लो को थोड़ा नोन-सीरियस करने की कोशिश की है। युवाओं के लिए कहा गया कि आप बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। आपने मिड-डे मील, निःशुल्क किताबें/फीसें करके प्रदेश के स्कूलों के बच्चों को एक तरह से अपाहिज करने की कोशिश की है वैसे ही आपने 1000 रुपये या 1500 रुपये की बात करके प्रदेश के युवाओं का अपमान किया है। मुख्य मंत्री स्टार्टअप योजना, यहां पर माननीय मुख्य मंत्री ने कई उद्योगों की बात की है। अगर आप लोग नये उद्योग या नई योजनाएं स्थापित करते हैं तो आपको इस तरह से बेरोजगारी भत्ता देने की जरुरत नहीं होती। मेरा तो आरोप है कि हमने पिछले चार सालों में इसका किसी भी बजट में समावेश नहीं किया और आने वाले समय में अब चुनाव होने वाले हैं। आप क्या प्रदेश के युवाओं को जो आज मंगल ग्रह पर बसने की बात कर रहे हैं उनको बेवकूफ समझने की बात करते हैं। आपने बजट में इस तरह की घोषणा करके हमारे बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय किया है।

श्री वर्मा द्वारा जारी

14/03/2017/1650/टी0सी0वी0/ए0एस0/1
श्री हंस राज.... जारी

आपने बजट में इस तरह का जो ओछा समावेश किया है कि हम 10-15 सौ रूपये या हजार रूपया देंगे और उससे ही वे युवा लोग चलेंगे, तो ये एक तरह से ड्रामा है। आप 1000

रूपया भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपके पास पैसे ही नहीं हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं सीधे ही चुराह की तरफ चलूंगा। इन्होंने यहां पर कहा कि इस अवधि में मैंने 14 नये उप-मण्डल, 16 तहसीलें तथा 31 उप-तहसीलें खोलीं हैं। हमारे चुराह में एक तहसील चलती हैं, जो चुराह तहसील हैं, वहां पर पिछले 4 सालों से तहसीलदार नहीं हैं और फिर नई तहसीलें खोलने की क्या जरूरत हैं? आपने यहां पर कहा कि नाहन में मेडिकल महाविद्यालय खोला गया है तथा चम्बा और हमीरपुर में इस तरह के विद्यालय खोलने प्रस्तावित हैं। चम्बा का जो मेडिकल हॉस्पिटल आज चला हुआ है, जिसमें माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी स्वंय गये हुए थे। इन्होंने अपने दौरे के दौरान कहा था कि जो सरकारी डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिसिस कर रहे हैं, उन पर एफ0आई0आरज दर्ज होंगी, लेकिन कोई एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं हुई। माननीय वन मंत्री जी यहां बैठें हैं। ये वहां के किचन और अन्य स्थानों पर घूमते रहते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में क्या हो रहा है? रेडियोलोजिस्ट को तो ये भरमौर ले गये हैं। इसके बारे में हमने कई बार चर्चा की हैं। पिछले कल की ही बात हैं। डूगली नामक पंचायत के चौली में दुर्घटना होती हैं। लड़का स्कूटर से दुर्घटनाग्रस्त होता है। उसको डूगली (चुराह) से चम्बा हॉस्पिटल लाया जाता है, जहां से उसको टांडा रैफर किया जाता है। टांडा में भी उसको कहा जाता है कि उसको ट्रामा सेंटर की जरूरत है और पी0जी0आई0 (चण्डीगढ़) भेजा जाता है। सभापति महोदय, दुर्भाग्य की बात है कि पी0जी0आई0 में भी उसका किसी तरह का इलाज नहीं हो पाया और उसको अब किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में वेंटिलेटर/आई0सी0यू0 में रखा गया हैं। आज स्वास्थ्य सेवाएं पूरे चम्बा जिला की ऐसी हैं, मैं तो माननीय मुख्य मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जी से कोई वास्ता नहीं रखता हूं। मेरा वन मंत्री से निवेदन है कि मेरे लिए तो मुख्य मंत्री आप हैं, मेरे लिए तो पूरी सरकार आप ही हैं, लेकिन चम्बा जिला का चाहे वह वनों के लिहाज़ से हो, चाहे मेडिकल/शिक्षा/सड़क के लिहाज़ से हों, अगर इनका सत्यानाश हुआ है, तो इसके लिए वन मंत्री जी जिम्मेवार हैं। व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए, क्योंकि आपसे लोगों को बड़ी उम्मीदें थीं। जब आप दरडा से गोली की तरफ चलते हैं, तो आप वहां के रोडों के हालात देखिए, इसके लिए लोग हररोज़

14/03/2017/1650/टी0सी0वी0/ए0एस0/2

हम पर छी.छी.- थू.थू. करते हैं। पिछले 4 साल से उस नेशनल हाईवे का बहुत बुरा हाल हैं और आपकी अपनी रोड़ भी बहुत ख़राब हैं, उसको भी बनवा लीजिए। पी0टी0ए0, पैट और एस0एम0सी0 पर जो लोग भर्ती हुए थे, पी0टी0ए0 वाले पिछले 17-18 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पैट वाले 14 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और एस0एम0सी0 पर जो लोग लगे हुए हैं, वे 3-4 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने रोस्टर नहीं लागू किया कोई बात नहीं, लेकिन ये जो तीन तरह के मास्टर हैं, ये उन इलाकों में पढ़ा रहे हैं, जहां पर अन्य रेगुलर टीचर कोई नहीं जाते हैं। जैसे चुराह और सिरमौर विधान सभा का क्षेत्र हैं, इन इलाकों में कोई भी सरकारी कर्मचारी/टीचर नहीं जाना चाहता है, लेकिन उनका अपना भविष्य अधर में लटका हुआ है, वे उस इलाके के बच्चों का भविष्य क्या बनाएंगे? माननीय मुख्य मंत्री जी को इस तरफ सोचना चाहिए और चुनाव आपने वाले हैं, इसलिए एस0एम0सी0 पर जो अध्यापक लगे हैं, उनको एक साल की एक्सटेंशन दी गई है। उनके सर पर आज भी तलवार लटकी हुई है। पी0टी0ए0 और पैट अध्यापकों के सर पर आज भी तलवार लटकी हुई है। माननीय सभापति महोदय, अगर इस तरह का इनवायरनमेंट रहा, तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रदेश का किसी तरह से कोई भला हो सकता है। माननीय वन मंत्री जी और माननीय धूमल जी ने भी कहा कि हमने 91 प्रकार की औषधिय पौधें लगायें हैं, लेकिन जो लैंटाना और मिड-हिमालयन प्रोजैक्ट हैं, उसके नाम पर जो लोग नर्सरियों में 18-20 सालों से काम कर रहे थे, रेस्ट हाऊस का रख-रखाव रखते थे या माननीय वन मंत्री जी सेवाएं करते थे, इन्होंने एम0पी0डब्ल्यू0 भर्ती किए, लेकिन जो 18-18 सालों से वहां पर सेवाएं दे रहे हैं, उनको उसमें शामिल नहीं किया गया। वे बेचारे कब तक इंतजार करते रहेंगे। माननीय मंत्री जी आप लिखकर दे देना।

श्रीमती एन0एस0.... द्वारा जारी।

14/03/2017/1655/ एन0एस0/ए0एस0 /1

श्री हंस राज -----**जारी।**

वन मंत्री : मेरी तरफ से उनके लिए कोई बन्धन नहीं था।

श्री हंस राज : नहीं-नहीं, सर, 29 में से 24 लोग आपके भरमौर क्षेत्र से लगे हुए हैं। सभापति महोदय, आज मुझे यह कहते हुए बहुत खेद होता है। हमारे चुराह क्षेत्र का विकास कब होगा? चुराह अस्पताल एक सिविल अस्पताल है, जहां प्रतिदिन लगभग 150 से 200 की ओ.पी.डी. होती है। उस अस्पताल में 9 पद रिक्त पड़े हुये हैं। लेकिन मुझे इस माननीय सदन में यह कहते हुए खेद हो रहा है कि 9 में से केवल दो पद ही भरे हुये हैं। वहां पर न तो एक्स-रे और न ही सी.टी.स्कैन की सुविधा है। माननीय मुख्य मंत्री जी आपने इस मान्य सदन को गुमराह किया है। आपने इस मान्य सदन में साढ़े चार घंटे लगा करके इतने पन्ने पढ़े हैं, उससे हमें तो कोई उम्मीद नहीं हुई है। आज तक 42 पंचायतों में एक ही कॉलेज़ चलता है। आपने यहां पर बड़े सारे कॉलेज़िज़ की बात की है कि अब 119 कॉलेज हो गए हैं और हमने 42 कॉलेज नये खोल दिए हैं। लेकिन सर, एक ही गवर्नमैंट कॉलेज, तीसा में है जिसमें मैं स्वयं पढ़ा चुका हूं। उस कॉलेज में आज भी 450 से 500 की स्ट्रेन्थ हैं लेकिन मेडिकल, नॉन-मेडिकल और कॉमर्स पढ़ने के लिए बच्चों को चम्बा, धर्मशाला या फिर शिमला जाना पड़ता है। सर, हमारे वहां के लोग आर्थिक रूप से इतने मजबूत नहीं हैं कि वे चुराह क्षेत्र से पढ़ने के लिए चम्बा या धर्मशाला जा सकें। आपने हमारे वहां से साईंस स्ट्रीम जो पहले मिला हुआ था उसको भी उठा कर आप चम्बा ले गए। उसके लिए वहां पर बिल्डिंग तो बड़ी मुश्किल से बन रही है। हमें नेशनल हाईवे मिला हुआ है और मेरा आपसे अनुरोध है कि उसकी डी0पी0आर0 जल्दी-से-जल्दी बनवायें ताकि उस पर काम शुरू हो। आपको इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। हमारे वहां पर दो महत्वपूर्ण सुरंगे हैं। आप हर बार पांगी जाते हैं और वहां के लोगों को भी ठगते हैं। माननीय भरमौरी जी भी ठगते रहे हैं। लेकिन इस बार केंद्र

14/03/2017/1655/ एन0एस0/ए0एस0 /2

सरकार ने हमारी दलीलों को मानते हुए चुवाड़ी-जोत-चम्बा, दूसरी, देवीकोठी- चैड़ीपाल से ले करके हमें पांगी तक सुरंगे दी हैं। इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। मैं यहां पर आपको पूरी रिपोर्ट बता रहा हूं।

सभापति : आप अपना वक्तव्य जारी रखें।

श्री हंस राज : आपने यहां पर प्रदेश में तकनीकी शिक्षा की बात कही है। माननीय बाली जी यहां से चले गये हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। वे कई बार हमारी बात सुन भी लेते हैं। मुझे दुःख इस बात का है कि मैं जब से विधायक बन कर आया हूं और मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी से बहुत आशा है। क्योंकि वे छठी बार मुख्य मंत्री बने हैं। चार-चार घंटें खड़े हो कर भाषण देते हैं। मुझे इनसे बहुत उम्मीद थी कि मेरे क्षेत्र की 42 पंचायतों के 82,000 लोगों को कुछ मिलेगा। चुराह क्षेत्र का दुर्भाग्य देखिए, कुछ नहीं मिला। आपने यहां पर शुरूआत में कहा है कि हिमाचल प्रदेश शिक्षा तथा समावेशी विकास के क्षेत्र में देश का सर्वोत्तम राज्य घोषित किया गया है और देश के बड़े राज्यों में हिमाचल खुले में पहला बाह्य शौच मुक्त राज्य घोषित किया गया है। मेरे हिसाब से समावेशी का अर्थ बनता है पूर्ण रूप से। फिर मुझे यह कहना पड़ेगा कि चुराह क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में नहीं है या फिर जब आपकी सरकार सत्ता में आती है तब आप चुराह क्षेत्र को हिमाचल का अंग समझते ही नहीं है। मैं कभी सीरियस नहीं होता हूं लेकिन आज मैं बहुत सीरियस हूं। वह इसलिए क्योंकि आपने चार घंटे ड्रामा करके, मैं इसको ड्रामा ही कहूंगा और इसके लिए माफी भी चाहूंगा, लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ कि चार घंटे के भाषण को मैं यहां बैठ कर सुनता रहा लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। आज हर विधान सभा क्षेत्र में पी.डब्लयू.डी., आई.पी.एच. और इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड का डिवीज़न है लेकिन हमारे चुराह क्षेत्र में क्यों नहीं है? हमारे 82,000 लोगों को आज तक आई.टी.आई. नहीं मिली है। हमारे साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है? इसलिए मैं बोल रहा हूं कि शायद चुराह विधान सभा क्षेत्र हिमाचल में आता ही नहीं है। अब हमें एक ही

14/03/2017/1655/ एन0एस0/ए0एस0 /3

आशा है नहीं तो हम राजनीति छोड़ देंगे। मैं कहना चाहूंगा कि आज की डेट में अगर कोई विधान सभा क्षेत्र, इसके लिए मेरा सिरमौर के लोग भी साथ देंगे क्योंकि हमारे लिए नई-नई योजनाएं सभी बनाते हैं,

श्री आर0के0एस0----जारी

14/03/2017/1700/RKS/DC/1

श्री हंस राज... जारी

सैंटर से भी पैसा आता है। स्टेट के लोग बड़े भाषण देकर जैसे एन.जी.ओज. के लोग गांव में जाकर बड़ी गंदी सी फोटो लेते हैं और उसी फोटो को आगे भेजते हैं कि भारत में बड़ी गरीबी है। इस तरह का हाल सिरमौर और चंबा जिलों की फोटो लेकर हमारी सरकार दिल्ली में जाकर कर रही है।

सभापति : अभी 3 माननीय सदस्य इस चर्चा में भाग लेने के लिए बाकी हैं।

14/03/2017/1700 /RKS/DC/2

मुख्य मंत्रीः सभापति महोदय, हम यह चाहते हैं कि इस चर्चा में माननीय सदस्य ज्यादा-से-ज्यादा भाग लें। लेकिन कई माननीय सदस्य ऐसे हैं जो न घंटी की परवाह करते हैं, न आपकी परवाह करते हैं, न ही चेयर की परवाह करते हैं और मनमाने तरीके से अंट-शंट बकते जाते हैं। मैं जानता हूं कि जो चुराह विधान सभा क्षेत्र से माननीय सदस्य हैं उनके दिल में दर्द होगा, उनके दिल में तकलीफ होगी और वे कई बातों से नाखुश भी होंगे। जो अच्छे काम हुए हैं उनका माननीय सदस्य जिक्र नहीं करते हैं। यह बात नहीं है। He is speaking just for the sake of speaking. If he abuses me and use unparliamentary language against me, I don't mind it.---(interruption)--- I don't mind it, I expect such things from him. इस आदमी की आदत ही ऐसा बोलने

की है। मैं इसके साथ बहस नहीं करना चाहता हूं। इनको आप निर्धारित समय ही बोलने को दीजिए। ये डरा धमका कर और धमकियां देकर आपसे ज्यादा समय ले लेते हैं। अभी और भी माननीय सदस्य बैठे हैं और मैं समझता हूं कि इतने समय में वे भी कवर हो जाते, उनको भी बोलने का मौका मिल जाता। *** इसकी इजाजत मैं आपको नहीं दे सकता। आप कोई अच्छाई करेंगे, अच्छे शब्द इस्तेमाल करेंगे इसकी उम्मीद मुझे आपसे बिल्कुल नहीं है। कड़वी-से-कड़वी बात भी मीठे शब्दों से कही जा सकती है। मैंने आपको पहले ही नाप लिया था कि आप कितने गहरे पानी में हैं। जहां तक आपके निर्वाचन क्षेत्र का प्रश्न है। am as much concerned about that as you are, even more than you. दूसरी बात यह है कि आपने कभी भी अपने निर्वाचन क्षेत्र की तरक्की के बारे में न मुझे कभी पत्र लिखा है और न ही मुझे मिले हैं। मेरा जो अपना अनुभव है उसके आधार पर हमने ज्यादा-से-ज्यादा विकास करने की कोशिश की है और कोशिश करेंगे। मैं जानता हूं कि चुराह विधान सभा क्षेत्र आज भी भौगोलिक दृष्टि की वजह से पीछे है। हम चाहते हैं कि चुराह विधान सभा क्षेत्र न केवल दूसरे विधान सभा क्षेत्रों के मुकाबले में आए बल्कि उनसे आगे बढ़े। यह हमारी इच्छा है। मगर उसके लिए आपका सुझाव आना चाहिए, आपका मार्गदर्शन आना चाहिए। हम आपको कभी इनकार नहीं करेंगे। विधान सभा में उठकर उटपटांग बोलना, अंगुली उठाना और *** कोई सभ्यता नहीं है। आपको इस चीज की शर्म आनी चाहिए।

*** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

14/03/2017/1700 /RKS/DC/3

सभापतिः माननीय सदन की बैठक 10 मिनट के लिए बढ़ाई जाती है। माननीय सदस्य श्री हंस राज जी आप कृपया वाईंड-अप कीजिए।

श्री एस0एल0एस0 द्वारा जारी..

14.03.2017/1705/SLS-DC-1

सभापति : हंस राज जी, अब आप वाईंड अप कीजिए।...(व्यवधान)... इनको वाईंड अप करने दीजिए। ...(व्यवधान)...

मुख्य मंत्री : सदन अभी और कितनी देर चलेगा? जो माननीय सदस्य आज रह गए हैं वह कल बोल लें।

सभापति : सदन का मत है कि किसी और सदस्य ने अभी नहीं बोलना है।...(व्यवधान)...भारद्वाज जी, और कोई नहीं बोलेगा। इनको वाईंड अप करने दीजिए। He is winding up.

श्री हंस राज : माननीय मुख्य मंत्री जी, आपने चुराह के बारे में सोचा, वक्तव्य भी दिया, यहां पर आश्वासन भी दिया और साथ में बदतमीज़ भी कहा। आपने ये शब्द कहे कि 'शर्म आनी चाहिए'। ...(व्यवधान)...

सभापति : माननीय सदस्य, आप बजट पर बोलिए और अब अपनी चर्चा को वाईंड अप कीजिए। आप अपना समय खराब न कीजिए। वाईंड अप कीजिए।

श्री हंस राज : मैं यहां नहीं बोलूंगा तो कहां बोलूंगा? कमाल करते हैं आप। मुझे अभी बोलने तो दो।

सभापति : आप समय को ऐसे ही बर्बाद न करो। वाईंड अप करिए।

श्री हंस राज : समय को तो आप बर्बाद करवा रहे हैं, सर। मैं यहां पर इतना ही कहना चाहूंगा कि ...(व्यवधान)... माननीय मुख्य मंत्री जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। आपका राजनीतिक अनुभव बहुत ज्यादा है। मैं तो 1983 का जन्मा हूं। मैं आपके सामने क्या बोलूंगा? लेकिन सर, जब मैं इस विधान सभा में शपथ लेकर आया था तो मैं उस इलाके से आया हूं जिस इलाके को मुझसे बहुत उम्मीदें थीं। आपने कहा कि कभी मैंने आपके साथ पत्राचार या बात नहीं की। एम.एल.एज़. प्रायरिटी की मीटिंग्ज तो हर बार होती हैं। उससे बड़ा पत्राचार क्या होगा? हमने

बार-बार एक-एक घंटा आपसे चर्चा की हुई है। उसमें से एक भी चीज़ न हो तो फिर एम.एल.ए. कहां जाएगा? ...(व्यवधान)...

मुख्य मंत्री : एम.एल.एज की प्रायरिटी के बारे में आप जो लिखकर देते हैं, हर एम.एल.ए. की प्रायरिटी को पूरा करने के लिए वह चीजें हमारी प्लॉन में आती हैं और उनके लिए धन का भी प्रावधान किया जाता है। ...(व्यवधान)...

श्री हंस राज : अब मैं सीधा अपने विषय पर आऊंगा। पर्यटन की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश एक अति महत्वपूर्ण प्रदेश है जिसमें चम्बा जिले का भी अपना स्थान है। चम्बा जिले में चुराह विधान सभा क्षेत्र चूंकि पिछड़ा है। कई लोगों ने यहां पर कहा कि...(व्यवधान)...

Chief Minister : Hon'ble Chairman, Sir, you have called another Member then how he is speaking now?

सभापति : आप वाईंड अप करिए। ...(व्यवधान)... ये वाईंड अप कर रहे हैं।

श्री हंस राज : अगर आप सच्चाई नहीं सुनना चाहते तो मैं बैठ ही जाता हूं। ...(व्यवधान)...

मुख्य मंत्री : इन्होंने अपना सारा समय ...(व्यवधान)...

सभापति : अब आप दो मिनट में वाईंड अप करिए।

श्री हंस राजः मैं क्यों दो मिनट में वाईंड अप करूं। हम पिछड़े क्षेत्र से आते हैं। हम लोग दलित हैं क्या इसलिए हम लोगों को बोलने नहीं दिया जाएगा? ...(व्यवधान)...

सभापति : माननीय सदस्य, please sit down.

...(व्यवधान)...आप बैठिए। दो मिनट बैठिए। Please sit down ...(व्यवधान)... प्लीज बैठिए। I am on my legs. Please sit down...(व्यवधान)... माननीय सदस्य, बैठिए।

...(व्यवधान)... हंस राज जी, बैठिए, प्लीज बैठिए। जो माननीय सदस्य के लिए इस माननीय सदन का समय बढ़ाया गया था, आपने वह समय बिल्कुल समाप्त कर दिया है।

14.03.2017/1705/SLS-DC-3

अब इस माननीय सदन की बैठक बुधवार, 15 मार्च, 2017 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला - 171004 **सुन्दर सिंह वर्मा,**
दिनांक : 14 मार्च, 2017 **सचिव।**